दैनिक जागरण

भाव के अभाव में भक्ति का कोई अर्थ नहीं

साइबर ठगी पर सख्ती

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सराहनीय है कि यदि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों की गलती या लापरवाही पाई जाती है तो उन्हें पीड़ित व्यक्ति को भरपाई करनी होगी। यह निराशाजनक है कि बैंक असामान्य लेनदेन को भांप पाने में नाकाम हैं, जबकि उन्हें इसके प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि साइबर धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और यह धोखाधड़ी बैंकों के माध्यम से ही हो रही है। साइबर अपराधी फर्जी पुलिस, कस्टम, सीबीआइ, ईडी अथवा आयकर अधिकारी के रूप में लोगों को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ठगने में लगे हुए हैं। उनके झांसे में आकर कोई व्यक्ति जैसे ही उनकी ओर से बताए गए खाते में धनराशि ट्रांसफर करता है, वैसे ही वह एक के बाद एक दूसरे खातों में स्थानांतरित होती जाती है और अधिकांश मामलों में अपराधियों तक पहुंच पाना कठिन हो जाता है। अनेक मामलों में तो यह सामने आया है कि साइबर छल के जरिये हासिल की गई राशि विदेश पहुंच गई। साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर तो लोगों को ठगने का काम कर ही रहे हैं, उन्हें लालच देकर अथवा बहकाकर भी ठगी कर रहे हैं। इस ठगी में भी बैंक ही माध्यम बनते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि साइबर धोखाधड़ी के कुछ मामलों में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत पाई गई है। ऐसे कुछ कर्मचारियों-अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक विडंबना यह भी है कि बैंक म्यूल खातों को पहचान और निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि साइबर ठगों के लिए ऐसे ही खातों का इस्तेमाल होता है।

इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कुछ मामलों में साइबर अपराधी पकड़ में आ जाते हैं और चंद लोगों को छल-छद्म से हड़पी गई राशि भी वापस हो जाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि साइबर अपराधियों का दुस्साहस और उनका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अधिकांश मामलों में लोगों को उनकी राशि कभी वापस नहीं मिल पाती। साइबर अपराधी किस तरह बेलगाम हो गए हैं और वे किस बड़े पैमाने पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, इसका पता कुछ माह पहले सामने आए इस आंकड़े से लगता है कि अभी तक 54 हजार करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी हो चुकी है। यह राशि कुछ राज्यों के बजट से भी अधिक है। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट साइबर धोखाधड़ी के मामलों के प्रति लगातार कठोर रुख अपना हुए है और गत दिवस उसने रिजर्व बैंक के प्रस्तावित केवाईसी संशोधन निर्देशों की समीक्षा करने की भी बात कही, लेकिन उचित यह होगा कि सरकारी एजेंसियां भी अपनी सक्रियता दिखाएं, क्योंकि अभी तक तो साइबर अपराधी उनसे दो हाथ आगे ही नजर आ रहे हैं। यह स्थिति डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम करने वाली है।

उचित निर्णय

हिमाचल प्रदेश में खराब परीक्षा परिणाम पर 24 शिक्षकों की वेतनवृद्धि रोकने का शिक्षा विभाग का निर्णय आश्वस्त करता है कि नियमों का प्रविधान है तो उनके उल्लंघन पर कार्रवाई भी होती है। ये वे शिक्षक हैं, जिनके विषयों में परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से भी कम रहा है। नोटिस 50 को जारी किए गए थे, लेकिन उनके जवाब आने के बाद निर्णय किया जाना है। पिछले वर्ष खराब परीक्षा परिणाम पर 139 शिक्षकों से कारण पूछे गए थे जबकि वार्षिक वेतनवृद्धि 109 को रोकी गई थी। इसमें संदेह नहीं है कि चिकित्सा और शिक्षा, ये दो ऐसे विभाग हैं जिनका हर घर या कहें व्यक्ति से वास्ता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता सीबीएसई से स्कूलों को जोड़ने की कसरत से भी समझ आती है। जो स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधीन हैं, वहां भी किसी न किसी योजना के अंतर्गत शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के प्रयास हैं। सरकार की सदिच्छा स्पष्ट है, लेकिन यह शिक्षा बोर्ड को भी देखना होगा कि परीक्षा परिणाम की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता न हो। यह परीक्षा के मानदंडों का कड़ाई के साथ पालन करने पर ही संभव है। हाल में शिक्षा विभाग ने दो ऐसे शिक्षकों से कारण पूछे हैं जिन्हें निर्धारित के दौरान सहायक पुस्तकों से पढ़ाते हुए देखा गया था। सरकारी स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों का पूरा अधिकार है कि शिक्षक अपने वेतन और सुविधाओं के अनुरूप विद्यार्थियों पर समय लगाएं, अच्छी पौध तैयार करें।

> खराब परिणाम पर वेतनवृद्धि रोकना सावित करता है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने के पक्ष में नहीं है

प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने का समय



आदित्य सिन्हा

इतिहास साक्षी है कि कोई भी देश गर्गर प्रशासनिक मशीनरी के बूते विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया



अवधेश राजपूत

'विकसित राजस्थान-2047' के लक्ष्य की दिशा में प्रशासनिक रोडमैप को गति देते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव ने बीते दिनों भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी क्यूसीआइ को शासन के छह विभागों के गहन संस्थागत परीक्षण का जिम्मा सौंपा है। इस कवायद का उद्देश्य कार्यप्रणालियों का विस्तृत खाका तैयार करना, विभागीय प्राथमिकताओं के अनुरूप मौजूदा मानव संसाधन की समीक्षा करना, अंतर-विभागीय दोहराव को समाप्त करना और प्रशासनिक पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अरुणाचल प्रदेश भी 2025 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कर चुका है। केरलम ऐसी चार कवायदें पहले ही पूरी कर चुका है। यह रुझान दर्शाता है राज्यों ने अपनी प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबकि केंद्र सरकार ने 2009 के बाद से ऐसी कोई पहल नहीं की है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत' का नारा तो दिया है, लेकिन वह अपने स्तर पर इस दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है?

कई कसौटियों पर प्रशासनिक सुधार आवश्यक ही नहीं, अपितु अपरिहार्य हो गए हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि सरकारी परियोजनाएं भारी लेट-लतीफी की शिकार हैं। केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधिकारिक निगरानी रिपोर्ट दर्शाती है कि 458 परियोजनाओं की स्वीकृत लागत में 5.71 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो गई है। ये परियोजनाएं कई महीनों से लेकर दशकों की देरी तक खिंच चुकी हैं। सुधारों की राह में इस पहलू को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि सरकारें सबसे बड़ी मुकदमेबाज बन गई हैं। वर्ष 2025 के अंत तक अदालतों में लंबित 5.39 करोड़ मुकदमों में केंद्र और राज्य सरकारें ही एक पक्ष हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार का एक विभाग ही दूसरे विभाग के खिलाफ अपील दायर कर रहा है और इस तकरार की कीमत आम नागरिकों के लंबित मामलों को चुकानी पड़ रही है।

सुधारों की राह में तीसरी कसौटी योजनाओं की सुसंगत बनाने की है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का दायरा कागजों पर तर्कसंगत बनाकर 130 से घटाकर 75 मूल श्रेणियों में समेटने का दावा तो किया गया, लेकिन हकीकत यही है कि 2025-26 में इनका बजट 5.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। इनमें से तमाम योजनाएं दशकों से चली आ रही हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता की व्यापक समीक्षा की सुध पहली बार पिछले साल ली गई है। चौथी कसौटी प्रशासनिक अधिकारियों से ही जुड़ी है। जहां सरकारों के सचिवालय तो बाबुओं से भरे हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों का भारी अभाव है। एक जनवरी 2025 तक आइएएस का लगभग हर पांचवां पद और आइएफएस का हर तीसरा पद खाली पड़ा था। इसका असर जिला स्तर और फील्ड पोस्टिंग में स्पष्ट दिखता है।

पांचवीं कसौटी यही है कि मौजूदा व्यवस्था में किसी के भी काम की जवाबदेही या प्रदर्शन को समग्रता में नहीं आंका जाता। 'रिजल्ट्स फ्रेमवर्क डाक्युमेंट्स' की व्यवस्था ने एक समय सचिव स्तर के शीर्ष अधिकारियों को वार्षिक लक्ष्यों के लिए सीधे जवाबदेह बनाया था, जिनकी स्वतंत्र समीक्षा तीसरे पक्ष से कराई जाती थी। अपने दौर में करीब 80 विभागों को दायरे में लेने वाली यह व्यवस्था 2013-14 के बाद ठंडे बस्ते में डाल दी गई और इसका कोई विकल्प तक तैयार नहीं किया गया। स्पष्ट है कि जो व्यवस्था अपने अधिकारियों की कार्यक्षमता का ही हिसाब नहीं रख सकती तो वह उनके काम की कद्र कर उन्हें पुरस्कृत करेगी? ऐसे में ठोस नतीजों की उम्मीद बेमानी ही कही जाएगी। ऐसा नहीं कि इन विसंगतियों को पहले चिह्नित न किया गया हो। वर्ष 2006 से 2009 के बीच द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार के स्तर पर 15 रिपोर्ट और 1,514 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थीं। इनमें से सरकार ने 1,183 को स्वीकार भी कर लिया था। इनके क्रियान्वयन का अंतिम बार हिसाब मई 2012 में दिया गया था। तब यह संख्या 533 दर्ज की गई थी और उसके बाद कभी इनकी गिनती ही नहीं हुई।

यह सही है कि दिसंबर 2023 तक 1,562 अप्रासंगिक हो चुके पुराने कानूनों को निरस्त किया गया। इसी क्रम में जन विश्वास अधिनियम, 2023 के जरिये 183 प्रविधानों को आपराधिक बंदिश से मुक्त किया गया। वर्ष 2017 के बजट से योजनागत और गैर-योजनागत व्यय का भेद समाप्त कर दिया गया। ये तमाम सुधार ऐसे हैं, जिनसे व्यवस्था के भीतरी तंत्र के विशेषाधिकारों पर जरा भी आंच नहीं आई। जबकि जिन सुधारों को दफन कर दिया गया, वे सत्ता प्रतिष्ठान की मानसिकता को पूरी तरह बेनकाब करते हैं। मंत्रालयों के एकीकरण या उन्हें सुगठित बनाने का यही अर्थ है कि नेताओं के विशेषाधिकारों पर चोट होना। सिविल सेवाओं के लिए एक कड़ा कानून भी अधिकारियों के सुरक्षा आवरण और सुविधावादी रवैये पर आघात करता है। असल में जब कुछ समूह अपने निहित स्वार्थों के लिए लामबंद होते हैं, तो सुधार वहीं दम तोड़ देते हैं। इस क्रम में विशेषाधिकार संपन्न वर्ग अपने मनमाने अधिकारों या विवेकाधिकारों की रक्षा में उतर आता है। भारत में सुधारों का क्रियान्वयन उनकी उपयोगिता या योग्यता से नहीं, बल्कि इस बात से निर्धारित हुआ है कि उनकी आंच किसको झेलनी पड़ेगी।

स्पष्ट है कि सुधारों की राह में परियोजनाओं की पूर्णता को लेकर अनुशासन बरतना होगा। सरकारों को मुकदमेबाजी के चलन से बचना होगा। परियोजनाओं की एक मियाद भी तय करनी होगी। प्रशासनिक अधिकारियों के कैडर का संतुलित रूप से पुनर्गठन करना होगा। हर विभाग का समग्रता में उचित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए। यदि हमें विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो अगले दो दशकों तक करीब आठ प्रतिशत की दर से आर्थिक वृद्धि करनी होगी। कोई भी देश जर्जर प्रशासनिक मशीनरी के बूते ऐसा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। विकसित भारत का आह्वान तो दिल्ली से हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत जयपुर से होती दिख रही है। प्रशासनिक सुधारों के मोर्चे पर दिल्ली को अब और देर नहीं करनी चाहिए।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

सही इतिहास लेखन की जरूरी पहल

हाल में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा नौ की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक 'अंडरस्टैंडिंग सोसायटी एंड बियॉड, भाग-2' जारी की। यह इतिहास के पुनर्पाठ और पुनर्लेखन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह दिल्ली-केंद्रित इतिहास से बाहर निकलकर भारत की ऐतिहासिक परंपराओं, उपेक्षित राजवंशों और सांस्कृतिक प्रतिरोध की गाथाओं को स्थान देती है। कथित 'गंगा-जमुनी तहजीब' के नाम पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में दिल्ली सल्तनत के गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों तथा मुगलों को अधिक स्थान मिलता रहा, जबकि अहोम, मेवाड़, मराठा और विजयनगर जैसे साम्राज्यों को क्षेत्रीय इतिहास कहकर सीमित कर दिया गया। जिस अहोम साम्राज्य ने छह शताब्दियों तक स्वतंत्रता बनाए रखी, जिस मेवाड़ ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, जिस मराठा शक्ति ने मुगल साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई और जिस विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में कला, साहित्य और स्थापत्य को समृद्ध किया, उन्हें इतिहास में अपेक्षित स्थान क्यों नहीं मिला? चोल, चालुक्य, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और काकतीय राजवंशों को उपेक्षा क्यों हुई?



इतिहास का उद्देश्य अतीत गढ़ना नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर अतीत को उसके समग्र स्वरूप में समझना है

प्रणय कुमार



इतिहास को सही स्वरूप में सामने रखना जरूरी। फाइल

भारत का इतिहास केवल विदेशी आक्रमणों और पराजयों का वृत्तांत नहीं है। यह हजार वर्षों तक चले संघर्ष, प्रतिरोध, बलिदान और सांस्कृतिक स्वाभिमान की गाथा भी है। जिस इस्लामी आक्रमण की आंधी ने पश्चिम एशिया की प्राचीन सभ्यताओं के राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप को बदल दिया, उसके सामने भारत ने अपनी सभ्यतागत निरंतरता कैसे बनाए रखी? इसके पीछे हमारी सामरिक शक्ति, सामाजिक संरचना, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक प्रतिरोध की कौन-सी धाराएं सक्रिय थीं? इनका उत्तर तलाशना इतिहास लेखन का दायित्व है। नई पुस्तक में महाराणा प्रताप, दिवेर का युद्ध, सरयघाट में ललित बरफुकन के नेतृत्व में मुगलों की पराजय, मराठों के स्वराज और सिख गुरुओं के बलिदान इसी दृष्टि को पुष्ट करते हैं। रानी नायकी देवी, रानी रुद्रमा देवी और रानी अब्बक्का की वीरता का उल्लेख बताता है कि विदेशी आक्रमणों और औपनिवेशिक विस्तार के विरुद्ध हमारी महिलाओं ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया।

हर बार की तरह वामपंथी इतिहासकारों को इस नई पुस्तक में सम्मिलित कथ्यों और तथ्यों से भी आपत्ति है, क्योंकि ये उनके नैरेटिव को चुनौती देते हैं। बिर्डबना देखिए कि इन वामपंथी इतिहासकारों द्वारा जहां एक ओर रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताने, पुराणों को इतिहास न मानने और भारतीय ज्ञान-परंपरा को कालबाह्य सिद्ध करने का पुरजोर प्रयास होता है तो दूसरी ओर अपनी वैचारिक सुविधा के अनुसार साहित्यिक संदर्भों को ऐतिहासिक प्रमाण बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। यही दोहरापन देवी दंतेश्वरी, देवी भवानी और अन्य धार्मिक परंपराओं से जुड़ी तलवारों के उल्लेख पर भी दिखाई देता है। बस्तर के राजा, विजयनगर के कुमार कंपन और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी ऐसी परंपराओं को अंधविश्वास कहकर खारिज करने वाले वामपंथी भूल जाते हैं कि इतिहास केवल युद्धों, संधियों और राजवंशों का विवरण नहीं, बल्कि उन आस्थाओं और प्रतीकों का अध्ययन भी है, जिन्होंने समाज को संघर्ष की प्रेरणा दी। इसे दोहरेपन की पराकाष्ठा ही कहेंगे कि जहां यूरोपीय परंपरा में जान आफ आर्क की धार्मिक प्रेरणा अथवा राजा आर्थर की तलवार एक्सकैलिबर से जुड़ी किंवदंतियों का अध्ययन सांस्कृतिक विरासत के रूप में किया जा सकता है, वहीं भारतीय इतिहास में माँ दुर्गा, काली और भवानी से जुड़ी आस्था का उल्लेख अवैज्ञानिकता बन जाता है।

नई पुस्तक मंदिरों के विध्वंस के साथ उनके पुनर्निर्माण को भी सामने लाती है। राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान से स्पष्ट होता है कि मंदिरों का पुनर्निर्माण केवल स्थापत्य का पुनरुद्धार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता और सामूहिक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा भी था। सूरदास, तुलसीदास, कबीर और मीराबाई जैसे संतों तथा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन ने कठिन परिस्थितियों में सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखा। जब आस्था के केंद्रों पर संकट था, तब भक्ति की धारा ने जनमानस को जोड़े रखा। यह भी प्रतिरोध था, जिसे इतिहास से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह पुस्तक भारतीय शासन-परंपराओं, प्राचीन गणराज्यों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और भारतीय ग्रंथों में निहित विचारों को आधुनिक लोकतंत्र तथा संवैधानिक व्यवस्था से जोड़ती है। 'सत्यमेव जयते' जैसे प्रतीक और संसद के नए भवन में स्थापित सेंगोल का उल्लेख इसी दृष्टि का उदाहरण है। यह पुस्तक इतिहास के एकपक्षीय आख्यान को व्यापक बनाने का प्रयास करती है। वामपंथी इतिहासकारों ने दशकों तक जिन प्रश्नों को हाशिये पर रखा, उन्हें सामने लाना आवश्यक था। एनसीईआरटी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। इतिहास का उद्देश्य किसी एक विचारधारा के अनुकूल अतीत गढ़ना नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर अतीत को उसके समग्र स्वरूप में समझना है।

(लेखक शिक्षाविद एवं सामाजिक संस्था 'शिक्षा-सोपान' के संस्थापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मा का उत्सव

जीवन एक अनवरत यात्रा है। इसमें कभी सफलता और आनंद का प्रकाश फैलता है, तो कभी असफलता और निराशा के बादल घिर आते हैं, पर जीवन की सार्थकता केवल सुखद क्षणों में नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने में है। जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्योदय का महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार दुख हमें सुख का वास्तविक मूल्य पहचानना सिखाता है। उपनिषदों की प्रार्थना-'अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, नश्वरता से मुझे अमरता की ओर ले चलो'-मनुष्य की इसी आंतरिक यात्रा का उद्घोष है।

आध्यात्मिक परिपक्वता तब आरंभ होती है, जब हम सुख-दुख, लाभ-हानि और जय-पराजय को समभाव से स्वीकार करना सीखते हैं। गीता का संदेश है कि समत्व ही योग है। इसका अर्थ परिस्थितियों के सामने निष्क्रिय हो जाना नहीं, बल्कि मन को विचलित किए बिना विवेकपूर्वक कर्म करना है। आशा इसी आंतरिक संतुलन से जन्म लेती है। वह विश्वास का दीपक है, जो कठिन समय में भी मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन की कठिनाइयां भी हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। हर संकट दंड नहीं होता और न हर असफलता अंत। कई बार ये नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम कठिन अनुभवों से निराश होने के बजाय उनसे सीखने का साहस रखें। जब हमारे विचार, वाणी और कर्म एक-दूसरे के अनुरूप होते हैं, तब जीवन में सहजता और संतोष जन्म लेते हैं। आत्मा का उत्सव किसी विशेष अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव नहीं, बल्कि जीवन को जागरूकता के साथ जीने की कला है। जब मन में समभाव, व्यवहार में करुणा और कर्म में सदाचार उतर आता है, तब साधारण जीवन भी असाधारण आनंद से भर उठता है।

ललित गर्ग

सीक्वल के मोह में मौलिकता का संकट

श्याम यादव

जिस फिल्म उद्योग की पहचान नए विषयों, यादगार किरदारों और प्रयोगधर्मी कथानकों से होती थी, वह आज अपनी पुरानी सफलताओं की दोहराने में अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा है। 'धुरंधर 2', 'बार्डर 2' और 'ड्रश्यम: द कन्फ्लूजन' जैसी फिल्मों के बीच सवाल केवल सीक्वल की लोकप्रियता का नहीं, उस रचनात्मक सोच का है, जो नई कहानियां गढ़ने के बजाय परिचित कथानकों पर दांव लगा रही है। सीक्वल के प्रति निर्माताओं का झुकाव व्यावसायिक दृष्टि से समझा जा सकता है। किसी सफल फिल्म के पात्रों और कहानी से दर्शक पहले से परिचित होते हैं। इससे प्रचार में मदद मिलती है और निवेश का जोखिम कम करने की उम्मीद रहती है। समस्या सीक्वल बनाने में नहीं, इसे सफलता का सुरक्षित सूत्र मान लेने में है।

दर्शक परिचित किरदारों को दोबारा देखना चाहते हैं, लेकिन उनसे नई परिस्थितियों, नए संघर्षों और प्रभावशाली कहानी की अपेक्षा भी रखते हैं। जब पटकथा का नवीनता के बजाय पुराने नाम, सितारों और प्रचार पर अधिक भरोसा किया जाता है तो रचनात्मकता प्रभावित होती है। व्यावसायिक सफलता की चाह में नए प्रयोगों से बचना अंततः सिनेमा की कल्पनाशीलता को सीमित कर सकता है। भारतीय समाज की विविधता में अनगिनत कथानक मौजूद हैं। शहरों का बदलता जीवन, ग्रामीण भारत की चुनौतियां, युवाओं की आकांक्षाएं, पारिवारिक संबंध और सामाजिक बदलाव ऐसे विषय हैं, जिन पर प्रभावशाली फिल्में बनाई जा सकती हैं, पर यदि निवेश का बड़ा हिस्सा स्थापित फ्रैंचाइजी तक सीमित रहने लगे तो नए लेखकों और मौलिक पटकथाओं के लिए अवसर सिमट सकते हैं।

> **सिनेमा की पहचान अतीत को दोहराने से नहीं, भविष्य की कल्पना करने से बनती है**

सिनेमा केवल कारोबार नहीं, समाज की संवेदनाओं और सांस्कृतिक अनुभवों की अभिव्यक्ति भी है। उसकी पहचान केवल बाक्स आफिस के आंकड़ों से नहीं, कहानियों की विविधता और दर्शकों पर उनके प्रभाव से भी बनती है। फिल्म उद्योग को समझना होगा कि पुरानी सफलताओं को दोहराना रचनात्मक उपलब्धियों का विकल्प नहीं है। सीक्वल की होड़ में मौलिक पटकथाओं और नए विचारों की उपेक्षा होती रही तो यह हिंदी सिनेमा के लिए गंभीर संकट होगा। दर्शकों को बार-बार परिचित कहानियां परोसने के बजाय अपने समय और समाज से जुड़ी नई कहानियां कहने का साहस दिखाना होगा। सिनेमा की पहचान अतीत को दोहराने से नहीं, भविष्य की कल्पना करने से बनती है। निर्माताओं को पटकथा लेखन में निवेश करना होगा, नए फिल्मकारों को अवसर देना होगा और दर्शकों की रुचियां समझनी होंगी। जोखिम से बचना लाभ दे सकता है, पर उद्योग को पहचान कमजोर कर सकता है।

(लेखक सिनेमा के जानकार हैं)

पर्यावरण के प्रति समझें जिम्मेदारी

डा. दीपक कोहली ने 'प्रदूषण के खिलाफ लड़ने होंगे साझा लड़ाई' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में मानव द्वारा उपजी एक गंभीर समस्या को रेखांकित किया है। आज मनुष्य पैसा कमाने, सुख-सुविधाएं जुटाने और विकास की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने आसपास के पर्यावरण की चिंता ही नहीं रही। हमने तरक्की की धन, बड़ी इमारतों, चमकती सड़कों और आधुनिक सुविधाओं से मापना शुरू कर दिया है, लेकिन यह भूल गए कि इन सबका आनंद लेने के लिए स्वच्छ हवा, निर्मल जल और स्वस्थ वातावरण भी जरूरी है। प्रदूषण का संकट अचानक पैदा नहीं हुआ है। हर साल सर्दियां आते ही वायु प्रदूषण सुर्खियों में छा जाता है। सरकारें बैठकें करती हैं, प्रशासन आदेश जारी करता है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं और नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, लेकिन मौसम बदलते ही यह चिंता भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। सरकार की जिम्मेदारी केवल घोषणाएं करने और आपातकालीन प्रतिबंध लगाने तक सीमित नहीं हो सकती। उसे प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, निर्माण स्थलों पर धूल रोकने, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और किसानों की पराली के व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इस आपदा से निपटने के लिए आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना, कचरा न जलाना, पेड़ों की रक्षा करना, पानी और बिजली की बर्बादी रोकना तथा स्थानीय स्तर पर स्वच्छता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, जीवन का अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें प्रदूषण पर हर साल चिंता जताने की औपचारिकता को छोड़ना होगा और उसे रोकने के लिए पूरे साल मिलकर काम करना होगा, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी विकास टिकेगा और मनुष्य का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

शिवम सिंह, बांदा, उप्र

मेलबाक्स

सेवानिवृत्ति की आयु

भारत की न्याय व्यवस्था में जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के प्रस्ताव पर 14 राज्यों ने सहमति जताई है। जिला न्यायालय भारतीय न्याय व्यवस्था की आधारशिला हैं। जो आम नागरिकों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जमीन-जायदाद के विवाद, पारिवारिक मामले, आपराधिक मुकदमे और अन्य दैनंदिनी मामलों की सुनवाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं अदालतों में होता है। यानी आम नागरिकों का न्यायपालिका से सबसे सीधा संपर्क प्रायः इन्हीं अदालतों के माध्यम से होता है। न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है, जब देश की अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ, न्यायाधीशों की कमी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अदालतों में लंबित मुकदमों का बढ़ता बोझ और न्यायिक पदों का रिक्त रहना आम नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने की राह में बड़ी बाधा है। न्यायाधीशों की मुकदमों से जुड़े तथ्यों तथा कानूनी पहलुओं की गहरी समझ विकसित करनी पड़ती है। इससे न्यायिक अधिकारियों के अनुभव का अधिक समय तक लाभ उठाया जा सकेगा। साथ ही अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण और न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद भी की जा रही है। अनुभवी अधिकारियों के अधिक समय तक सेवा में रहने से न्यायिक प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने में भी सहायता मिल सकती है। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे न्यायिक संस्थानों को अपने मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा।

महेश कुमार, सिद्धमुख (राजस्थान)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, अई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : (0120)-4615800, E-mail: delhi@jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/71721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर चुकी है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। सौर और पवन ऊर्जा इसके सबसे बड़े आधार हैं। भारत में कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है।

आजकल

डार्क वेब से ग्राहकों के भरोसे में सेंधमारी

किसी भी सेवा में उपभोक्ताओं के भरोसे की बड़ी कीमत होती है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के साढ़े तीन हजार से अधिक ग्राहकों की निजी जानकारियां डार्क वेब पर लीक हो गईं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पीआइआइ यानी पर्सनली आईडेंटिफिएबल इन्फोर्मेशन संबंधी विवरण हैं, जिसमें ग्राहकों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, आधार या बैंकिंग लेनदेन से जुड़े सीआइएफ नंबर होते हैं। एसबीआइ के हजारों ग्राहकों की निजी सूचनाओं के डार्क वेब पर आने की घटना ने ग्राहकों के भरोसे को कायम रखने की दिशा में नई चुनौती पैदा की है



डार्क वेब के माध्यम से की जानी वाली आर्थिक धोखाधड़ी को रोकने की बड़ी चुनौती सामने आई है। प्रतीकात्मक

अभिषेक कुमार सिंह
टेली परफॉर्मेंसेज से संबद्ध

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का आधार सिर्फ धन का लेनदेन नहीं, बल्कि भरोसा है। एक आम नागरिक जिंदगी भर की अपनी जमापूंजी बैंक में इसलिए रखता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वहां उसका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन डिजिटल युग में इस भरोसे का अर्थ बदल गया है। अब बैंक केवल धन के संरक्षक नहीं हैं। उनके पास ग्राहकों की पहचान, पारिवारिक स्थिति, आय, निवास, संपर्क और आर्थिक लेनदेन से जुड़ी ऐसी सूचनाएं भी होती हैं, जिनके दुरुपयोग से ग्राहक गंभीर संकट में फंस सकते हैं। ऐसे में, एसबीआइ ने 21 अक्टूबर को जब शेयर बाजारों को यह सूचना दी कि उसके ग्राहकों से संबंधित कुछ डाटा लीक हो गया है, तो सनसनी फैल गई। इससे पहले बैंक को 16 अक्टूबर को अपनी साइबर खतरा निगरानी सेवा, रक्षा साइबर एजेंसी और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी सर्ट-इन से डार्क वेब पर संदिग्ध डाटा उपलब्ध होने की जानकारी मिली थी। शुरुआती जांच में डार्क वेब पर उपलब्ध करीब तीन लाख 75 हजार रिकार्ड्स में से 3897 ग्राहकों की तकरीबन सारी गोपनीय सूचनाएं मौजूद मिलीं।

हालांकि इस मामले की जांच स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को सौंप दी गई है और बैंक के मुताबिक इस लीकेज से सामान्य बैंकिंग सेवाएं, कारोबारी निरंतरता और वित्तीय प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ा है। लेकिन इससे यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि इस बैंक के सभी ग्राहकों की निजी और गोपनीय सूचनाएं पूरी तरह महफूज हैं। इसे समझना होगा कि अगर आज किसी नागरिक का मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, पता और लोन संबंधी विवरण किसी साइबर अपराधी के हाथों में पड़ जाएं, तो यह खतरा अत्यंत वास्तविक है कि उस ग्राहक के बैंक खाते से पूरी रकम गायब की जा सकती है, उसे डिजिटल रूप से बंधक बनाकर उसकी संपत्तियों पर डाका डाला जा सकता है।

पैसे से ज्यादा बड़ी चोरी : परंपरागत बैंक डकैती में किसी अपराधी को बैंक की तिजोरी तोड़कर नकदी- जेवर आदि निकालने का दुस्साहस करना पड़ सकता है। लेकिन आधुनिक साइबर दुनिया में अपराध तिजोरी को छुए बिना ग्राहक की पहचान से जुड़ी जानकारी हासिल करके किया जा सकता है। ये सूचनाएं हथिया लेने पर अपराधी बैंक अधिकारी, लोन डिपार्टमेंट के कर्मचारी या ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर किसी भी ग्राहक को अपने भरोसे में ले सकता है। जब किसी अनजान व्यक्ति को ग्राहक का पूरा नाम, जन्मतिथि, बैंक शाखा और लोन एप्लिकेशन के संदर्भ आदि मालूम हों, तो उसकी बात विश्वसनीय लगने लगती है। ऐसे में अपराधी किसी ग्राहक को यह विश्वास दिला सकता है कि उसके खाते में कोई समस्या है, केवाइसी अधूरा है या लोन की किस्त के विवरण में सुधार की जरूरत है। इसके बाद, साइबर अपराधी फर्जी लिंक, नकली वेबसाइट या फिर धोखाधड़ी वाले पेमेंट संबंधी निवेदनों का सहारा ले सकता है। एआइ की मदद से तैयार आवाज और संदेश से ऐसे छल को ज्यादा विश्वसनीय बना सकता है।

हालांकि अभी एसबीआइ के मामले में यह स्थापित नहीं हुआ है कि लीक हुई जानकारियों का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन इससे पैदा खतरों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। निश्चित ही, डाटा लीक और वित्तीय धोखाधड़ी- दो अलग घटनाएं हैं, लेकिन पहली घटना उससे जुड़ी दुर्घटना का रास्ता तो खोल ही सकती है। इसलिए एक बड़ा नैतिक सवाल पैदा होता है। बैंक अपने ग्राहकों से केवाइसी के नाम पर अनेक सूचनाएं और दस्तावेज मांगते हैं। आम नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने के लिए बार-बार ये सूचनाएं बैंक और सरकारी संस्थाओं को देनी पड़ती हैं। लेकिन जिन संस्थाओं को वे अपनी जानकारी सौंपते हैं, उन संस्थाओं की जवाबदेही कितनी है। आप ग्राहकों से तो सजगता और सतर्कता की उम्मीद करते हैं, पर उन्हीं ग्राहकों की जानकारी की सुरक्षा आप खुद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में, संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ग्राहकों पर डालना कितना उचित है।

डिजिटल संसार के छल-छिद्र : एसबीआइ की घटना का दूसरा पहलू उस डिजिटल संसार से जुड़ा है, जहां ऐसी सूचनाएं डार्क वेब पर उपलब्ध होने की बात सामने आई है। इंटरनेट के बारे में आम धारणा यह है कि जो कुछ गूगल या अन्य सर्च इंजनों पर दिखाई देता है, वही उसका पूरा संसार है। लेकिन हकीकत इससे अलग है। इंटरनेट को उसके तीन स्तरों पर समझना होगा। पहला है- सर्फेस वेब यानी जिसमें सामान्य सर्च इंजनों से खोजी जाने वाली सूचनाएं और वेबसाइटें आती हैं। दूसरा है- डीप वेब, जिसमें बैंक खातों के निजी पेज, ईमेल, डाटाबेस, चिकित्सा रिकार्ड और ऐसी सूचनाएं शामिल हैं, जो सामान्य खोज परिणामों में नहीं दिखाई देती हैं। तीसरा है डार्क वेब, जहां विशेष नेटवर्क और खास साफ्टवेयरों की मदद से ही पहुंचा जा सकता है।

हालांकि इसके नामकरण से लगता है कि यह अपराध की दुनिया से जुड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा सामान्य, उपयोगी और वैध डिजिटल व्यवस्था से संबंधित होता है। दमनकारी व्यवस्थाओं में रहने वाले कई नागरिक गोपनीय तरीके से संवाद के लिए इन तकनीकों का उपयोग करते हैं। कह सकते हैं कि कुछ को छोड़कर डार्क वेब का हरेक इस्तेमाल अवैध नहीं होता है। लेकिन समस्या वहां सामने आती है, जब पहचान छिपाने की सुविधा देने वाला यही डार्क वेब अपराधियों का सुरक्षा कवच बन जाता है। चुराए गए पासवर्ड, व्यक्तिगत दस्तावेज, वित्तीय जानकारी, मादक पदार्थों और हथियारों के अवैध कारोबार से जुड़ी कुछ सेवाओं के कारण डार्क वेब के कुछ मंच कुख्यात हो गए हैं। इसी तरह डार्क वेब के आकार को लेकर भी कुछ प्रचलित दावों में अतिशयोक्ति है।

डिजिटल भुगतान का सिरदर्द : इन चुनौतियों का एक पहलू दुनिया भर में तेज रफ्तार पकड़ती डिजिटल भुगतान की व्यवस्था है। इसी तरह क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कुछ अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए करते हैं, लेकिन यह मानना गलत होगा कि प्रत्येक क्रिप्टो लेनदेन का पता लगाना असंभव है। सर्वजनिक ब्लाकचेन पर दर्ज लेनदेन का विश्लेषण कई जांचों में उपयोगी साबित हुआ है। वैसे अपराधियों की असली पहचान हासिल करने के लिए तकनीकी विश्लेषण, वित्तीय सूचनाओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है। इसलिए डार्क वेब की समस्या को केवल इंटरनेट की रहस्यमय दुनिया के रूप में देखना काफी नहीं होगा।

एसबीआइ से जुड़ी घटना में फिलहाल एआइ की कोई भूमिका नहीं दिखी गई है, परंतु यह अवश्य है कि एआइ तकनीकें साइबर सुरक्षा के लिए दोहरी चुनौती पेश कर रही हैं। समस्या यह है कि जिस तकनीक से बैंकिंग धोखाधड़ियों की पहचान की जा सकती है, उसी तकनीक का इस्तेमाल अपराधी ज्यादा असरदार ढंग से कोई छल करने, स्वचालित तरीके से अपने शिकार खोजने और उन्हें फंसाने के लिए संदेश और वित्तीय संस्थानों के लिए नियमित स्वतंत्र साइबर सुरक्षा परीक्षण तथा डाटा उल्लंघन की पारदर्शी सूचना व्यवस्था। दूसरा, साइबर पुलिस को डिजिटल फोरेंसिक, वित्तीय जांच और अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क की पड़ताल के लिए विशेष प्रशिक्षण। तीसरा, पीड़ितों के लिए समयबद्ध शिकायत निस्तारण और धन वापसी की प्रभावी प्रणाली। डिजिटल शासन की सफलता अपराधियों की गिरफ्तारी की संख्या से ही नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि संकट में फंसे कितने नागरिकों का धन, डाटा और विश्वास सुरक्षित रखा जा सका।

(अभिषेक कुमार सिंह)

साइबर अपराधियों का कड़ा होता शिकंजा

डिजिटल भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल साइबर अपराध रोकना नहीं, बल्कि उसके शिकार नागरिकों को प्रभावी न्याय दिलाना भी है। गृह मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई, 2026 को जारी जानकारी इस समस्या की गंभीरता उजागर करती है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर धोखाधड़ी की 53.87 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें 56 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल बताई गई। इसके मुकाबले दर्ज प्राथमिकी (एफआइआर) की संख्या लगभग 1.81 लाख थी। यह अंतर शिकायतों और औपचारिक आपराधिक जांच के बीच मौजूद बड़ी चुनौती की ओर संकेत करता है। हालांकि सरकारी आंकड़ों का दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय के अनुसार, जून 2026 तक नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली ने 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाने में सहायता की।

यानी समय पर सूचना और बैंकों तथा जांच एजेंसियों के बीच समन्वय से नुकसान रोका जा सकता है। लेकिन रकम की बचाना, खाते में रोकना और पीड़ित को वापस दिलाना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। अब जरूरत तीन स्तरों पर सुधार की है। पहला, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को तेज, पारदर्शी और समन्वित तंत्र बनाना होगा, ताकि संदिग्ध लेनदेन की पहचान होते ही खाते फ्रीज किए जा सकें। दूसरा, पुलिस और साइबर सेल को तकनीकी जांच, डिजिटल साक्ष्य संकलन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सक्षम बनाना होगा। तीसरा, नागरिकों को जागरूक करना होगा। जिस व्यवस्था में नागरिक का पैसा तो सुरक्षित हो, लेकिन निजी सूचनाओं पर कोई डाका डाल ले, तो उसे पूरी तरह से सुरक्षित व्यवस्था नहीं कहा जा सकता, चाहे वह बैंकिंग व्यवस्था हो या आधार से जुड़ी व्यवस्था।

बहरहाल, डिजिटल युग में यदि ग्राहकों के इस विश्वास की रक्षा नहीं हुई कि जिस भरोसे के साथ वे अपनी निजी जानकारी संस्थाओं को सौंपते हैं, वह भरोसा किसी भी कारण से टूट गया, तो देश की तकनीकी प्रगति से सारे दावे अधूरे ही माने जाएंगे। असल में, भारत को अब डिजिटल सुविधा से आगे बढ़कर डिजिटल जवाबदेही का युग शुरू करना होगा। जिस व्यवस्था में नागरिक का पैसा तो सुरक्षित हो, लेकिन निजी सूचनाओं पर कोई डाका डाल ले, तो उसे पूरी तरह से सुरक्षित व्यवस्था नहीं कहा जा सकता, चाहे वह बैंकिंग व्यवस्था हो या आधार से जुड़ी व्यवस्था।

खरी-खरी

केयर का लेयर

विनय कुमार पाठक

अंग्रेजी के कई शब्द बहुत प्यारे होते हैं। कई शब्द क्या अंग्रेजी के सारे शब्द बड़े प्यारे होते हैं। इसीलिए हिंदी के किसी भी कार्यक्रम में अंग्रेजी शब्दों की बहुतायत होती है। सच कहा जाए तो अंग्रेजी के शब्दों में पारस सी क्षमता होती है। किसी हिंदी वाक्य में एक दो अंग्रेजी का शब्द पूरे वाक्य को गरिमामय बना देता है।

केयर उन प्यारे शब्दों में एक शब्द है। व्यवसायियों के लिए यह शब्द और भी प्यारा है। इस शब्द के प्रयोग से वे अपने ग्राहकों को अपने झांसे में बहुत आसानी से फंसा सकते हैं। और जब बात होती है हेयर-केयर और स्किन-केयर की, फिर तो कहना ही क्या। बल्ले-बल्ले हो जाती है व्यवसायियों की। वैसे वे ज्ञाति यह हैं कि उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले होने वाली है।

अब बात जब हेयर की हो, तो सभी को काले घने और लंबे बाल चाहिए। और बात आती है स्किन की तो सभी को गोरी और चमकदार त्वचा ही चाहिए होती है। ऐसे में व्यवसायी केयर शब्द का प्रयोग करते हुए तरह-तरह के उत्पाद बाजार में लाते हैं। जैसे अमुक हेयर केयर क्रीम, फलाना हेयर केयर फ्रूट आयल, ढिमका हेयर केयर कोंबों आदि-आदि। लोग क्रीम, आयल खरीदते हैं और सपनों में खो जाते हैं काले घने और लंबे बालों से आच्छादित अपने सिर के। अब उन्हें कौन बताए कि देश ही नहीं दुनिया के भी सबसे ज्यादा अमीर लोगों को गंजे होते अपने सिर की ज्यों का त्यों स्वीकार करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि जिनके सिर पर बाल नहीं होते वे प्रतिभा में किसी से कम होते हैं। पर हेयर केयर का विज्ञापन उजड़े चमन को भले न ढक सके पर इन तथ्यों को तो ढक ही देता है।

केश से किसी भी मामले में त्वचा पीछे नहीं है। स्किन केयर क्रीम, इंटेंसिव केयर बाडी लोशन, डीप मोइश्चर स्किन केयर बाडी मिल्क आदि नामों से सुसज्जित अनेक उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। विज्ञापन में तो यह भी दिखाया जाता है कि इस तरह की क्रीम का प्रयोग करने से ही सफलता प्रयोगकर्ता के कदम चूमने लगती है।

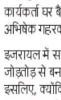
ये व्यवसायी केयर का लेयर बना 'घने बालार्थियों' और 'चमकदार त्वचार्थियों' का खूब दोहन करते हैं।

पोस्ट

अधिकारी प्रशासन चलाते हैं, सरकार नहीं। कमिश्नर, कलेक्टर, कप्तान और कोतवाल सिस्टम संभाल सकते हैं, पर सत्ता नहीं दिला सकते। सरकारें अफसर नहीं, कार्यकर्ता बनाते हैं। यदि जमीन पर मेहनत करने वाला कार्यकर्ता घर बैठा, तो सब धरा रह जाता है।
अभिषेक गहरवार@AdvAbhishekSinh

इजरायल में सरकारें चुने गए सांसदों के जोड़ाहे से बनती हैं, चुनाव से नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि स्पष्ट जनादेश किसी पार्टी या गठबंधन को नहीं मिलता। इस बार भी वही होता दिख रहा है। फिर भी, नेतन्याहू के गठबंधन का आगे रहना उन विरोधियों की हार है, जो जनमत उनके खिलाफ होने के दावे कर रहे थे।
शिवकांत@shivkant

साहस की कोई सीमा नहीं होती और सच्ची वीरता को हर जगह सम्मान मिलता है। यह बेहद गर्व का क्षण है कि भारतीय पायलट कैप्टन स्मिता को संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिष्ठित फर्स्ट वेलास आर्डर आफ जायद सेकेंड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान साहस, कर्तव्य व मानवता के प्रति एक अनुपम भेंट है।
लक्ष्मी एम पुरी@lakshmiunwomen





शशि शेखर
सांपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

खनिज उपकर पर सियासत से आगे बढ़े बात

झारखंड में खनिजों पर सेस लगाने के अधिकार को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर एक्ट) में किए गए संशोधन के विरोध में 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है। यह महज किसी कर या उपकर की वसूली का मामला नहीं है, बल्कि राज्यों के वित्तीय अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण और संघीय व्यवस्था में केंद्र-राज्य संबंधों से भी जुड़ा है।

खनिज संपन्न झारखंड समेत कई राज्यों की आपत्ति है कि नए प्रविधानों से उनके राजस्व के एक बड़े स्रोत पर संकट खड़ा हो सकता है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस मुद्दे को लेकर मुखर है और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई लड़ने और बड़ा आंदोलन करने की घोषणा कर रखी है। इसे खनिजों पर राज्य के अधिकार के सवाल, राज्य की वित्तीय स्वायत्तता और गरिमा के सवाल से भी जोड़ा जा रहा है। हेमंत सरकार लगातार यह तर्क भी दे रही है कि राजस्व का यह हिस्सा छिनने से राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के संचालन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। वहीं, केंद्र सरकार ने खनिजों पर एकीकृत कर की जरूरी बताया है।

खास बात यह है कि झारखंड सरकार इस संशोधन अधिनियम के खिलाफ न सिर्फ विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है, बल्कि पहले से अधिक उपकर वसूलने की भी तैयारी कर चुकी है। इसके अनुसार कैप्टिव खनन पट्टों से उत्पादित खनिजों पर निर्धारित सीमा से अधिक गैर-कैप्टिव उपयोग अथवा वाणिज्यिक प्रेषण किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त उपकर (सेस) लगाने का प्रविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, धातुकर्मीय ग्रेड बाक्साइट पर उपकर की दर को एल्युमिनियम मूल्य के दो प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

केंद्र सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के माध्यम से खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर राज्यों की कर तथा सेस लगाने की शक्तियों को सीमित किया है। राज्य सरकारों की चिंता है कि इससे उन्हें अपने संसाधनों के अनुरूप राजस्व जुटाने की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। राज्य सरकारों और विपक्ष का आरोप है कि केंद्र ने कानून में धारा 9-डी जोड़कर इस फैसले के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की है। राज्य सरकार का कहना है कि यह सबाल केवल राजस्व का नहीं, बल्कि न्यायिक फैसलों की भावना और राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का भी है। हालांकि, संशोधित कानून की वैधानिकता और उसके दायरे पर अंतिम स्थिति संबंधित कानूनी प्रविधानों तथा न्यायिक व्याख्या से ही स्पष्ट होगी। ऐसे में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर गंभीर विमर्श जरूरी है।

झारखंड सरकार का कहना है कि यहां खनन से होने वाली आय के साथ पर्यावरणीय क्षति, विस्थापन और आबादी पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की जिम्मेदारी भी राज्य को उठानी पड़ती है। खनिज निकालने से लाभ उत्पादक क्षेत्र को ही नहीं, बल्कि उद्योगों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी मिलता है। ऐसे में संसाधन संपन्न राज्यों को उनके योगदान के अनुरूप राजस्व और विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता मिलनी चाहिए। यदि खनिजों से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा केंद्र की नीतियों से प्रभावित होता है, तो राज्यों की विकास योजनाओं और स्थानीय जरूरतों के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है।

विधानसभा का विशेष सत्र इस मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख स्पष्ट करने का अवसर होगा, लेकिन केवल विरोध प्रस्ताव पारित करने या राजनीतिक बयानबाजी से इस विवाद का समाधान नहीं निकलेगा। राज्य सरकार को अपने राजस्व संबंधी दावों, संभावित नुकसान और संवैधानिक आधार को ठोस आंकड़ों के साथ सामने रखना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह खनिज संपन्न राज्यों की आशंकाओं को गंभीरता से सुने और कानून के प्रभाव को लेकर पारदर्शिता बनाए। जरूरत पड़ने पर केंद्र और राज्यों के बीच औपचारिक संवाद, राजस्व प्रभाव का संयुक्त आकलन और कानूनी स्थिति पर स्पष्टता की पहल होनी चाहिए।

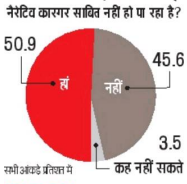
वस्तुतः खनिज संपदा राष्ट्रीय विकास की धुरी है, लेकिन उसके दोहन का बोझ स्थानीय क्षेत्रों को अधिक उठाना पड़ता है। इसलिए लाभ के बंटवारे में उनकी आवश्यकताओं और हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। टकराव के बजाय संवाद और समन्वय का रास्ता ही इस विवाद का स्थायी समाधान दे सकता है।



वैधेनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। (बाएं से दूसरे)। फाइल

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन दर्शाता है कि उसका कोई नैरेटिव कारगर साबित नहीं हो पा रहा है?



सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या हिंसक विरोध-प्रदर्शनों में शामिल होने वालों को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

काशी के संग नागपुर हुआ मामला टेंस,
झटका देता है बड़ा ओवर कान्फिडेंस।
ओवर कान्फिडेंस सबक अब भी ना सीखे,
तो आगे परिणाम मिलेंगे इससे तीखे।
भज मोदी का नाम लीजिए आप उवासी,
तो निश्चित है हार नागपुर हो या काशी!

-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भारत निरंतर अग्रसर है। इस दिशा में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और तमाम चुनौतियों के बावजूद इसे निरंतर विस्तार दिया जा रहा है



श्रीपद येस्सो नाइक
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री

जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते तापमान, बदलते मौसम और ऊर्जा असुरक्षा के दोहरे संकट से जूझ रही है, तब भारत ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक ऐसा रास्ता चुना है, जो आने वाले दशकों में उसकी आर्थिक और रणनीतिक ताकत की बुनियाद बन सकता है। पिछले 12 वर्षों में देश का ऊर्जा परिदृश्य जिस तेजी से बदला है, वह सिर्फ बिजली उत्पादन के आंकड़ों में बढ़ोतरी की कहानी नहीं है। यह आत्मनिर्भरता का एक नया सोपान है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर ऊर्जा परिवर्तन की शुरुआत की है। सौर और पवन ऊर्जा का तेज विस्तार, रूफटाप सोलर, पीएम-कुसुम, पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना, बड़े सोलर पार्क, आफशोर विंड प्रोजेक्ट, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन- ये सभी एक ऐसी व्यापक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका लक्ष्य केवल कार्बन उत्सर्जन घटाना नहीं, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर चुकी है। सौर और पवन ऊर्जा इसके सबसे बड़े आधार हैं और कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। भारत की अंदाजा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल देश में बिजली की मांग में और तेज वृद्धि होना तय है।

हालांकि भारत की ऊर्जा नीति केवल नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर रहने की नीति नहीं है। देश को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली की जरूरत है। यहां आकर थर्मल पावर और परमाणु ऊर्जा का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन भारत की रणनीति पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा को एक-दूसरे के विकल्प के रूप में देखने के बजाय एक संतुलित ऊर्जा मिश्रण तैयार करने की है। कोयला और परमाणु ऊर्जा से स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, दूसरी तरफ सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार तेजी से किया जा रहा है।

यह दृष्टिकोण भारत के ऊर्जा परिवर्तन को व्यावहारिक बनाता है। क्योंकि केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। चुनौती यह भी है कि जब सूरज नहीं निकले या हवा की गति कम हो, तब भी घरों, अस्पतालों, उद्योगों, रेलवे, परिवहन और तेजी से बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली मिलती रहे। इसी वजह से बैटरी एनर्जी स्टोरेज, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन जैसी तकनीकों पर जोर बढ़ रहा है।

सौलर पंप किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के साथ डीजल पर निर्भरता घटाते हैं। वहीं अनुपयोगी या कम उपयोग वाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाने वाले किसान अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय का नया स्रोत तैयार कर सकते हैं। ऊर्जा परिवर्तन किसाना को 'ऊर्जादाता' बनने का भी अवसर दे रहा है। यह बदलाव सिर्फ कुछ तक सीमित नहीं है। शहरों में रूफटाप सोलर ने मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बिजली की लागत कम करने का रास्ता खोला है। पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के जरिए घरों की छतों को छोटे ऊर्जा केंद्रों में बदलने की दिशा में काम हो रहा है।

स्टोरेज और ग्रिड की चुनौती : भारत के सामने बड़ा सबाल केवल यह नहीं है कि कितनी सौर या पवन ऊर्जा पैदा की जा सकती है। असली चुनौती यह है कि इस ऊर्जा को जरूरत के समय कैसे उपलब्ध कराया जाए। सौर ऊर्जा दिन में अधिक पैदा होती है, जबकि बिजली की मांग निरंतर बनी रहती है। पवन ऊर्जा भी मौसम और हवा की गति पर निर्भर करती है। ऐसे में बैटरी स्टोरेज, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, एआइ आधारित ग्रिड प्रबंधन और डिजिटल ऊर्जा प्रणालियां भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था के लिए निर्णायक साबित होंगी। इसी क्षेत्र में भारत के शोध संस्थान, स्टार्टअप, निजी उद्योग और सरकारी एजेंसियां मिलकर स्वदेशी समाधान विकसित करने की कोशिश कर रही हैं। लक्ष्य साफ है- रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़े, लेकिन बिजली ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता से कोई समझौता न हो।

इस पूरी यात्रा को केवल 'ग्रीन एनर्जी' के चश्मे से देखना शायद इसकी सबसे बड़ी तस्वीर को छोटा कर देगा। इसका सामाजिक असर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गांवों में भरोसेमंद बिजली से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रामीण उद्यमों को गति मिलती है। विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियां स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर पैदा कर सकती हैं। वैसे भी आने वाला दशक उन देशों के लिए निर्णायक होगा, जो आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा पैदा कर सकेंगे। भारत ने इस दौड़ में अपनी दिशा तय कर ली है। चुनौती इस गति को बनाए रखने, भंडारण को मजबूत करने, घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने की है।



स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी तमाम बाधाओं से निपटने में सक्षम दिख रहा भारत। फाइल

जीएमआर एयरपोर्ट्स का मुनाफा 86 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल) का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 86 प्रतिशत बढ़कर 65 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 35 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। सितंबर में समाप्त तिमाही में उसकी कुल आय 12 प्रतिशत बढ़कर 4,188 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 3,754 करोड़ रुपये थी। । (प्रेट)

मैं इस समय किसी कंपनी को एआइ के इस्तेमाल के बारे में सिर्फ एक सलाह दे सकता हूं, और वह यह है कि कोडेक्स से उत्पादकता बढ़ाने से भी पहले एआइ से जुड़े सुरक्षा खतरों को समझें और उन्हें कम करने के उपाय करें।
– सैम आल्टमैन, सीईओ, ओपनएआइ



सेंसेक्स	74,151.04 ▲ 905.01	निफ्टी	22,936.75 ▲ 237.90	सोना	₹1,46,000 प्रति दस ग्राम	चांदी	₹1,98,500 प्रति किलो ग्राम ▲ ₹500	डालर	₹95.26 ▼ ₹0.02	क्रूड	$113.96 प्रति बैरल

एक नजर में

एशियन पेंट्स का लाभ बढ़कर 1,068 करोड़ पर

नई दिल्ली: एशियन पेंट्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 7.5 प्रतिशत बढ़कर 1,067.6 करोड़ रुपये रहा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिक्री में हुई वृद्धि से कंपनी का लाभ बढ़ा है। हालांकि, कच्चे माल की बढ़ती लागत ने परिचालन मार्जिन पर दबाव डाला। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसकी एकीकृत शुद्ध बिक्री 16.9 प्रतिशत बढ़कर 9,953.9 करोड़ रुपये हो गई। । (प्रेट)

अंबुजा सीमेंट्स का शुद्ध लाभ 90 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली: अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 90 प्रतिशत घटकर 236 करोड़ रुपये रह गया। ईंधन और लाजिस्टिक लागत बढ़ने तथा मानसून के कारण मांग प्रभावित होने से अंबानी समूह की इस कंपनी के परिचालन मार्जिन पर दबाव पड़ा। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 2,336 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। कंपनी की परिचालन आय 0.2% बढ़कर 9,197 करोड़ रुपये रही। । (प्रेट)

मारुति का इंडी निर्यात 50,000 इकाई के पार

नई दिल्ली: मारुति सुजुकी का अगस्त, 2025 से अक्टूबर, 2026 के दौरान डलेविट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्यात का आंकड़ा 50,000 इकाई को पार कर गया है। कंपनी ने अगस्त, 2025 में ही वैश्विक बाजारों में ईवी की आपूर्ति शुरू की थी। अप्रैल-सितंबर के दौरान भारत से हुए ईवी वाहनों के कुल निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 93% रही। कंपनी ईवी एसयूवी 'ई-विटारा' का निर्यात ब्रिटेन, नार्वे, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड सहित करीब 50 देशों में कर रही है। । (प्रेट)

बाजार में फिर से आए वाइजेग टीएमटी रीबार्स

विशाखापत्तनम: विशाखापत्तनम स्थित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआइएनएल) प्लांट से टीएमटी बार्स का उत्पादन एक बार फिर से शुरू हो गया है। वाइजैग टीएमटी ब्रांड नाम के तहत बनाए जाने वाले ये रीबार्स बाजार में पहले से काफी जाने-माने हैं और निर्माण क्षेत्र में इनकी सबसे ज्यादा मांग रहती है। अलग-अलग आकार में टीएमटी रीबार्स के उत्पाद्य होने से घर बनाने, बुनियादी ढांचे और अन्य निर्माण परियोजनाओं से जुड़े ग्राहकों का भरोसा और मजबूत होगा। । (वि)

मनीग्राम और मुथूट फारेक्स के बीच हुई साझेदारी

नई दिल्ली: मुथूट ग्रुप ने पेमेंट नेटवर्क के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मनीग्राम और मुथूट फारेक्स लिमिटेड के बीच साझेदारी का एलान किया है। यह रणनीतिक साझेदारी पूरे भारत में ग्राहकों को तेज, सुविधाजनक और भरोसेमद अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करेगी। अब ग्राहक विदेशों से भेजे गए पैसे (रेमिटेंस) को पूरे देश में स्थित मुथूट फारेक्स और मुथूट फाइनेंस की शाखाओं से प्राप्त कर सकेंगे या मनीग्राम के डिजिटल चैनलों के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में जमा करा सकता है। । (वि)

बैंकिंग में खरीदारी से सेंसेक्स 905 अंक चढ़ा

मुंबई, प्रेट: कच्चे तेल के दाम में नरमी के बीच बैंक और वैश्विक उपयोग का उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) के शेयरों में भारी लिवाली से घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी आई। मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 905.01 अंक यानी 1.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,151.04 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 237.90 अंक यानी 1.05 प्रतिशत के लाभ बढ़त के साथ 22,936.75 अंक पर रहा।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से अदाणी पोर्ट्स में सबसे ज्यादा पांच प्रतिशत की तेजी आई। कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 18 प्रतिशत बढ़कर 3,682.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जिससे कंपनी का शेयर लाभ में रहा। कोटक महिंद्रा बैंक में 3.86 प्रतिशत, पावर ग्रिड में 3.70 प्रतिशत, 3.46 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस में 2.56 प्रतिशत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.43 प्रतिशत और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2.43 प्रतिशत की तेजी आई। टाइटन, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और इन्फोसिस भी बढ़त के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, ट्रेंट, मारुति सुजुकी इंडिया, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वैश्विक स्तर पर तेल के बेंचमार्क माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.18 प्रतिशत गिरकर 113.96 डालर प्रति बैरल पर आ गई।



74,151.04 पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक

237.90 अंक के लाभ के साथ 22,937 पर पहुंचा निफ्टी

जियो प्लेटफार्म्स का शेयर लगातार दूसरे दिन चढ़ा

जियो प्लेटफार्म्स के शेयर में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन तेजी जारी रही। बीएसई में कंपनी का शेयर 0.40 प्रतिशत चढ़कर 1,423.05 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। एक समय यह 5.12% बढ़कर 1,490 रुपये तक पहुंच गया था। बाजार पूंजीकरण 13,10,491 करोड़ रुपये हो गया।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने, कच्चे तेल की कीमतें में मामूली नरमी और संस्थागत निवेशकों की लिवाली से घरेलू शेयर बाजार में तेजी आई। कुछ कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों और घरेलू मांग बने रहने से बाजार की बुनियादी स्थिति को समर्थन मिल रहा है। हालांकि, लागत ऊंची रहने से कंपनियों के लाभ मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। **-विनोद नायर,** रिसर्च हेड, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

पीएचडी चैंबर ने एलटीसीजी खत्म करने का दिया सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट: उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआइ) ने आयकर विभाग को पत्र लिखकर घरेलू शेयर बाजार में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) खत्म करने तथा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (एसटीसीजी) और प्रतिभूति लेनदेन कर की दरों को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया है। किसी निवेश को दीर्घकालिक मानने के लिए उसकी न्यूनतम अवधि 12 महीने से बढ़ा 18-24 महीने की जा सकती है।

संगठन ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंपी अपनी सिफारिश में कहा कि शेयरों में निवेश पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) और पूंजीगत लाभ कर लगाए जाने से 'देहरा कराधान' होता है। कर दरों को तर्कसंगत बनाने से इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। पीएचडीसीसीआइ ने एसटीसीजी पर कर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने या एसटीटी की दरें कम करने का सुझाव दिया। वर्तमान में, सूचीबद्ध शेयरों और शेयर आधारित म्यूचुअल फंड से होने वाले 1.25 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर के साथ अधिभार और उपकर लगाया जाता है। दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति माने जाने के लिए उसे निवेश को खरीद की तारीख से 12 महीने से अधिक समय तक रखना जरूरी है।



उद्योग संगठन ने एसटीसीजी और प्रतिभूति लेनदेन कर की दरों को तर्कसंगत बनाने का भी सरकार से किया अनुरोध

कंपनियों में ग्रीन स्किल वाले कर्मचारियों की मांग बढ़ी

17% मिलेनियल्स को ग्रीन जाब खोजने में हो रही दिक्कत

18% हुई ऐसे कर्मचारियों की हिस्सेदारी यूटिलिटी सेक्टर में



कंपनियों में ऊर्जा बचाने, अपशिष्ट कम करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने में मदद करने वाले कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है। पेशेवर नेटवर्किंग मंच लिंक्डइन की 'वैश्विक हरित कौशल रिपोर्ट 2026' के मुताबिक भारत में ग्रीन स्किल वाले कर्मचारियों की भर्ती 31 प्रतिशत बढ़ गई है वहीं कुल कार्यबल में इस तरह के कर्मचारियों की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत बढ़ी है। इस तरह हरित कौशल वाले कर्मचारियों की मांग और उनकी उपलब्धता दोनों बढ़ रही है।

लागत घटाने में भी हो रहा ऐसे कर्मचारियों का इस्तेमाल



रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ग्रीन स्किल वाले कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की ऐसे पदों पर भर्ती हो रही है, जिनके पदनाम पारंपरिक रूप से पर्यावरण से नहीं जुड़े हैं। कंपनियां लागत घटाने, दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण पर अपना प्रभाव कम करने में मदद करने वाले कर्मचारियों की तलाश कर रही हैं।

युवाओं के लिए अवसर तलाशना चुनौतीपूर्ण



युवा कर्मचारी ग्रीन स्किल में विशेष रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन उनके लिए ऐसे अवसर तलाशना चुनौती बना हुआ है। सर्वे में शामिल जेन-जी पीढ़ी के आधे से अधिक कर्मचारी ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जो जलवायु परिवर्तन से निपटने या ऊर्जा बदलाव में योगदान दे। हालांकि, 35 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें हरित क्षेत्र में नौकरी ढूंढने में दिक्कत होती है।

12% है तेल-गैस क्षेत्र में ऐसे कर्मचारियों की संख्या

ग्रीन स्किल वाले कर्मचारियों की भर्ती में उपयोगिता क्षेत्र (यूटिलिटी सेक्टर) सबसे आगे है। इस क्षेत्र में कुल भर्तियों में ऐसे कर्मचारियों की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत थी। इसके बाद तेल, गैस एवं खनन क्षेत्र में 12 प्रतिशत और निर्माण क्षेत्र में 11 प्रतिशत भर्तियां हरित कौशल वाले कर्मचारियों की हुईं।

ऊर्जा क्षेत्र के कार्यबल में भी आ रहा है बदलाव

वर्ष 2021 के बाद से भारत में लिंक्डइन के उन सदस्यों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत बढ़ी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं, तेल एवं गैस क्षेत्र में काम करने वाले सदस्यों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत घटी है।

देश में ग्रीन करियर की शुरुआत का पर्यावरण से जुड़े पद के रूप में होना ही जरूरी नहीं है। नियोक्ता ऐसे लोगों को चाहते हैं जो परिचालन को अधिक सुरक्षित, कम खर्चीला और दक्ष बना सकें।
-सुरीन मेल्ह्, एवआर हेड (भारत) लिंक्डइन

इनपुट-प्रेट जागरण इन्फो

अलनीनो के असर से बढ़ सकती है महंगाई

वित्त मंत्रालय ने कहा-चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मूल्य स्थिरता पर फोकस करें नीति निर्धारक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय का कहना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और अल-नीनो असर के कारण महंगाई बढ़ सकती है। वर्तमान हालात में वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ रही है और घरेलू स्तर पर भी नीति निर्धारकों को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में मूल्य स्थिरता पर फोकस करने की जरूरत है। इस सबके बावजूद भारत की घरेलू मांग मजबूत दिख रही है और औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात का प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है। भारत की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है और निवेश की गति भी कायम है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत थी। विश्व बैंक से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) जैसी सभी वैश्विक एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाते हुए सात प्रतिशत या उससे अधिक कर दिया है।

- क्रूड के बढ़ते दाम और खरीफ फसल को लेकर अनिश्चितता से विकास दर को कायम रखना चुनौती भरा
- **7.35** प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान लगाया है दूसरी तिमाही में वित्त मंत्रालय ने



गुरुवार को जारी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम और खरीफ फसल को लेकर अनिश्चितता के बीच आर्थिक गतिविधियों की गति को कायम रखना चुनौती भरा है और नीति निर्धारकों को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई है और खाद्य महंगाई दर सात प्रतिशत को पार कर गई है।

दुनिया के अन्य सेंट्रल बैंकों की तरह आरबीआइ ने भी महंगाई पर काबू के लिए रेपो रेट में 25 आधार अंक की वृद्धि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका से लेकर यूरोप और चीन जैसे सभी देश महंगाई की मार झेल रहे हैं। अमेरिका की महंगाई दर इस साल जनवरी में 2.4 प्रतिशत थी जो सितंबर में बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गई। यूरोप में महंगाई दर पिछले छह माह में 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गई है।

खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर ज्यादा चिंता का विषय

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि इससे मांग प्रभावित होती है। खाद्य वस्तु में प्याज, चीनी और खाद्य तेल के दाम अधिक चल रहे हैं। त्योहारी सीजन में चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। खाद्य तेल के दाम को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से आयातित खाद्य तेल के सीमा शुल्क में कटौती की गई है और उसका असर अगले माह से दिख सकता है। विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर के अनुमान में भी 0.1 प्रतिशत का इजाफा किया है। वर्ष 2026 के लिए वैश्विक विकास दर 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। विकसित देशों की विकास दर के अनुमान में 0.4 प्रतिशत का इजाफा किया गया है जबकि भारत की विकास दर अनुमान में 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

अमेरिका के साथ ट्रेड डील भारत के सभी हितों की रक्षा करेगी : गोयल

नई दिल्ली, प्रेट: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार समझौता देश के सभी संवेदनशील हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि समझौते का ब्योरा सार्वजनिक होने पर देश के लोग इसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि समझौते की आलोचना कर रहे विपक्षी दलों को इस विषय की समझ और जानकारी नहीं है।

गोयल ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, 'कुछ लोग अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह समझ और जानकारी का अभाव है। समझौते का पूरा ब्योरा अभी सामने नहीं आया है। मुझे नहीं पता कि वे (विपक्षी दल) किस बात की आलोचना कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और मैं पूरे दृढ़ संकल्प के साथ यह कह सकता हूं कि जब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का ब्योरा सामने आएगा, तो देश के लोग इसका स्वागत करेंगे। हमारे व्यापार या किसी भी पक्ष के किसी संवेदनशील हित से समझौता नहीं किया गया है। इसके उलट, भारत को तुलनात्मक लाभ की मजबूत स्थिति मिलेगी और व्यापार तुलनात्मक लाभ पर ही आधारित होता है।' भारत और अमेरिका ने इस साल फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। हालांकि, अमेरिका में शुल्क व्यवस्था में बदलाव के कारण इस समझौते पर आगे बातचीत की जा रही है। भारत, अमेरिका के बाजार में अपने सामान पर बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क चाहता है। गोयल ने यह भी कहा कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से बाहर हो गया था, क्योंकि इससे विनिर्माण क्षेत्र पर असर पड़ सकता था।


पीयूष गोयल ●

- वाणिज्य मंत्री बोले-समझौते का ब्योरा सार्वजनिक होने पर देश के लोग इसका स्वागत करेंगे
- ट्रेड डील की आलोचना कर रहे विपक्षी दलों को इस विषय की समझ और जानकारी नहीं

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या क्लिक करें jagran.com

नोएल टाटा की जगह बहराम वकील होंगे ट्रेंट के नए चेयरमैन

नई दिल्ली, प्रेट: टाटा समूह की खुदरा कारोबार कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन नोएल एन टाटा 11 नवंबर को पद से सेवानिवृत्त होंगे। उनके स्थान पर कंपनी ने बहराम वकील को 12 नवंबर से नया चेयरमैन नियुक्त किया है। नोएल टाटा 12 नवंबर से मानद चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। कंपनी ने उनके योगदान को देखते हुए यह निर्णय लिया है। वह 1997 से ही ट्रेंट से जुड़े रहे हैं। निदेशक मंडल ने राजीव दुबे को 30 अक्टूबर से अतिरिक्त गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है। ट्रेंट कंपनी वेस्टसाइड और जुडियो जैसे ब्रांड के जरिये फैशन खुदरा कारोबार में सक्रिय है। इसके अलावा कंपनी स्टार नाम से खाद्य एवं किराना कारोबार भी चलाती है। कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 468 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान उसका राजस्व 22 प्रतिशत बढ़कर 5,873 करोड़ रुपये हो गया।

इंडिगो का सितंबर तिमाही में घाटा 1,879.1 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में घाटा कम होकर 1,879.1 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, खर्च बढ़ने से कंपनी की आय पर असर पड़ा। वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में एयरलाइन कंपनी को 2,582.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की कुल आय बढ़कर 24,311.9 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 19,599.5 करोड़ रुपये थी। हालांकि, जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 26,188.4 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान विमान ईंधन पर खर्च बढ़कर 9,996.8 करोड़ रुपये रहा। इंडिगो के सीईओ बिली वाल्टर्स ने कहा कि भारत में एविएशन के क्षेत्र में लंबे समय के लिए बेहतरीन मौके हैं।

घरेलू विमानन उद्योग को 38,000 करोड़ रुपये तक के घाटे का अनुमान

मुंबई, प्रेट: भारतीय विमानन उद्योग को चालू वित्त वर्ष (2026-27) में 36,000 से 38,000 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा होने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि यात्री यातायात की वृद्धि दर में नरमी, विमान ईंधन (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों और डालर के मुकाबले रुपये में तेज गिरावट के कारण विदेशी मुद्रा संबंधी नुकसान विमानन उद्योग के घाटे के प्रमुख कारण हैं। इक्रा के मुताबिक, फरवरी, 2026 के अंत में पंजीय एकाधिकार में हवाई यात्री यातायात की वृद्धि प्रभावित होने की आशंका है।



इंडियन होटल्स और अदाणी समूह में आठ होटल के लिए करार

नई दिल्ली, प्रेट: टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड और अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने आठ होटल के लिए करार किया है। इसके तहत मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी में 2,000 कमरों के आठ होटल का संचालन किया जाएगा। ये होटल विभिन्न हवाई अड्डों के पास स्थित होंगे।

शहरों के लिहाज से मुंबई में हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर एक ताज होटल निर्माणाधीन है। अहमदाबाद में ताज और विवांता होटल का निर्माण काफी आगे बढ़ गया है। लखनऊ में विवांता और जिंजर होटल विकसित किए जाएंगे, जबकि गुवाहाटी में ताज, गेटवे और जिंजर ब्रांड के होटल होंगे। इन होटल का विकास अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स करेगी, जबकि इनके संचालन की जिम्मेदारी आइएचसीएल संभालेगी। अदाणी एयरपोर्ट ने छह हवाई अड्डों पर 655 एकड़ से अधिक भूमि विकसित करने को अदाणी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड का गठन किया है।

राष्ट्रीय फलक

सितंबर तिमाही में सैमसंग को 80 अरब डालर का रिकार्ड मुनाफा

सियोल, एपी : सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स का जुलाई-सितंबर तिमाही परिचालन लाभ रिकार्ड 107.4 ट्रिलियन वान (80.5 अरब डालर) तक पहुंच गया। इसकी मुख्य वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) में इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर मेमोरी चिप्स की भारी मांग रही। इस दौरान कंपनी का राजस्व भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 195.3 ट्रिलियन वान (146 अरब डालर) पर पहुंच गया। यह लगातार चौथी तिमाही है जब कंपनी ने लाभ और राजस्व के मामले में रिकार्ड बनाया है। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी घरेलू प्रतिद्वंद्वी कंपनी एसके हिंक्स द्वारा तीसरी तिमाही में रिकार्ड लाभ के प्लान के एक दिन बाद दी है। दक्षिण कोरिया की इन दोनों दिग्गज कंपनियों का वैश्विक मेमोरी बाजार के लगभग दो-तिहाई हिस्से पर नियंत्रण है।

माइक्रोसाफ्ट का राजस्व 19% बढ़कर 92 अरब डालर हुआ

वाशिंगटन, एपनआइ: जुलाई-सितंबर तिमाही में माइक्रोसाफ्ट का राजस्व सालाना आधार पर 19% बढ़कर 92.30 अरब डालर हो गया। इस वृद्धि में कंपनी के क्लाउड बिजनेस का बड़ा योगदान रहा। पिछले साल की समान अवधि में राजस्व 77.70 अरब डालर रहा था। कंपनी के सीईओ सत्य नडेला ने एक पोस्ट में कंपनी के क्लाउड कारोबार के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 'माइक्रोसाफ्ट क्लाउड का राजस्व 63 अरब डालर के पार पहुंच गया है, जिसमें सालाना आधार पर 30 प्रतिशत की तेजी आई है।'

एआइएफ, एफपीआइ के अंतिम लाभार्थियों का ब्योरा उजागर करने का निर्देश देने से शीर्ष कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआइएफ), फारेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआइ) और भारत में उनकी इंटरमीडियरीज के अंतिम लाभकारी मालिकों व पोर्टफोलियो का ब्योरा सार्वजनिक करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया।

जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जीके उपाध्याय की पीठ ने कहा, 'हमारा मानना है कि संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए ऐसी मांग मंजूर नहीं की जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जिस पूर्ण ब्यौरे को उजागर करने की मांग की है, उसके लिए कानूनी ढांचे या नियमों की जरूरत होगी। ऐसे कानूनी ढांचे या नियमों के अभाव में अदालत अंतिम लाभार्थी मालिकों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश नहीं दे सकती। इसलिए रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।'

पीठ ने कहा कि अदालत के सामने ऐसा कोई निवेशक नहीं है, जो वास्तव में प्रभावित हुआ हो। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश में विदेशी निवेश न आए। भूषण ने इसका खंडन करते हुए कहा कि अंतिम लाभार्थी मालिकों का ब्योरा उजागर करने से वैध निवेश को कोई नुकसान नहीं होगा।

- कहा, कानूनी व्यवस्था या ढांचे के अभाव में नहीं दे सकते इसके निर्देश
- याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा से कहा, वह संसद में उठा सकती हैं यह मुद्दा

पीठ सांसद सदस्य महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में पीठ ने मोइत्रा से ऐसी याचिका दायर करने पर सवाल किया और कहा कि वह यह मुद्दा संसद में उठा सकती हैं और चर्चा की मांग कर सकती हैं। उनके वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इन दिनों संसद में चर्चा कराना बहुत मुश्किल है और वह इस संबंध में हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'हम निवेश निकायों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे शेयर बाजारों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।'

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एनसीएलटी पर कर लिया है कब्जा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक टिप्पणी में कहा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और उसकी अपीलीय संस्था एनसीएलएटी को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है।

एनसीएलटी और एनसीएलएटी के अध्यक्षों को नियुक्तियों के मामले में स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने अंतरिम उपाय के तौर पर प्रतिनियुक्ति और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) या कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के जरिये चरणबद्ध तरीके से नियमित भर्ती का सुझाव दिया।

प्रधान न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा, 'मैं जानता हूं कि ठेकेदार किस तरह अपना खेल खेलते हैं। उन्हें न्यायिक या तकनीकी सदस्यों की परवाह नहीं है। न्यायाधिकरण पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इससे संस्था की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। यही समस्या है। मंत्रालय पूरी पकड़ रखना चाहता है; यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।'

उन्होंने ये टिप्पणियां एनसीएलटी और एनसीएलएटी में काम कर रहे सेविदा कर्मियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं। सेविदा कर्मियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि मामले का फैसला अदालत को करना चाहिए और लंबे समय से काम कर रहे लोगों को रातोंरात नहीं हटाया जाना चाहिए।

- कहा, नियुक्ति के मामले में मिले इसके अध्यक्षों को स्वायत्तता

चिंतन

ठगी मामलों में जिम्मेदारी से नहीं बच सकते बैंक

डिजिटल बैंकिंग ने लेन-देन को जितना आसान बनाया है, साइबर अपराधियों ने भी उसी रफ्तार से लोगों की जमा-पूंजी पर सेंध लगाने के तरीके खोज लिए हैं। मोबाइल की एक घंटी, वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी और गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों को उनकी जीवनभर की कमाई से वंचित किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी अब केवल साइबर अपराध की समस्या नहीं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था की सुरक्षा और जवाबदेही की भी गंभीर परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बैंकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी लापरवाही से ठगी होती है तो उन्हें पीड़ितों को हर्जाना देना चाहिए। यह टिप्पणी बैंकिंग प्रणाली को उसकी बुनियादी जिम्मेदारी याद दिलाती है। ग्राहकों के धन की सुरक्षा केवल खाताधारक की सतर्कता पर नहीं छोड़ी जा सकती। आंकड़े समस्या की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। वर्ष 2026 में अब तक डिजिटल अरेस्ट के 22 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं और 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी हुई है। वर्ष 2025 में ऐसे 58,239 मामलों में लगभग 1,211 करोड़ रुपये गंवाए गए। ये आंकड़े बताते हैं कि जागरूकता अभियान और लगातार सामने आ रही खबरों के बावजूद अपराधियों का जाल कमजोर नहीं पड़ा। सवाल यह है कि जब डिजिटल लेन-देन का पूरा तंत्र बैंकों की निगरानी में संचालित होता है, तब असामान्य और संदिग्ध लेन-देन को समय रहते पकड़ने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है? कोई खाताधारक अचानक अपनी जमा-पूंजी कुछ ही मिनटों में दूसरे खातों में भेजने लगे, किसी खाते में असामान्य रकम आने और तत्काल आगे हस्तांतरित होने का सिलसिला शुरू हो जाए या किसी खाते का इस्तेमाल लगातार संदिग्ध लेन-देन के लिए हो, तो बैंकिंग प्रणाली को सतर्क होना चाहिए। बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। असामान्य लेन-देन पर तत्काल अतिरिक्त सत्यापन, ग्राहक से स्वतंत्र माध्यम से संपर्क, संदिग्ध खातों की त्वरित जांच और ठगी की आशंका होने पर धन हस्तांतरण को अस्थायी रूप से रोकने की प्रभावी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस, साइबर अपराध इकाइयों, बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच तत्काल सूचना साझा करने का तंत्र भी जरूरी है। बैंकों की जवाबदेही तय करने के मामले में भी स्पष्ट नियम जरूरी हैं। यदि जांच में साबित हो कि बैंक ने निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया, संदिग्ध गतिविधियों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की या शिकायत मिलने के बाद धन रोकने में अनुचित देरी की, तो पीड़ित को मुआवजा दिया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को इस दिशा में ठोस नियम बनाने चाहिए, ताकि ग्राहकों को मुआवजे के लिए भटकना न पड़े। दूसरी ओर, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भयभीत किए जा रहे लोगों को यह समझाना भी जरूरी है कि पुलिस, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियां वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करतीं और न ही गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी खाते में रकम जमा कराने की वैध प्रक्रिया है। अपराधी सरकारी प्रतीकों, फर्जी पहचान और मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में लोगों को अनजान वीडियो कॉल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, न ही ओटीपी, बैंक विवरण या गोपनीय जानकारी साझा करनी चाहिए। यदि ग्राहक को यह आशंका रहने लगे कि उसकी जीवनभर की कमाई कुछ मिनटों में गायब हो सकती है और उसके बाद उसे केवल शिकायतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो डिजिटल बैंकिंग की विश्वसनीयता प्रभावित होगी।



आर्थिकी

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

अब जीएसटी सुधारों का नया दौर

एक नवंबर से भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों का नया दौर आकार लेने जा रहा है। इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित हो रही विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह रेखांकित हो रहा है कि भारत के अप्रत्यक्ष कर (इन डायरेक्ट टैक्स) ढांचे में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई जीएसटी कर प्रणाली भारत के आर्थिक इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रही है और अब इससे भारत की आर्थिक मजबूती का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' के विजन के साथ शुरू हुई यह व्यवस्था विगत वर्षों में निरंतर प्रशासनिक, तकनीकी और प्रक्रियागत सुधारों से गुजरते हुए अब अपने सबसे परिपक्व चरण में प्रवेश कर रही है। राजनीतिक इच्छाशक्ति और आवश्यक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एकीकृत जीएसटी कानून लागू किया गया। निसंदेह जीएसटी लागू होने के बाद से भारत का कर आधार (टैक्स बेस) तेजी से विस्तृत हुआ है और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) के डिजिटलीकरण, ई-वे बिल और ई-इन्वॉयसिंग जैसे तकनीकी नवाचारों ने कर चोरी पर अंकुश लगाकर असंगठित क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। इन सुधारों के कारण राजस्व संग्रह में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है; जहां वित्तीय वर्ष 2017-18 के शुरुआती दौर में औसत मासिक संग्रह



लगभग 90,000 करोड़ रुपये प्रति माह रहता था, वहीं सितंबर 2026 में यह बढ़कर 2,00,000 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। यह ऐतिहासिक राजस्व संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती, कर अनुपालन में आई पारदर्शिता और कर प्रणाली की उच्च दक्षता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में करीब 9 वर्षों के अनुभवों के आधार पर दूरगामी सुधारों को हरी झंडी दी गई है। इनसे नए रिफंड आवेदनों को पूरी तरह से डिजिटल और जोखिम मूल्यांकन आधारित ऑटोमेटेड सिस्टम पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे रिफंड पावती की अवधि घटेगी और दावा की गई राशि बिना किसी अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप के सीधे कारोबारियों के बैंक खातों में जमा होगी। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जूझ रहे उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए 90 प्रतिशत तक का अस्थायी रिफंड तुरंत स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई है, जिससे एमएसएमई और विनिर्माण इकाइयों की फंसी हुई पूंजी तुरंत अनलॉक होगी। सामान की बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट (पोस्ट-सेल डिस्काउंट) और क्रेडिट नोट से जुड़े अनुपालन नियमों को व्यावहारिक और लचीला बनाया गया है, जिससे व्यापारी अपनी वास्तविक कर देनदारी का सटीक संतुलन बना सकेंगे। कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने और व्यापारियों में विश्वास जगाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। एक ऐतिहासिक कदम के तहत जीएसटी अधिकारियों की सीधी गिरफ्तारी की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है; अब अधिकारी महज कानून का हवाला देकर कारोबारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे और इसके लिए अदालत से पूर्व आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) की सीमा को बढ़ाए जाने से छोटे और ईमानदार व्यापारियों में फैला 'टैक्स टेरर' का डर समाप्त होगा। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से व्यापार करने वाले छोटे व असंगठित विक्रेताओं के लिए पंजीकरण और अनुपालन की शर्तों को बेहद आसान बनाया गया है, जिससे वे वेयरहाउस का उपयोग कर बिना जटिल कागजी कार्रवाई के व्यापार कर सकेंगे। छोटे विवादों से राहत देते हुए 10,000 रुपये से कम की कुल कर देनदारी पर अब कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) जारी न करने और धारा 125 के तहत सामान्य जुर्मानी की सीमा घटाने के फैसले लिए गए हैं। कर ढांचे को व्यावहारिक बनाने के लिए कर दरों और स्लैब का पुनर्गठन एक अत्यंत प्रभावी कदम सिद्ध हुआ है। जीएसटी के शुरुआती वर्षों में मुख्य रूप से चार कर स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, और 28 प्रतिशत) तथा विभिन्न उपकर (सेस) प्रभावी थे, जिन्हें बाद में जीएसटी परिषद द्वारा व्यापक समीक्षा के बाद पुनर्गठित कर मुख्य रूप से दो प्रमुख स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के अंतर्गत सुव्यवस्थित किया गया।

निसंदेह जीएसटी संबंधी हालिया सुधार सराहनीय हैं, परंतु जीएसटी को पूर्णतः गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने के लिए अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मोर्चों पर काम किया जाना शेष है। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, बिजली और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जब तक ये वस्तुएं जीएसटी के तहत नहीं आतीं, तब तक समूची मूल्य श्रृंखला में इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह संभव नहीं है। उम्मीद करें कि एक नवंबर से चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहे सुधारों और एक अप्रैल 2027 से लागू होने वाले जीएसटी के दीर्घकालिक सुधारों से जीएसटी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और कर आतंक की समाप्ति से उद्योग-कारोबार जगत लाभान्वित होगा।

(लेखक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

> एक नवंबर से भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों का नया दौर आकार लेने जा रहा है। इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित हो रही विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह रेखांकित हो रहा है कि भारत के अप्रत्यक्ष कर (इन डायरेक्ट टैक्स) ढांचे में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई जीएसटी कर प्रणाली भारत के आर्थिक इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रही है और अब इससे भारत की आर्थिक मजबूती का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' के विजन के साथ शुरू हुई यह व्यवस्था विगत वर्षों में निरंतर प्रशासनिक, तकनीकी और प्रक्रियागत सुधारों से गुजरते हुए अब अपने सबसे परिपक्व चरण में प्रवेश कर रही है।

विधान परिषद चुनाव

बाल मुकुन्द ओझा



भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी

देश के 4 राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के चुनाव नतीजों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में खलबली मचा दी है। भाजपा ने प्रतिष्ठा वाली सीटों पर हार के मद्देनजर आत्म चिंतन और विश्लेषण शुरू कर दिया है। बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस अपनी बुरी हार के बावजूद एक नवम्बर की रैली में व्यस्त है। कांग्रेस ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज एक सीट पर विजय हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की बैलेट पेपर पर हार से तंज कसते हुए कहा, चार बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव में 28 सीटों पर मतदान पर्ची से हुए। अनुमान लगाइए कि इनमें कांग्रेस को कितनी सीट मिली हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बनारस और नागपुर की हार पर भाजपा को आईना दिखाया है। दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। कर्नाटक में सत्तारूढ़ होने के बावजूद कांग्रेस ने चारों सीटें गंवा दी। इनमें एक सीट पहले कांग्रेस के पास थी। वहीं भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस संसदीय सीट पर हुए स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों पर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, आरएसएस मुख्यालय की नागपुर सीट भी भाजपा ने कांग्रेस के हाथों गंवा दी। नागपुर आरएसएस का मुख्यालय होने के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी गृह क्षेत्र है। हालांकि भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ 28 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की है। अकेले भाजपा को इनमें से 13 सीटें मिली हैं। उसकी सहयोगी जदयू, जदएस और शिवसेना (शिंदे) को एक-एक सीट मिली है। इसी के साथ ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के नतीजे भी कांग्रेस को मुफीद नहीं रहे। चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी, जबकि कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई। यूपी में कुछ ही माह बाद विधान सभा चुनाव होने जा रहा है। इस दृष्टि से इन चुनावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 28 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस महज एक सीट पर जीत हासिल कर पाई है। यह कांग्रेस के लिए झटके की तरह है। वहीं बीजेपी भले ही सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही हो, लेकिन वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 2 सीट और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संसदीय क्षेत्र नागपुर की स्नातक सीट से हार गई। यूपी में 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हुए थे। इनमें से छह सीटों पर भाजपा जीती है और पांच सीटें मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। पहले सपा के पास तीन सीटें थीं और दो सीटों पर निर्दलीय जीते थे। इस बार सपा ने पांच सीटें जीती हैं। सपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी की स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। स्नातक सीट पर आशुतोष सिन्हा ने भाजपा के केदारनाथ सिंह को हराया तो शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव ने प्रमोद मिश्रा को हराया। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में सपा की कांति सिंह और इलाहाबाद-झांसी सीट पर सपा के मानसिंह यादव जीते। शिक्षक क्षेत्र में सपा ने आगरा और वाराणसी दो सीटों पर जीत हासिल की। गोरखपुर सीट पर कांटे की टक्कर में भाजपा के धुव त्रिपाठी सिर्फ 307 वोट से जीते। भाजपा को शिक्षक क्षेत्र में मेरठ और लखनऊ में जीत मिली है, जबकि स्नातक क्षेत्र में आगरा और मेरठ-सहारनपुर में जीत मिली है। बिहार में आठ सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से चार सीटें एनडीए के खाते में गई हैं, जबकि चार सीटें अन्य को मिली हैं। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा 30 साल के बाद हारी है। राजद के डॉक्टर संजीव ने भाजपा को नवल किशोर यादव को हराया। भाजपा ने कोशी स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत शिक्षक सीट पर जीत हासिल की है। जनता दल को सिर्फ एक पटना स्नातक की सीट मिली है। दरभंगा शिक्षक सीट जनसुराज के सुरेश राय ने जीती है। सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय जीते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के नतीजे आ गए थे। इनमें से दो सीटें सत्तारूढ़ गठबंधन यानी भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति ने जीती हैं और तीन सीटें विपक्ष यानी महाविकास आघाडी के खाते में गई हैं। पुणे शिक्षक सीट पर भाजपा के कौस्तुभ गावडे और अमरावती शिक्षक सीट पर एकनाथ शिंदे की शिव सेना के किरण सरनाइक जीते हैं। महाविकास अघाड़ी में दोनों सीटें शरद पवार की एनसीपी को मिली हैं। छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट और पुणे स्नातक सीट उनके उम्मीदवार जीते हैं। नागपुर स्नातक सीट कांग्रेस ने जीत ली है।

(लेखक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

खोने के डर को मन पर हावी ना होने दें



संकलित

दर्शन

कई बार छोटी-छोटी बातें भी मन को इतना परेशान कर देती हैं कि जरूरी काम करना मुश्किल हो जाता है। किसी बात के बिगड़ने का डर हो या कुछ खोने की चिंता, मन लगातार उलझा रहता है। ऐसे में श्रीमद्भगवद्गीता की सीख जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए मनुष्य को सुख-दुख और लाभ-हानि में संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया है। भगवान श्रीकृष्ण की सीख के अनुसार, मनुष्य की चिंता का एक बड़ा कारण किसी चीज को खोने का डर है। जब हम किसी उपलब्धि, रिश्ते या सुख-सुविधा से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो उसे खोने की आशंका परेशान करने लगती है। कई बार मनुष्य किसी चीज को हासिल करने के बाद भी उसके छिन जाने की चिंता में रहता है। इसलिए जीवन में जो कुछ मिला है, उसका आनंद लें, लेकिन उसे हमेशा अपने पास बनाए रखने की जिद ना करें। यही सोच मन को हल्का रखने में मदद करती है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने हर परिस्थिति में संतुलित रहने की सीख दी है। जीवन में कभी मन के मुताबिक परिणाम मिलते हैं, तो कभी निराशा हाथ लगती है। अगर हर अच्छी बात पर जरूरत से ज्यादा खुश और हर परेशानी में टूटने लगेंगे, तो मन हमेशा बेचैन रहेगा। इसलिए सुख मिलने पर अहंकार ना करें और दुख आने पर हिम्मत ना हारें। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इस बात को समझने वाला व्यक्ति मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रखता है।

दूसरों से सीखिए, नकल मत कीजिए



संकलित

प्रेरणा

जिंदगी में हम सभी किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं। कोई अपने माता-पिता से कुछ सीखता है, कोई शिक्षक से, तो कोई किसी सफल व्यक्ति को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दूसरों की अच्छी आदतों और विचारों से सीखना गलत नहीं है। परेशानी तब शुरू होती है, जब हम सीखने के बजाय उसी व्यक्ति की नकल करने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक सीख इसी बात की ओर ध्यान दिलाती है। उनका संदेश था - दूसरों से जो भी अच्छा है, उसे सीखो, लेकिन उसे अपनी तरह से अपनाओ, किसी और जैसे मत बनो।' इस विचार में सीखने के साथ-साथ अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी कही गई है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, जिससे हम सीख सकते हैं। किसी का अनुशासन अच्छा हो सकता है, किसी की मेहनत, किसी का धैर्य तो किसी की सोचने का तरीका हमें प्रभावित कर सकता है। विवेकानंद की सीख है कि ऐसी अच्छी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मन को खुला रखें और जहां से अच्छी बात मिले, उसे सीखने की कोशिश करें। ज्ञान किसी एक व्यक्ति या जगह तक सीमित नहीं होता है। किसी की बात अच्छी लगी, तो उसे तुरंत अपनी जिंदगी का नियम बना लेना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। जो तरीका किसी दूसरे के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी उसी तरह काम करे। इसलिए किसी अच्छी बात को पहले समझना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी और परिस्थितियों के हिसाब से कैसे अपनाया जा सकता है।

अंतर्मन



आज की पाती

अपशिष्ट प्रबंधन के ठोस उपाय करना जरूरी

कम करें, पुनः उपयोग करना, रीसायकल करना एक ऐसा टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन है, जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य और पर्यावरण के अनुकूल है। अपशिष्ट उत्पाद आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले प्रदूषण का कारण बनता है। कम करना, पुनः उपयोग करना और रीसायकल करना भूमि, वायु और जल प्रदूषण के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक को खत्म करने के तीन बेहतरीन तरीके हैं। कम करने का मतलब है कि अपशिष्ट को जन्म लेने से पहले ही रोक दिया जाता है। अपशिष्ट में कमी का सीधा मतलब है उन चीजों को कम करना जिन्हें हम उपयोग करते हैं और केवल वही उपयोग करते हैं जो आवश्यक है।

विनय कुमार साहू, रायपुर

ट्रेंड

आयुष्मान वय वंदना योजना

हमारे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्यजनक जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। इस दिशा में, 29 अक्टूबर 2024 को 'आयुष्मान वय वंदना योजना' की शुरुआत के आज दो साल पूरे हो गए हैं।

- जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री

टाटा को बर्बाद कर रहे

टाटा को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, और किसी भी कारोबारी नेता में इस बारे बोलने की हिम्मत नहीं है। आप कब तक चुप रहेंगे? क्या तब तक, जब तक वे आप पर पूरी तरह कब्जा न कर लें? भारतीय कारोबार मोदी और शाह के खिलौने नहीं हैं।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

मतदान रोकने की साजिश

वाराणसी में मतदान को रोकने या धीमा करने के पीछे की साजिश को सब समझते हैं, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब नहीं होगी। वाराणसी में बीजेपी की हार राष्ट्रीय खबर न बन जाए, इसे रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

अधिकार की रक्षा

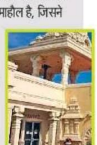
1 नवंबर को 'इंडिया' रामलीला मैदान में एकजुट होकर खड़ा होगा। 'वोट चोरी' के खिलाफ यह लड़ाई, हर भारतीय के चुनने के अधिकार की रक्षा करने की लड़ाई है। बंगाल और अन्य राज्यों में हुई 'वोट लूट' पर जवाब चाहिए, खामोशी नहीं!

- ममता बनर्जी, पूर्व सीएम, प. बंगाल

करंट अफेयर

मंदिर पर गोलीबारी, दक्षिण एशियाई समुदाय में चिंता

शिकागो के पास एक हिंदू मंदिर में सामूहिक गोलीबारी की साजिश को नाकाम किए जाने के बाद क्षेत्र के दक्षिण एशियाई समुदाय में डर का माहौल है, जिसने आस्था और पारिवारिक समारोहों के आसपास पर उत्सासपूर्ण मौसम को फीका कर दिया है। अभियोजकों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में, जब 11 अक्टूबर को नवरात्र का त्योहार शुरू होने पर श्रद्धालु हिंदू मंदिरों में इकट्ठा हुए थे, तब एलेवजेंड्रोस पापोगिरास इलिनॉय के ऑरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर पहुंचा और पार्किंग क्षेत्र में बैठ गया, लेकिन राइफल जाम होने के कारण गोली चलाए बिना ही भाग गया। अभियोजकों ने बताया कि पापोगिरोकिस (19) को उसी दिन शिकागो से करीब 64 किलोमीटर दूर इलिनॉय के प्लैटेइन स्थित उसके घर के पास गिरफ्तार किया गया। 'टैको बेल' के एक कर्मचारी ने अधिकारियों को उसकी भारतीय लोगों को मारने की योजना के बारे में सूचना दी थी। उस पर आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने के गंभीर आरोप हैं। उसे शुक्रवार को फिर अदालत में पेश होना है। दक्षिण एशियाई समुदाय को एकजुट करने वाले गैर-लाभकारी संगठन 'द शिकागो कसम' की कार्यकारी निदेशक आशा राव ने कहा कि समुदाय के लोग इस घटना से स्तब्ध और आक्रोशित हैं।



ऑफ बीट

ब्रिटिश पीएम बर्नहम आएंगे भारत, मजबूत होंगे रिश्ते

ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम भारत का दौरा करने के इच्छुक हैं और जल्द ही उनकी यात्रा हो सकती है। एक शीर्ष राजनयिक ने बृहस्पतिवारक को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का उल्लेख करते हुए यह जानकारी दी। भारत में कार्यवाहक ब्रिटिश उच्चायुक्त बेन मेलर ने यहां बताया कि पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान, बर्नहम ने भारत आने की अपनी इच्छा जताई थी। मेलर ने कहा, मुझे पता है कि एंडी बर्नहम भारत आने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, जब बर्नहम ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उसके तुरंत बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने सीधे तौर पर यह बात रखी थी। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही ऐसा होता हुआ देख पाएंगे। इस साल 20 जुलाई को बर्नहम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। भारत-ब्रिटेन आर्थिक संबंधों पर, मेलर ने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे-जैसे ब्रिटेन और भारत की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेंगी, हम दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य को पार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता 100 दिन पहले लागू हुआ, लेकिन असल में इस पर एक साल से कुछ समय पहले ही हस्ताक्षर किए गए थे तथा तब से अब तक 12 अरब पाउंड के नए समझौते हो चुके हैं।



अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

भित्यापाठी माहितीचा ब्रह्मराक्षस

'माहिती अडवा, माहिती दडवा!' हा अग्रलेख (२९ ऑक्टोबर) वाचला. सुरुवातीला समाजमाध्यमांत पेरलेल्या भाकडकथा जोवर आपल्या राजकीय फायद्याच्या होत्या तोवर विद्यमान सरकारला माहितीचा प्रसार व प्रचार हे दोन्ही हवेहवेसे वाटत होते. कालांतराने तेच राज्यकर्त्यांसाठी दुधारी शस्त्र ठरले. तत्कालीन मुख्य माहिती स्रोतांवर मालकी हक्क प्रस्थापित केल्यावरही राज्यकर्त्यांच्या हितास मारक अशा माहितीचे नवनवीन स्रोत निर्माण झाले व फोफावले. त्यावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न सरकारदरबारी सुरू झाले. आणि माहितीच्या अधिकारावर टप्प्याटप्प्याने गदा आली. 'फॅक्ट चेक युनिट' स्थापनेचा प्रयत्नदेखील याचाच एक भाग होता. पण लोकशाहीच्या सुदैवाने उच्च न्यायालयाने ते असांविधानिक ठरवून रद्द केले. आता माहितीचे वादळ निवडणूक आयोग, मित्र उद्योगपती आणि सर्वोच्च न्यायालयावरही घोंगावू लागले आहे. केंद्र सरकारचा डीपीडीपी कायदा हा या माहितीच्या वादळाला आळा घालण्याचा प्रयत्न आहे. माहिती बंद, टीका बंद! डीपीडीपी कायद्याखाली दंडाची २५० कोटी रुपये एवढी रक्कम पाहता माहितीचा ब्रह्मराक्षस सरकारच्या मागे किती हात धुऊन लागला आहे, हे स्पष्ट होते.

■ **ओवी भावे,** पुणे

आजचे निर्णय उद्या महागात पडू शकतात

'माहिती अडवा, माहिती दडवा!' हे संपादकीय वाचले. माहिती अडवली तर ती जास्त जिरते, पाण्यासारखी वाट मिळेल तेथे पसरते. माहिती दाबली तर ती कर्णोपकर्णी जाताना त्यात आणखी भर पडत जाते. गैरसमज वाढतात. झाकले की बघण्याचा मोह वाढतो. डिजिटल माध्यमांना दहा तोंडे असतात. सरकार कोणाकोणाला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार देणार? अनेक वर्षे विरोधी पक्षात घालवलेल्या भाजपला डीपीडीपीसारखा कायदा केला तर काय परिणाम होतो हे माहीत असणे अपेक्षित होते. आजचा सरकारी पक्ष उद्याचा विरोधी पक्ष होऊ शकतो हे ध्यानात ठेवून विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी जपून पावले टाकावीत.

■ **श्रीनिवास डोंगरे,** दादर (मुंबई)

नैतिकतेला कात्री लावण्यासाठीच

'माहिती अडवा, माहिती दडवा!' हा अग्रलेख (२९ ऑक्टोबर) वाचला आणि १८२३ साली जॉन अ‍ॅडम याने ब्रिटिश आधिपत्याखाली असलेल्या भारतातील वृत्तपत्रांना अशाच प्रकारे नियंत्रित करणारा 'परवाना अधिनियम १८२३' जारी केल्याचे आठवले. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवणाऱ्या आपल्या देशातील बहुतांश इलेक्ट्रिक आणि मुद्रित माध्यमांना विविध मार्गांनी स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न सरकार करताना दिसते. मुख्य प्रवाहातील अनेक माध्यमांना त्यांची भूमिका प्रामाणिकपणे बजावण्यात अडथळे येताना दिसतात. त्यामुळेच अनेकांनी पत्रकारितेसाठी नवे मंच शोधले आहेत. आता या मंचांवरील आशयही आपल्या नियंत्रणात असावा यासाठी सरकार धडपडत आहे. धोरणकर्ते घटनात्मक संस्थांना आणि त्यांच्या प्रमुखांना हाताशी धरून स्वतःला हवे तेच साधून घेत आहेत. हे करताना नैतिकतेलादेखील कात्री लावत आहेत.

■ **सचिन शिंदे,** बीड

सरकारच्या सोयीचे बदल

'माहिती अडवा, माहिती दडवा!' हे संपादकीय (२९ ऑक्टोबर) वाचले. अलीकडे प्रसारमाध्यमांवर उद्योगपतींचे वर्चस्व वाढू लागले असताना सरकारचा 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन' कायदा (डीपीडीपी) लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न आहे. लोकशाही व्यवस्था मजबूत करणाऱ्या संस्थांचे अधिकार कमी करण्याचे काम सरकारच्या वतीने सुरू आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ९९वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या (एनजेएसी) माध्यमातून न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. संविधानाने न्यायव्यवस्थेला दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला; परंतु न्यायव्यवस्थेने ही घटना दुरुस्ती रद्द करून सरकारचे प्रयत्न हाणून पाडले. निवडणूक आयोगाच्या बाबतीतही तेच झाले २०२३ च्या कायद्याने निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांऐवजी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश केला. म्हणजेच सरकार आपल्या सोयीने वाटेल ते बदल करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. जे लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे.

■ **विष्णू चौरे,** नांदेड

'हा' पर्यावरणपूरक विकास?

'उजाड जंगलातील अस्वस्थ स्मशान शांतता!' ही बातमी (लोकसत्ता- २९ ऑक्टोबर) वाचली. कर्जत परिसरात टोरंट पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची होणारी कत्तल हा भविष्यावर घाला आहे. राज्यात दुष्काळस्थिती असताना विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश होणे, दुर्दैवी आहे. जंगलसंपत्ती वाचवली तरच पुढच्या पिढ्या वाचतील, याचा विचार करणार की नाही? स्वच्छ हवा, पाणी, जंगले आणि जैवविविधता उधळून लावली जात आहे. वर्षानुवर्षांची झाडे तोडून म्हणायचे आम्ही नवीन ९० हजार झाडे लावू, प्रकल्प पर्यावरणपूरक आहे... या दाव्यांत अजिबात तथ्य नाही. सत्ताधारी नेत्यांची यासंदर्भातील वक्तव्ये ही दिशाभूलच आहे. परिपक्व जंगल हा केवळ झाडांचा समूह नसतो. ती कार्बन शोषणारी, तापमान संतुलित ठेवणारी, मातीची धूप रोखणारी, जलचक्राला आधार देणारी आणि असंख्य जीवांना आश्रय देणारी जिवंत परिसंस्था आहे, हे सरकारच्या लक्षात का येत नाही? विविध प्रकारची परिसंस्था, जैवविविधता निसर्गच निर्माण करतो, ही संपदा नष्ट करून उभारण्यात येणाऱ्या 'विकासा'लाच पर्यावरणपूरक विकास म्हणायचे का?

■ **राजेंद्र पाडवी,** तळोदा (नंदुरबार)

गोपनीयता, जबाबदारीचे काय?

'आता जनगणनाही खासगी व्यक्तींच्या हाती' ही बातमी (लोकसत्ता- २९ ऑक्टोबर) वाचली. देशात जनगणनेचे काम करण्यासाठी खासगी व्यक्तीची नेमणूक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सर्व पक्षीय राज्यकर्ते खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचा अट्टहास धरत आहेत. आधीच एसआयआर प्रकियेचा पुरता गोंधळ उडालेला आहे. या प्रक्रियेची धुरा बीएलओंवर आहे. रेल्वेपासून बँका, तेल कंपन्या सर्वच क्षेत्रांत खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण रेटून नेले जात आहे. सरकारकडे लाखो कर्मचारी, अधिकारी असताना, त्यांच्याकडून काम करवून घेणे आवश्यक आहे. खासगी व्यक्तीकडे सरकारी काम दिल्यास गोपनीयता, जबाबदारी याचे काय करायचे? केवळ कमिशन, टक्केवारी, आपली माणसे, आपला कंत्राटदार यासाठी तर जनगणनेचे काम खासगी व्यक्तींकडे दिले जात नाही ना?

■ **अनंत बोरसे,** शहापूर जिल्हा, ठाणे

दुही माजवणारे प्रचारकी कारखाने

'सनातन' अवकाशाला कुंपण...' हा लेख (२९ ऑक्टोबर) वाचला. धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीची जी अवस्था होते, तशीच तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यापासून सुवेंदु अधिकारींची झाली आहे. हिंदू-सनातनप्रेम जास्तच बोकाळले आहे. हेच लोण देशभर पसरत असल्याचे दिसते.

मध्यंतरी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मढी येथील कानिफनाथ यात्रेत मुस्लिमांना दुकाने लावण्यास मनाईचा एकमुखी निर्णय ग्रामसभेने घेतला आणि तथाकथित नवहिंदुत्ववाद्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. तसेच मध्यंतरी संदल मिरवणुकीत त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या पायरीला धूप दाखविण्यास आणि फुले अर्पण करण्यास विरोध दर्शवण्यात आला. मंदिर प्रवेशद्वारावर गोमूत्र शिंपडून 'शुद्धीकरण' केले. गुजरातमध्ये हिंदू धर्मस्थळ परिसरात मुस्लीम विक्रेत्यांवर बंदी घातली गेली. अशा धार्मिक विद्वेष पसरवणाऱ्या घटना सातत्याने घडत आहेत. कोल्हापूरच्या बाबूजमल दर्ग्याच्या प्रवेशद्वारावर गणेशाची मूर्ती आहे तर सांगलीच्या कडेगावची ताबूत परंपरा भाऊसाहेब देशपांडे यांनी सुरू केली. अशी असंख्य धार्मिक एकोपा साधणारी उदाहरणे पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात दिसतात. वैष्णोदेवी दर्शनासाठी भाविकांच्या पालखीचे भोई असणारे असंख्य मुस्लीम हिंदू धर्माचरणाशी एकरूप झाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये अनेक मुस्लीम नवरात्रोत्सवात सहभागी होतात एवढेच नव्हे तर नवरात्रोत्सव आयोजितदेखील करतात. अशा विविधतेत एकता जपणाऱ्या भारतात दुही माजवणारे प्रचारकी कारखाने अहर्निश सुरू आहेत ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. समाजात असा कोणता समाज आहे, ज्याने धर्म विद्वेषातून प्रगती साधली आहे?

■ **बाळकृष्ण शिंदे,** बिबवेवाडी (पुणे)

हा नव्या आशेचा प्रारंभ!

लोकशाहीचे वस्त्रहरण रोखण्यासाठी जनता आणि राजकीय पक्ष उभे राहात असतील, तर त्याला अराजकता म्हणता येणार नाही, याची आठवण देणारा हा प्रतिवाद...

सचिन सावंत
राष्ट्रीय सचिव - अखिल भारतीय काँग्रेस समिती

संपूर्ण विरोधी पक्ष व आंदोलक मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांचा राजीनामा मागत असताना भाजपला पोटशूळ का उठावा बरं? ज्ञानेश कुमार यांच्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इतके प्रेम का की त्यांच्या निवडीसाठी साक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना निवड समितीतून बाहेरचा रस्ता दाखवावा लागला?

ज्ञानेश कुमार यांच्या निवडीपूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अशी निवड समिती होती. या व्यवस्थेत 'सरन्यायाधीशांऐवजी केंद्रीय मंत्री' असा बदल करून गृहमंत्री अमित शहा यांना समितीत सामील करण्यात आले. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधानंतरही मोदी आणि शहा यांच्या मर्जीने दोन विरुद्ध एक मतांनी ज्ञानेश कुमार यांची निवड झाली. पुढे मोदी सरकारने विरोधी पक्षाच्या बहिष्काराला न जुमानता मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निवृत्तीनंतरही कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणारी तरतूद संसदेत मंजूर करून घेतली. पदावर राहून असा कोणता गुन्हा ते करणार हे अपेक्षित होते की ज्यातून त्यांना संरक्षणाची गरज होती? म्हणूनच ज्ञानेश कुमार आणि भाजप यांच्यातील नात्याबद्दल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है?' या प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी आधी दिले पाहिजे.

मुख्यमंत्री आपल्या लेखात 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे वर्णन 'काँग्रेस जिताओ पार्टी' असे करतात. अवघ्या चार दिवसांत समाजमाध्यमांवरील एका पेजला कोट्यवधी युवकांनी प्रतिसाद दिला. यातूनच युवकांच्या मनातील असंतोषाची व्याप्ती लक्षात येते. 'आमच्याकडे राजीनामे होत नाहीत,' असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारला धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागूनही जर या असंतोषाची जाणीव होत नसेल, तर ते विरोधी पक्षांसाठी चांगलेच आहे. परंतु काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या विरोधात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' आंदोलन जवळपास तीन वर्षे चालले. याच आंदोलनात सहभागी असलेल्या एका प्रमुख नेत्याने या आंदोलनामागे संघ आणि भाजपचा छुपा हात होता, असे खुलेआम सांगितले आहे. भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबाही जाहीर केला होता. त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने या आंदोलनाला 'भाजप जिताओ आंदोलन' म्हटले नव्हते, की या आंदोलनामागे परकीय शक्तींचा हात असल्याचा आरोपही केला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या लेखाचा बराचसा भाग 'रेजिम चेंज' या शब्दाची फोड करण्यात खर्च केला आहे. भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये आंदोलनांच्या माध्यमातून राजवटी बदलल्या, त्याच पद्धतीचा अवलंब भारतातही केला जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसेच देशात राजवट नसून सरकार आहे आणि लोकशाही पद्धतीने झालेल्या निवडणुकांमधून सरकार बदलत असते, असे ते म्हणतात. त्यामुळे आंदोलनकर्ते लोकशाही आणि संविधान न मानणारे अराजकवादी आहेत, असा मुख्यमंत्र्यांच्या युक्तिवादाचा अर्थ होतो. नुकतेच संघाच्या वार्षिक मेळाव्यात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देशात 'रेजिम चेंज' होणार नाही, असे मत मांडल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ऐकले. मग भागवत यांच्या मते देशात असे कोणते 'रेजिम' आहे, जे बदलणार नाही, याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. भाजप आणि तथाकथित सांस्कृतिक संघटना असलेल्या संघाची भूमिका आणि शब्दावली एकसारखीच असल्याचे दिसते. हे पाहता देशात संघाचेच रेजिम आहे, असे म्हणण्यास वाव नाही का?

भाजपचा इतिहास विसरू नये!

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गोव्यातील भाषणात निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे भाजपशी संगनमत असल्याचा आरोप केला. यावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अशी बेजबाबदार विधाने कशी करू शकतात, असा प्रश्न मुख्यमंत्री करतात. मुख्यमंत्र्यांना आता भाजपच्याच अलीकडच्या इतिहासाचे स्मरण करून देणे गरजेचे आहे. २००६ ते २००९ या काळात तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांचा काँग्रेसशी संबंध असल्याचा आरोप करून राजीनामा मागण्यात लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच अग्रेसर होता, हे मुख्यमंत्री विसरले का? २००६ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी सुमारे २०० खासदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रपतींना भेटले होते. ईव्हीएमला विरोध करणारे लालकृष्ण अडवाणी हेच आद्य नेते होते.

मे २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान निवडणूक आयोगाने सुरक्षेच्या कारणास्तव नरेंद्र मोदी यांच्या सभेला परवानगी दिली नाही. त्यावेळी अरुण जेटली, अमित शहा आणि व्यंकय्या नायडू यांसारख्या भाजप नेत्यांनी निवडणूक आयोग पक्षपाती असल्याचा आरोप करत मोठे धरणे आंदोलन केले. याच काळात अनेक ठिकाणी भाजपने मतदारयाद्यांवरही आक्षेप घेतले होते. त्यावेळी भाजप 'अराजकतावादी' होता की नव्हता? निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे अराजकता नव्हे. मुख्यमंत्री निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरील प्रश्नांना बगल देण्यासाठी न्यायालयीन निर्णयांचा आधार घेत आहेत. अलीकडेच न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी आपल्या पुस्तकातून मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील न्यायव्यवस्थेच्या स्थितीवर भाष्य केले आहे ते मुख्यमंत्री वाचतील ही अपेक्षा आहे.

मतदार याद्यांचे केवळ 'समरी रिव्हिजन' २००४ मध्ये झाले होते, ते सखोल पुनरीक्षण नव्हते, याची आठवण मुख्यमंत्री देतात; परंतु २००२ मध्ये महाराष्ट्रात 'एसआयआर' प्रक्रिया झाली होती, याचा उल्लेख ते सोयीस्करपणे टाळतात. त्यामुळे 'एसआयआर' प्रक्रियेदरम्यान शहरी भागांत अधिक दुबार मतदार आढळल्याचे त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण कितपत सयुक्तिक आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

आंदोलनाचा आधार केवळ विरोधी पक्षांचे आक्षेप नसून 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने केलेल्या सखोल शोधपत्रकारितेतून समोर आलेले मुद्दे आहेत. या वृत्तमालिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 'ईसीआयनेट' सारख्या सॉफ्टवेअरद्वारे स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मतदारांची नावे जोडण्याच्या किंवा वगळण्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनीही यासंदर्भात दुजोरा दिला आहे. कर्नाटक व तेलंगणमध्ये तर पूर्वमुद्रित फॉर्म क्रमांक ७ निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आल्याचेही समोर आले. तेलंगणमध्ये या प्रक्रियेमागे आपला पक्ष असल्याची कबुली भाजपने दिली आहे. लाखो मतदारांना वगळण्याचा हा डाव आहे.

महाराष्ट्रात २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांत ३२ लाख मतदारांची वाढ झाली होती. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यानच्या अवघ्या पाच महिन्यांत ४१ लाख मतदारांची वाढ झाली. त्यातही १६ ते १९ ऑक्टोबर २०२४ या चार दिवसांत ६ लाख ५५ हजार मतदारांची वाढ झाली. राहुल गांधी यांनी याच प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती.

'एसआयआर' साधारणपणे निवडणुकीच्या दोन वर्षे आधी केली जात असे. मात्र, बिहारमध्ये ही प्रक्रिया निवडणुकीच्या काही महिने आधी सुरू करण्यात आली आणि ६८ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. पश्चिम बंगालमधील 'एसआयआर' प्रक्रियेतून वगळलेल्या मतदारांपैकी ९१ टक्के मतदारांचा निवडणुकीनंतर पुन्हा यादीत समावेश करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगानेच स्पष्ट केले आहे. असे असेल, तर पात्र मतदारांना बंगालच्या निवडणुकीत मतदान करण्यापासून वंचित ठेवण्यात का आले, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील मतांच्या फरकाच्या पार्श्वभूमीवर या मतदारांना मतदान करता आले असते, तर निकाल वेगळा लागला नसता का?

बंगालमध्ये १६ लाख पात्र मतदारांच्या नावांवर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पुन्हा आक्षेप घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हे कोणाच्या आदेशाने करण्यात आले, हे स्पष्ट केले जात नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सॉफ्टवेअर पुरवणारी कंपनी कोणती, हेदेखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये बदल कसे आणि का करण्यात आले? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

लोकशाहीचा पाया असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत निष्पक्षता अपेक्षित असताना, तिच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या मुद्द्यांची उत्तरे मागून राहुल गांधी देशसेवाच करत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे अराजकता नव्हे. राहुल गांधी हे आरोप शपथपत्रावर का करत नाहीत, असा प्रश्न विचारण्यापूर्वी लालकृष्ण अडवाणी यांनी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील आरोप शपथपत्रावर केले होते का, याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. राहुल गांधी हे देशाचे विरोधी पक्षनेते आहेत आणि निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या विरोधी पक्षाची भूमिका मांडत आहेत. ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधी यांना शपथपत्र देण्यास सांगून तसे न केल्यास कारवाई करण्याची धमकी दिली होती, तर अद्याप कारवाई का केली नाही, हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी ज्ञानेश कुमार यांनाच विचारावा.

मोदी आणि संघाच्या राजवटीत शांततापूर्ण विरोध करणाऱ्यांना पोलिसांनी खिळे लावलेल्या दांडक्यांनी निर्दयपणे मारणे, पोलिसांकडूनच दगडफेक होणे, पेलेट गनचा वापर करणे, भाजप आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांना खासगी वेशात पाठवून पोलिसांच्या संरक्षणात आंदोलकांवर हल्ले करण्याची मुभा देणे आणि आंदोलकांना अतिरेक्यांप्रमाणे वागणूक देणे, हे सर्व प्रकार गंभीर आहेत. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारला लोकशाही मान्य आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरेल. देशात इंग्रजांचेच राज्य सुरू असल्याचे वाटावे, अशी परिस्थिती आहे. यूपीए सरकारच्या काळात सातत्याने भारत बंदची हाक देणाऱ्या भाजपला आज स्वतःच्या विरोधात आंदोलने होत आहेत म्हणून आगपाखड करण्याचा अधिकार नाही. ज्या प्रक्रियेतून १३ कोटी ३० लाख मतदारांची नावे वगळली गेली, ती प्रक्रिया सदोष असेल, तर ती नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी अयोग्य कशी? सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनीही इतक्या मोठ्या संख्येने मतदारांना वगळणे नागरिकांना दुय्यम नागरिक बनवण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मग मुख्यमंत्र्यांच्या तर्कानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीही अराजकतावादी आहेत का?

लोकशाहीचे वस्त्रहरण गेली बारा वर्षे खुलेआम होत असताना घटनात्मक संस्था स्वस्थ बसून पाहात असतील आणि अशा वेळी जनता पुढे येऊन लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी उभी राहत असेल, तर त्याला अराजकता म्हणता येणार नाही. तो लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनाचा, जनजागृतीचा आणि नव्या आशेचा प्रारंभ आहे.

कुतूहल

पोटरीत गोळे का येतात?

झोपेत पोटरीत अचानक गोळा येणे ही अनेकांना जाणवणारी समस्या आहे. या वेळी पोटरीतील स्नायू अचानक आकुंचन पावतात व त्यामुळे तीव्र वेदना होऊ शकते. काही वेळाने ही वेदनादायक कळ आपोआप कमी होते. पण या मधल्या काळात अस्वस्थता जाणवत राहते.

झोपेत पोटरीत गोळा येण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे स्नायूंमध्ये निर्माण होणारा थकवा किंवा शरीरातील काही क्षारांचं असंतुलन होणं. या असंतुलनामुळे, तसंच अयोग्य रक्ताभिसरण किंवा पायाच्या स्नायूंमध्ये होणाऱ्या रक्तप्रवाहात अडथळा आल्यामुळे स्नायूंना रक्तातील पोषकतत्त्वांचा पुरेसा पुरवठा होत नाही.



यामुळे स्नायूंना थकवा येतो. अनेकदा धावणं किंवा सायकल चालवणं यासारख्या पायांच्या हालचालींचा समावेश असलेल्या क्रिया अति प्रमाणात केल्यामुळे स्नायूंना थकवा येतो. तसंच दिवसभर जास्त चालणं, खूप वेळ एकाच स्थितीत उभं राहणं, प्रमाणाबाहेर व्यायाम करणं यामुळेही स्नायू थकतात. चुकीच्या पद्धतीने बसल्यामुळेही स्नायूंवर ताण पडतो आणि स्नायू आकुंचन पावून पायात गोळा येतो.

स्नायूंच्या योग्य व सुसूत्र हालचालीसाठी आपल्या शरीराला आहारातील कॅल्शियम, पोटॅशियम, सोडियम आणि मॅग्नेशियम यांच्या क्षारांची म्हणजेच इलेक्ट्रोलाइट्सची नितांत आवश्यकता असते. स्नायूंचं आकुंचन-प्रसरण ही प्रक्रिया या इलेक्ट्रोलाइट्सनी दिलेल्या विद्युत संकेतांवर अवलंबून असते. हे संकेत तयार होण्यासाठी आणि योग्य वेळी स्नायूंचं आकुंचन-प्रसरण योग्य पद्धतीने होण्यासाठी हे इलेक्ट्रोलाइट्स शरीराला आवश्यक असतात. स्नायूंच्या आकुंचनासाठी कॅल्शियम अतिशय महत्त्वाचं आहे तर मॅग्नेशियम स्नायू प्रसरणाला मदत करतं. त्यामुळे स्नायू ताठ होणं, गोळा येणं टळतं. मेंदूकडून स्नायूंना मिळणाऱ्या संदेशांच्या वहनात मॅग्नेशियम मदत करतं. स्नायूंना हालचालीसाठी ज्या स्वरूपात ऊर्जा लागते त्या स्वरूपात तिचा उपयोग होण्यासाठी मॅग्नेशियम आवश्यक आहे. मॅग्नेशियम स्नायूंमध्ये लॅक्टिक आम्ल साचण्याचं प्रमाण कमी करतं ज्यामुळे स्नायू लवकर थकत नाहीत व वेदना कमी होतात. पोटॅशियम आणि सोडियम हे दोन्ही घटक पेशींच्या आतील आणि बाहेरील विद्युत फरक टिकवून ठेवतात. त्यामुळे स्नायूंना योग्य तो संदेश मिळतो व काम करणं सुलभ जातं. या क्षारांचं संतुलन बिघडल्यास म्हणजेच त्यांची शरीरात कमतरता भासल्यास स्नायूंच्या आकुंचन प्रसरणात अडथळा निर्माण होतो व पोटरीत गोळा येतो.

शरीरात पाण्याची कमतरता, झोपण्याची चुकीची पद्धत किंवा इतर काही वैद्यकीय समस्या, हीसुद्धा झोपेत पोटरीत गोळा येण्याची आणखी काही कारणं आहेत. पुरेसं पाणी प्यायल्यास, केळी, नारळपाणी, हिरव्या पालेभाज्या, सुकामेवा, कडधान्य इत्यादींचा समावेश आपल्या आहारात असल्यास पोटरीत गोळे येण्याची समस्या कमी होऊ शकते.

– प्रज्ञा नाडकर्णी
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

ज्या अमेरिकेत १८६५ पर्यंत गुलामगिरी कायदेशीर होती, तिथे त्या हिणकस मानवी पिळवणुकीचा कायदेशीर दर्जा रद्द झाल्यानंतरही शेतमजुरांची प्रभावी संघटना स्थापन होण्यास सुमारे शंभर वर्षे लागली, यात नवल नाही. या बाबतीत गांधीजींचा चंपारण्य सत्याग्रह (१९१७) किंवा डॉ. आंबेडकरांनी अलिबाग परिसरात घडवून आणलेला खोती प्रथाविरोधी संप (१९३३) यासारखे काहीही अमेरिकेत घडूच शकले नाही, इतकी भांडवलशाहीप्रणीत विषमता त्या देशाच्या अंगवळणी पडली होती. अशा स्थितीत नवल हे की, मेक्सिकोतून अमेरिकेत आलेल्या एका महिलेने अमेरिकी शेतमजुरांच्या या लढ्याचे नेतृत्व केले. पुढे बराक ओबामांनी लोकप्रिय केलेली 'येस वी कॅन' ही साधी- पण सामूहिक बळ वाढवणारी घोषणा पहिल्यांदा या महिलेने, शेतमजुरांच्या सभेत स्पॅनिश भाषेत दिली आणि पुढल्या आयुष्यातही लढाऊपणा तिने सोडला नाही. या महिलेचे नाव डोलोरिस उएर्ता (अडानावो स्पेलिंग 'एच' पासून सुरू होते, तरी स्पॅनिश पद्धतीने ते अक्षर अनुच्चारित). वयाच्या ९६ वर्षी त्यांचे निधन झाल्याचे वृत्त गुरुवारी आले.



डोलोरिस उएर्ता

'युनायटेड फार्मवर्कर्स युनियन' हे त्यांनी १९६२ सालापासून स्थपन केलेल्या संघटनेचे नाव. आज तिचे कार्य अमेरिकाभर पसरले आहे. पण प्रामुख्याने दक्षिण अमेरिकेतून रोजगारासाठी येणारे शेतमजूर अमेरिकेच्या खिजगणतीतही नव्हते, तेव्हाच्या काळात डोलोरिस आणि त्यांचे सहकारी सीझर चावेझ यांनी अमेरिकेतील दक्षिणेकडची सर्व राज्ये पिंजून काढली. डोलोरिस यादेखील अशाच शेतमजूर कुटुंबात वाढल्या होत्या. त्या लहान असतानाच आईवडील कॅलिफोर्नियात आले, पुढे वडिलांनी आईला टाकले आणि शिक्षणाची आस असलेल्या डोलोरिस यांना अगदी लहान वयात अन्नप्रक्रिया केंद्रात काम करावे लागले.. सीझर चावेझ हे लढाऊ, प्रभावी नेते. पण या चळवळीला मानवी चेहरा डोलोरिस यांनी दिला. मात्र 'सीझर चावेझ यांनी माझ्यावर लैंगिक बळजबरी केली होती' असा आरोप त्यांनी फार उशीरा- सक्रिय चळवळीतून निवृत्तीनंतर केला. व्यवस्थेशी संघर्ष अदाकि महत्त्वाचा असे आपल्यावर बिंबवण्यात आल्याने स्वतःवरील अन्यायाबाबत आपण गप्प राहिलो, हा त्यांचा त्या वेळचा खुलासा होता.

महात्मा गांधी यांच्या चळवळीने आणि विचारांनी आपण प्रभावित झालो, अहिंसेमधली शक्ती गांधीजींनी जगाला दाखवून दिली, असे डोलोरिस नेहमी सांगत. गांधीजींच्या आध्यात्मिकतेचे सार आपल्यापुरते कॅथॉलिक ख्रिस्ती विचारांत शोधण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. त्यांना 'एलिनॉर रूझवेल्ट मानवी हक्करक्षण पुरस्कार' (१९९८) आणि २०१२ चे 'राष्ट्राध्यक्ष सुवर्णपदक' यांसह अनेक पुरस्कार मिळाले होते. असंघटितांना संघटित करण्यासाठी स्वतःची सुखदुःखे विसरणाऱ्या कार्यकर्ती आणि चळवळीतल्या महिलांची पुढली वाट सुकर करण्याचे धैर्य दाखवणाऱ्या नेत्या म्हणून त्यांची आठवण नेहमीच राहील.

राजवाडे विचारविश्व

'जीर्णोद्धार करण्यासारखे उत्तम काव्य!'

राजवाड्यांनी ज्या काही अज्ञात कवींच्या रचना कमीअधिक प्रमाणात उजेडात आणण्याचे काम केले, त्यांच्यापैकी रामकवीच्या 'प्रदोषव्रतमाहात्मा'चा उल्लेख मागे एका लेखांकात वेगळ्या संदर्भात येऊन गेला आहे. चोंभा कवीच्या कालनिश्चितीसाठी या काव्यातील त्याच्या ज्ञानेश्वरादिकांबरोबरच्या उल्लेखाचा राजवाड्यांनी कसा वापर केला, हे त्या लेखांकात नोंदवले होते. तथापि या काव्याची स्वतंत्र दखल घेणेही आवश्यक आहे. राजवाड्यांनी 'रामकविकृत प्रदोषव्रतमाहात्मय' या शीर्षकाच्या १९१४ साली भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या इतिवृत्तात प्रकाशित केलेल्या लेखात म्हटले होते, 'एकनाथानंतर मुक्तेश्वर, तुकाराम, रामदास, वामनप्रभृति थोर संतकवी झाले, त्याच सुमारास होऊन गेलेल्या रामकवीची गणना मात्र संतांमध्ये केलेली कोठे आढळत नाही. तेव्हा कवी या एकाच नात्याने जे दोनचार ग्रंथकार शंभर वर्षांपाठीमागे महाराष्ट्रात उदयास आले, त्यांच्यामध्ये याची गणना होते. 'प्रदोषव्रतमाहात्म्य' हे याचे एकच काव्य सध्या सापडले आहे. (याची प्रकरणे एकंदर २३ आहेत आणि ओवीसंख्या ३७३३ आहे.) कऱ्हाड येथील काशीनाथ देव यांच्या संग्रहात हे काव्य होते. इतरत्र महाराष्ट्रात या कवीची काव्ये ज्या अर्थी गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत मला सापडली नाहीत, त्याअर्थी हा कवी प्रांतात इतरत्र फारसा माहीत नसावासा दिसतो, तसेच हा कवी कऱ्हाडास किंवा कऱ्हाडच्या आसपास कोठे तरी कृष्णातीरी राहात असावा, असेही अनुमान कऱ्हाडास याचा ग्रंथ सापडला, या बाबीवरून सकृद्दर्शनी करण्याकडे प्रवृत्ती होते...'

राजवाडे पोथी अर्धीमुर्धी असली किंवा संपूर्ण असली, तरी ती ते वाचून काढत व आपल्या टिपणांमधून त्याबद्दलची निरीक्षणेही नोंदवत. 'प्रदोषव्रतमाहात्म्या'बद्दलचे आपले मत नोंदवताना त्यांनी लिहिले की, 'नावावरून प्रथमदर्शनी असा समज होण्याचा संभव आहे की हे प्रकरण पौराणिक कथाभागाचे एखादे ओवीबद्ध सामान्य भारूड असावे, परंतु तसा प्रकार नाही. हे प्रकरण मराठीत जी अनेक उत्तम काव्ये आहेत, त्यांत मोडण्यासारखे आहे... रामकवीच्या या काव्यातून उत्कृष्ट निवडक वेचे देण्याचे हे स्थळ नव्हे, परंतु एवढे सांगितल्यावाचून राहवत नाही की सृष्टिवर्णने व व्यवहारवर्णने या काव्यात फारच कुशलतेने केलेली आहेत, नवरसांचे साधन कवीस आहे...' एवढी प्रशंसा करून न थांबता राजवाड्यांनी पुढे असेही लिहिले की, 'भारत इतिहास संशोधक मंडळास मी अशी शिफारस करण्याची परवानगी घेतो की, हे काव्य मंडळाने प्रसिद्ध केल्यास एका उत्तम काव्याचा जीर्णोद्धार केल्याचे श्रेय त्यास मिळेल...'

'नामदेव व विष्णुदास नामा हे दोघे जातीने शिंपी पडल्यामुळे व दोघेही विठ्ठलभक्त ऊर्फ विष्णुदास पडल्यामुळे त्या दोघांचेही अभंग एकाच व्यक्तीचे समजून छापले गेले आहेत', ही (इतरांकडून घडलेली) गफलत लक्षात आल्यावर राजवाड्यांनी तिच्याबद्दलचा खुलासा केला, तो असा... 'आद्याक्षरांत मंत्र गोवायची सवय मोरोपंताला फार होती, पण त्याच्याहीपूर्वी दोनशे वर्षे विष्णुदास नाम्यालाही हा छंद सूक्ष्मपणे होता, असे दिसते. न अक्षर आद्यस्थानी आणताना नामदेवाचा उल्लेख या विष्णुदास नाम्याने 'नामदेवाचे पवित्र नाम उच्चारी आखंडीत' असा केला आहे. एकनाथकालीन विष्णुदास नामा ज्ञानेश्वरकालीन नामदेवाहून निराळा व दोनअडीचशे वर्षे अलीकडला आहे, या विधानाला खुद्द विष्णुदास नाम्याचीच ही साक्ष उपलब्ध झाली आहे आणि तोही नामदेवाप्रमाणेच जातीने शिंपीच होता, याचे प्रमाण कऱ्हाड येथील एका बाडातील अभंगात सापडले आहे.

'अमंगळु भूमीसी। उगवल्या तुळसी। अपवित्र तयासी। म्हणू नये॥

कागा विष्ठामधी। उगवला पिंपळु। तयासी अमंगळु। म्हणू नये॥

लोखंडाचा वीळा। परिसा लाविला। मागलिया मोला। मांगू नये॥

दासीचिया पुत्रा। राज्यपट आला। मागली उपमा। देऊ नये॥

विष्णुदास नामा। विठ्ठली मिळाला। सिंपी सिंपी त्याला। म्हणू नये॥'...

या विष्णुदास नाम्याची बावनाक्षरी कऱ्हाडास सापडली, तेव्हा हे ध्यानात आले!'

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

एक शून्य शून्य!

विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला काही मिळाले नाही ही बाब कशाहीपेक्षा अधिक महत्त्वाची मानण्याचा आनंद नागपूरने मात्र हिरावून घेतला...

जत्रेत एखाद्या लहानशा रिंगणाचे जे महत्त्व ते आणि तितकेच आपल्या लोकशाही नामे निवडणूक जत्रेत विधान परिषद निवडणुकांचे स्थान. ज्यांची सोय विधानसभेत करता येत नाही वा जे विधानसभेत उतरवण्यास योग्य (की लायक?) नसतात आणि तरीही ज्यांना शांत करण्याची गरज असते अशा व्यक्तींची सोय लावण्याचे स्थळ म्हणजे हे सभागृह. त्या सदनाचे एकंदर स्थानही तसे दुय्यम. अशा विधान परिषदेसाठी झालेल्या निवडणुकांचे महत्त्व ते काय! त्या निवडणुकांचा परीघही लहान आणि त्यांचे परिणामक्षेत्रही मर्यादित. परत मतदार संख्या अगदीच मोजकी. अशा सर्व कारणांमुळे परिषद निवडणुका हा बहुशः एक उपचार असतो. त्यांच्या निकालात ना कोणता कल असतो ना कसली चाहूल. तथापि ग्रामपंचायतीची असो अथवा लोकसभेची; प्रत्येक निवडणूक जिवाच्या आकांताने लढण्याचा नवाच पायंडा भाजपने पाडलेला असल्याने आताच्या निवडणुका आणि मुख्य म्हणजे त्यांचे निकाल चर्चेत आले. त्यात साक्षात पंतप्रधान, गृहमंत्री आदी महारथींनी या निकालांवर समाजमाध्यमी भाष्य केल्याने तेथील उतावीळ अर्धवटरावांसही चेव चढला. वास्तविक देशास महासत्ता बनवण्यासाठी दिवसाचे वीस-वीस तास काम करणाऱ्या आपल्या शीर्षस्थांनी या फुटकळ निवडणुकांवर भाष्य करण्याची गरज होती का, असा प्रश्न काही शहाणे विचारतील. पण सद्यःस्थितीत शहाणपण हे दुर्लक्षाची हमखास हमी देत असल्याने या शहाण्यांच्या प्रतिक्रियांस वळसा घालून या निवडणूक निकालांवर भाष्य करणे योग्य. ते दोन टप्प्यांत करता येईल. देशभरातील निकाल आणि महाराष्ट्राचे चित्र असे हे दोन भाग.

यातील देशाची दखल घेताना माननीय पंतप्रधानांनी काँग्रेसला डिवचले ते अगदी योग्य. एक म्हणजे एकाही ठिकाणी त्यांना विजय मिळवता आला नाही. इतकेच काय कर्नाटकात त्या पक्षाची एकहाती सत्ता असताना तेथेही बेंगळूरुसारख्या ठिकाणी काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. यावरून त्या पक्षनेतृत्वास डिवचून पंतप्रधानांनी त्यांची जागा दाखवून दिली. तथापि तसे करताना पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या यशाविषयी एखादा कौतुकाचा शब्द काढला असता तर बरे दिसले असते. तसेच त्यामुळे काँग्रेस आणि 'सप' यांच्यात दरी निर्माण करण्यासाठी ते कौतुक कामी आले असते. शेवटी या पक्षाचे संस्थापक मुलायमसिंह यांस पद्मविभूषण देण्याचे औदार्य विद्यमान पंतप्रधानांनीच दाखवले होते, हे कसे विसरणार? त्याआधी भले भाजपच्या काही अल्पबुद्धी नेत्यांनी मुलायमसिंह यांच्या मागे 'मुल्ला' ही उपाधी लावण्याचा हुच्चपणा केला असेल. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांना पद्मविभूषण देण्यास मोठेच औदार्य लागते. ते विद्यमान सत्ताधीशांनी दाखवले. त्यामुळेही असेल कदाचित पण 'सप'चा विजय भाजप नेत्यांस तितका टोचला नसणार. उत्तर प्रदेशातील ११ पैकी सहा जागा भाजपने जिंकल्या तर पद्मविभूषण मुलायमसिंह यांचे चिरंजीव अखिलेश नेतृत्व करत असलेल्या समाजवादी पक्षास पाच ठिकाणी यश मिळाले. ज्या उत्तर प्रदेशात लवकरच विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत त्या राज्यातील मुख्य आव्हानवीर 'सप'ने भाजपच्या इतक्या जवळ येणे यात जनसामान्यांस धोका वाटेलही. पण हा पक्ष पद्मविभूषण-प्राप्त मुलायमसिंह-स्थापित असल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वास त्या पक्षाच्या यशाविषयी इतकी असूया वाटली नसणार. त्यापेक्षा काँग्रेसला त्या राज्यात एकही जागा मिळाली नाही, ही बाब जास्त महत्त्वाची. अर्थात काँग्रेसच्या उत्तर प्रदेशी शून्यतेचा आनंद साजरा करताना भ्रष्ट, देशद्रोही इत्यादींचा हा पक्ष पद्मविभूषणमंडित मुलायमसिंह यांच्या 'सप'चा मित्रपक्ष आहे आणि आगामी निवडणुकांत या दोघांत आघाडी होण्याची शक्यता आहे

> **प्रत्येक निवडणूक जिवाच्या आकांताने लढणाऱ्या भाजपला कर्नाटकात चारपैकी, तर बिहारमध्ये आठपैकी तीन जागा मिळाल्या. उत्तर प्रदेशात वाराणसी या पंतप्रधानांच्या मतदारसंघात भाजपला पराभव पत्करावा लागला; हे तपशील भाजपच्या शीर्षस्थांसाठी काँग्रेसच्या पराभवाइतके महत्त्वाचे ठरत नाहीत...**

हा मुद्दा अलाहिदा. काँग्रेसचे शून्यत्व महत्त्वाचे. ते इतके महत्त्वाचे की पुण्यनगरी वाराणसी या साक्षात पंतप्रधानांच्या मतदारसंघात भाजपला पराभव पत्करावा लागला, ही बाबही दुर्लक्ष करावी अशीच. लोकसभेत आधी अयोध्या गेले; विधान परिषदेने वाराणसी नेले यास अजिबात महत्त्व नाही. काँग्रेसला काही मिळाले नाही ही बाब यापेक्षाही अधिक महत्त्वाची.

उत्तर प्रदेशखालोखाल दुसरे महत्त्वाचे राज्य बिहार. माजी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांस भाजपने राज्यसभेवर धाडल्यापासून सत्ताधाऱ्यांची आघाडी जरा डळमळीतच दिसते. अलीकडे विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपचे अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या मतदारसंघात प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाने बलदंड भाजपस धूळ चारली. आणि आता विधान परिषदेतही त्या पक्षाने चांगली कामगिरी नोंदवली. सत्ताधारी संयुक्त जनता दलास मोजका विजय मिळाला. तोही कसाबसा. त्या राज्यातील आठपैकी तीन जागा भाजपला मिळाल्या आणि जनता दल, जनसुराज, लालूंचा राजद या सर्वांस एक तर अपक्षांस दोन ठिकाणी विजय मिळाला. या राज्यातही काँग्रेसचा भोपळा हा सत्ताधाऱ्यांच्या बेतास बात कामगिरीपेक्षाही अधिक महत्त्वाचा. पण खरा आनंदीआनंद आहे तो कर्नाटकात. त्या राज्यातील चारपैकी एकही जागा काँग्रेसला मिळवता आली नाही. उलट त्यांची एक जागा देवेगौडांच्या जनता दलाने खेचून आणली. भाजपने तीन ठिकाणी विजय मिळवला. त्या राज्यातही काँग्रेसचे शून्य अत्याधिक आनंददायी. हा विजय म्हणजे कर्नाटकी जनतेने काँग्रेसला नाकारल्याचे चिन्ह असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. ते खरेच.

परंतु हा आनंद महाराष्ट्राने भाजपस दिला नाही, ही सत्ताधाऱ्यांसाठी मोठी खेदाची गोष्ट असेल. या राज्यातील पाचपैकी विरोधी पक्षीय महाविकास आघाडीने तीन जागा पटकावल्या तर सत्ताधाऱ्यांस दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. किती केंद्रीय यंत्रणा मागे ला(व/)गल्या, फोडाफोडी घड(व)ली, जिल्हा बँका ते साखर कारखाने अशा प्रत्येक ठिकाणी नम(/व)ले तरी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने एक नव्हे तर दोन ठिकाणी विजय मिळवला ही बाब स्थानिक नेतृत्वासाठी फारच क्लेशकारक म्हणायची. पण भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वास शरद पवार यांच्या विजयाचा इतका खेद होणार नाही. कारण मुलायमसिंह यांच्याप्रमाणे शरद पवार यांनाही पद्मविभूषणने गौरवण्याचे औदार्य सत्ताधाऱ्यांनी दर्शवलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचा विजय काही सत्ताधाऱ्यांस सलणार नाही. त्यांना वेदना असेल ती काँग्रेसच्या शून्यावस्थेस महाराष्ट्राने तडा दिला; ही. तोही परत नागपूरसारख्या ठिकाणी. हे म्हणजे जखमेवर केवळ मीठच नव्हे तर तिखट चोळून वरून गरम तेल ओतण्यासारखे. मुख्यमंत्री नागपूरचे, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नागपूरचे आणि यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे भाजपच्या विचार विद्यापीठाचे मुख्य केंद्र आणि कुलपतींचे वास्तव्य नागपुरात. तरीही या शहरातील निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय होतो ही बाब किती वेदनादायी! देशभर अन्यत्र काँग्रेस शून्यावस्थेत असताना त्या पक्षाचा हा शून्यभंग नागपुरात व्हावा हे काही योग्य नव्हे. अयोध्येत पराभव सहन करायचा. वाराणसीत पराभव पचवायचा आणि वर नागपुरातही पराभव चाखायचा हे दुःख किती हे समाजमाध्यमी भाष्य पुसून टाकायची वेळ आलेल्यांनाच कळेल!

त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब हीच की ज्यांना पद्मविभूषणने गौरवले गेले त्यांच्या पक्षाचे तरी भले झाले. असो. बाकी या विधान परिषद निवडणुकांचे निकाल काँग्रेससाठी 'एक- शून्य शून्य' असेच म्हणायचे. महाराष्ट्राने- त्यातही नागपूरने- हात दिला. अन्यथा शून्यच.

स्वयं-पुनर्विकासाची अशी अडवणूक थांबावी!

लेख

संजय केळकर
आमदार, ठाणे शहर विधानसभा मतदारसंघ

> **'क्लस्टर'खेरीज पुनर्विकास अशक्य करणाऱ्या अटी ठाण्यासारख्या शहरात घालायच्या; पण सामूहिक क्षेत्रफळाच्या अटीत न बसणाऱ्या हाउसिंग सोसायट्यांना यातून वगळून- त्यांच्या स्वयं-पुनर्विकासाला सवलती न देता उलट एक-दीड कोटी रुपयांनी त्यांचे नुकसान करायचे, हे राज्याचे धोरण नाही आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री असतानापासून 'स्वयं-पुनर्विकासा'च्या केलेल्या पाठराखणीशीही ते सुसंगत नाही. त्यामुळे आता तरी नियमावर बोट ठेवून अडवणूक करण्यापेक्षा, नियमांत ठोस बदल हवा...**

महाराष्ट्र राज्याचे लघुरूप ठाणे आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (एमएमआरडीए) ठाणे शहर आणि जिल्ह्याचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. ठाणे महानगरीय तसेच शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण असे संमिश्र आहे. ठाण्यातील बहुतेक सर्व नागरी विषय, प्रश्न हे राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. यातील कळीचा मुद्दा पुनर्विकास आणि स्वयं-पुनर्विकास हा आहे. ठाणे शहर आणि जिल्ह्यातील पुनर्विकास आणि स्वयं-पुनर्विकास लालफितीच्या कारभारातून सुटल्यास राज्यातील पुनर्विकास आणि स्वयं-पुनर्विकास यांची वाट विस्तारेल. ठाणे शहर वेगाने विस्तारत आहे. मेट्रो, रिंग रोड, कोस्टल रोड आणि इतर भव्य पायाभूत प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. शहराच्या भविष्यासाठी मोठे नियोजन केले जात असतानाच, दुसऱ्या बाजूला ठाण्यातील हजारो जुन्या आणि धोकादायक इमारती व वसाहती आजही पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाणेकरांसमोर एक थेट आणि कळीचा प्रश्न निर्माण होतो. शहराचा बाह्य विकास इतक्या वेगाने होत असताना, जुन्या ठाण्याचा पुनर्विकास आणि स्वयं-पुनर्विकास अपेक्षित वेगाने का होत नाही? हा विकास नेमका कोण आणि कसा रोखत आहे? हा प्रश्न केवळ एखाद्या शहरातल्या सिमेंट-काँक्रीटच्या नव्या इमारतींचा नाही; तर तो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा, हक्काच्या मालमत्तेचा, मूलभूत नागरी सुविधांचा आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा प्रश्न आहे.

'मिनी क्लस्टर'चा पर्यायही हवा

ठाणे महापालिकेने जुन्या इमारतींचा एकत्रित कायापालट करण्यासाठी क्लस्टर (समूह विकास) ही योजना पुढे आणली आहे. महापालिकेने एकंदर पन्नास नागरी पुनरुत्थान आराखडे (अर्बन रिन्यूअल प्लॅन- यूआरपी) तयार केले असून, सप्टेंबर २०२६ पर्यंत त्यापैकी १२ आराखड्यांना मान्यता मिळाली आहे. यामध्ये लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, चरई आणि ठाणे स्थानकालगतच्या परिसराचा समावेश आहे.

परंतु ठाण्यातील प्रत्येक इमारतीसाठी क्लस्टर हा एकमेव उपाय ठरू शकत नाही. जुन्या ठाण्यात मोठ्या प्रमाणावर जागा उपलब्ध नसल्याने, क्लस्टरसाठी आवश्यक असलेल्या क्षेत्रफळाची अट शिथिल करून 'मिनी क्लस्टर' संकल्पनेला परवानगी देणे गरजेचे आहे. यामुळे अनेक छोट्या सोसायट्या एकत्र येऊन स्वयं-पुनर्विकासाच्या माध्यमातून क्लस्टर योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

विद्यमान सरकारचे धोरण

स्वयं-पुनर्विकासाचे महत्त्व ओळखून देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमपासूनच या संकल्पनेला अतिशय भक्कम पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या या भक्कम पाठिंब्यामुळेच आणि दूरदृष्टीमुळे १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्वयं-पुनर्विकासाचा ऐतिहासिक शासन निर्णय (जीआर) लागू झाला. यामध्ये सोसायट्यांना १० टक्के अतिरिक्त मोफत एफएसआय (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स), 'टीडीआर'च्या (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स) प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत आणि परवानग्यांसाठी 'एक खिडकी योजना' असे अत्यंत दिलासादायक निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतले. मात्र, प्रशासनातील काही आडमुठ्या अधिकाऱ्यांमुळे आणि लालफीतशाहीमुळे या कल्याणकारी निर्णयाला केराची टोपली दाखवली जात आहे. नगरविकास विभागाचे अधिकारी केवळ तांत्रिक कारणे पुढे करत आहेत की, २०१९ च्या या 'जीआर'चा 'यूडीसीपीआर'मध्ये अधिकृतपणे समावेश झालेला नाही. वास्तविक 'यूडीसीपीआर' म्हणजे 'युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अ‍ॅण्ड प्रमोशन रेग्युलेशन्स' अर्थात 'एकत्रीकृत विकास नियंत्रण वा प्रोत्साहन नियमावली'च्या व्यापक हेतूचा विचार केल्यास स्वयं-पुनर्विकासाची या प्रकारे अडवणूक करणे योग्य ठरेल का?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या नेतृत्वाने स्वयं-पुनर्विकासाला भक्कम बळ देऊनही, नोकरशाहीच्या उदासीनतेमुळे हा शासन निर्णय अद्याप फायलींमध्ये अडकून पडला आहे. बिल्डरांच्या दावणीला न बांधता स्वतःच्या इमारतीचा स्वतः विकास करणे म्हणजेच 'स्वयं-पुनर्विकास'. हा ठाण्यातील मध्यमवर्गीय सोसायट्यांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित आणि स्वाभिमानाचा मार्ग आहे. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री असतानाही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वयं-पुनर्विकासाचे महत्त्व ओळखून या संकल्पनेला अतिशय भक्कम पाठिंबा दिला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि पुढाकारामुळे १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्वयं-पुनर्विकासाचा ऐतिहासिक शासन निर्णय (जीआर) लागू झाला. तेव्हापासून आजवर, १० टक्के अतिरिक्त मोफत प्रोत्साहनपर एफएसआय, टीडीआर प्रीमियममध्ये ५० टक्क्यांची भरघोस सवलत आणि परवानग्यांसाठी सहा महिन्यांची 'एक खिडकी योजना' आणि व्याज अनुदान स्वयं-पुनर्विकाससाठी लागू आहे. या क्रांतिकारी धोरणाचे आणि निर्णयांचे जितके स्वागत व कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती भक्कम असतानाही, दुर्दैवाने प्रशासकीय पातळीवर या धोरणाला केराची टोपली दाखवली जात आहे. विशेषतः नगरविकास विभाग आणि विशेषतः ठाण्यात स्थानिक महापालिकेतील नोकरशाहीने लालफीतशाहीची पकड अधिक घट्ट आवळली आहे.

अधिकाऱ्यांचा तांत्रिक युक्तिवाद कागदोपत्री बिनचूक आहे. 'यूडीसीपीआर' २०२० पासून मंजूर झाला, त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. क्लस्टर स्वयं-पुनर्विकास आणि 'मिनी-क्लस्टर'ला या सवलती लागू करणे यांसाठी आवश्यक असणारी किरकोळ सुधारणा अधिसूचना (स्टॅच्युटरी नोटीस ऑफ मॉडिफिकेशन) वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवून नगरविकास खात्याच्या उदासीनतेमुळे स्वयं-पुनर्विकास रोखला जात आहे.

कोट्यवधींचा अवाजवी भुर्दंड

नोकरशाहीच्या या तांत्रिक पेचामुळे स्वयं-पुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या सोसायट्यांना नाहक कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. उदाहरणार्थ, ठाणे-पाचपाखाडी भागातील गुरुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेवर २.१७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त भार, तर ठाणे विकास स.गृ.संस्था या सोसायटीचे २.१४ कोटी रुपये अतिरिक्त नुकसान; कळवा भागातील जीवनग्राम स.गृ.संस्थेचे २.७५ कोटी रुपये नुकसान; वागळे इस्टेट भागातील प्रसाद सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला १.१६ कोटी रुपयांचा भुर्दंड; ठाणे पूर्व भागातील साई धाम आणि गंगा भास्कर सहकारी गृहनिर्माण संस्था या दोन्ही सोसायट्यांचे प्रत्येकी १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान!

उदाहरणादाखल येथे मांडलेल्या, या सहा सोसायट्यांमधील २४० मध्यमवर्गीय कुटुंबांना नोकरशाहीच्या अडेलतट्टूपणामुळे १०.५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अवाजवी भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या प्रशासकीय अडथळ्यांविरुद्ध विधिमंडळात विशेष लक्षवेधी सूचना आणून दोषी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाईल. तसेच नगरविकास विभागाने एमआरटीपी कायद्याच्या (महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६) कलम १५४ अंतर्गत सर्व महापालिकांना तात्काळ निर्देश द्यावेत, अशी ठाम मागणी आहे. यासोबतच 'हाऊसिंग सोसायटीज असोसिएशन'मार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिकाही दाखल केली जात आहे. असे असतानाही, पाचपाखाडी येथील गुरुकुल सोसायटीने स्वयं-पुनर्विकासाचा लढा पुढे नेला असून, ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेला त्यांचा भूमिपूजन सोहळा हा लालफितीविरुद्ध नागरिकांच्या विजयाचे प्रतीक ठरला आहे.

स्वयं-पुनर्विकासाचे लाभ का नाकारता?

अनेक बिल्डर आर्थिक क्षमता नसताना प्रकल्प हाती घेतात आणि ते अधांतरी सोडतात (ठाण्यातील एक उदाहरण म्हणजे, चरईतील सहजीवन सोसायटीचा २०१९ पासून रखडलेला प्रकल्प). त्यामुळे विकासकांवर विसंबून राहणे धोक्याचे ठरत आहे. याउलट, स्वयं-पुनर्विकासामुळे संस्थांना जमिनीची १०० टक्के मालकी, जास्तीत जास्त चटईक्षेत्र (कार्पेट एरिया) आणि विक्रीयोग्य सदनिकांमधून मिळणारा नफा मूळ सभासदांना मिळतो. तसेच ठाण्यात रिंग मेट्रो आणि कोस्टल रोडचे काम सुरू असताना (उदा. वसंत विहार, नाथ पै रोड परिसर), चुकीच्या नियोजनामुळे वृक्षतोड व रहिवाशांच्या समस्या वाढत आहेत. क्लस्टर किंवा खासगी पुनर्विकास असो, उंच इमारती उभ्या राहिल्यानंतर त्यांना लागणारा पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, पार्किंग आणि रस्ते रुंदीकरण यावर ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे.

ठाणे शहराच्या संदर्भात, पण महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी तातडीचा असा हा प्रश्न आहे हे ओळखून राज्याच्या नगरविकास विभागाने तातडीने परिपत्रक काढून २०१९ च्या स्वयं-पुनर्विकास धोरणातील ५० टक्के टीडीआर सवलत व १० टक्के एफएसआयचा समावेश 'यूडीसीपीआर'मध्ये करावा. सोसायट्यांचे स्वयं-पुनर्विकास प्रस्ताव सहा महिन्यांच्या आत मंजूर करणारी डिजिटल आणि पारदर्शक प्रणाली कार्यान्वित करावी. महत्त्वाचे म्हणजे, 'मिनी क्लस्टर' या संकल्पनेला मान्यता देऊन (म्हणजेच क्लस्टरसाठी किमान १० हजार चौरस मीटरच्या क्षेत्रफळाची) अट शिथिल करून छोट्या सोसायट्यांना एकत्र येऊन स्वयं-पुनर्विकासाची संधी द्यावी.

ठाण्याचा अथवा कोणत्याही शहराचा विकास म्हणजे केवळ रिंग रोड किंवा उड्डाणपूल बांधणे नव्हे; तर ज्या घरात सामान्य ठाणेकर आयुष्यभराची पुंजी लावून राहतो, ते घर सुरक्षित करणे हाच खरा शहरविकास आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या धोरणाची नगरविकास खात्याने प्रामाणिक अंमलबजावणी केल्यास, क्लस्टर आणि स्वयं-पुनर्विकासामार्फत सामान्य ठाणेकराचे हक्काच्या घराचे स्वप्न नक्कीच पूर्ण होईल!

अन्वयार्थ

स्पेनमधील रेल्वे अपघाताचा धडा

स्पेनच्या परिवहन मंत्र्याने गेल्या जानेवारीत झालेल्या रेल्वे अपघातानंतर सर्वांना आश्वस्त केले होते, की अशा प्रकारचा अपघात पुन्हा होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. या विधानानंतर नऊ महिन्यांतच स्पेनमध्ये दुसरा भीषण रेल्वे अपघात झाला. दोन्ही अपघातांचे स्वरूप जवळपास सारखेच. दोन्ही अपघात द्रुतगती रेल्वेंचे. जानेवारीतील



अपघातांत रुळांवरून घसरलेल्या एका रेल्वेवर दुसरी वेगवान रेल्वे येऊन आदळली. परवाच्या अपघातात रुळांवर उभ्या असलेल्या रेल्वेस मागून एका रेल्वेने धडक दिली. या दोन्ही अपघातांतील रेल्वे कंपन्याही त्याच आहेत. अशा प्रकारच्या अपघातांत तिसऱ्या जगातल्या देशांची 'मक्तेदारी' असल्याचे मानण्याचा प्रघात आहे. तो स्पेनसारख्या विकसित देशात झाल्याने नाही म्हटले तरी अनेकांच्या भुवया वर गेल्या. या अपघाताविषयी येत असलेल्या समाजमाध्यमी प्रतिक्रियांतूनही, युरोपीय महासंघात असे कसे काय घडू शकते, असा प्रच्छन्न प्रश्न दिसतो.

या दुर्घटनेची काही प्राथमिक कारणे पुढे आली आहेत. एक रेल्वे रुळावर उभी होती. तिला संगणकीय समस्येमुळे पुढे जाता येत नव्हते. अशा परिस्थितीत त्या रुळावर मागून येणाऱ्या रेल्वेंना तसा संदेश जायला हवा. तो गेला नाही. उलट रेल्वे 'सर्वसाधारण' वेगाने - म्हणजे सुमारे २०० किमी प्रति तास - धावू दे, असे नियंत्रणकक्षातून रेल्वेचालकांस सांगण्यात आले. यातून दिसते, की मानवी आणि तांत्रिक चूक या दोन्हींचा हा परिणाम आहे. हे का व कसे घडले हा पुढच्या तपासाचा प्रश्न. एखादी मोठी घटना, दुर्घटना घडते, तेव्हा त्यांचा नेमका अर्थ लावणे हे अनेकांच्या क्षमतेपलीकडचे असते. त्या घटनांचे काही तरी साधे, भावनांचे समाधान करील असे स्पष्टीकरण त्यांना हवे असते. चिंता आणि भयमुक्ती हवी असते. कटकाल्पनिका जन्मतात त्या या गरजेतून. या अपघाताबद्दलचा सध्याचा एक लोकप्रिय षड्यंत्र सिद्धांत आहे तो 'सायबर युद्धा'चा आणि त्यात इस्रायलचा हात असल्याचे सांगण्यात येते. स्पेन आणि इस्रायलमधील ताणलेले संबंध, या अपघातातील सरकारी रेल्वेकंपनीने इस्रायलच्या एका माजी गुप्तचराशी संबंधित असलेल्या कंपनीस दिलेले सुरक्षासेवा कंत्राट अशी काही टिंबे जोडून हे कटकाल्पनिकेचे चित्र तयार केले जात आहे. त्यात किती तथ्य हे कालांतराने कळेलच. पण आजचे जग हे कृत्रिम प्रज्ञेचे आहे. सायबर युद्ध हा अनेक देशांच्या रणनीतीचा प्रमुख भाग बनलेला आहे. असे असताना या अशा बाबी दुर्लक्षिता येत नसतात.

आणि म्हणूनच या अपघाताने दिलेल्या धड्यांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. आपल्याकडे सध्या बुलेट ट्रेनचे काम कासवगतीने सुरू आहे. तशा प्रकारच्या आणि खरे तर मुंबई-अहमदाबाद या 'आता सुरू - आता संपला' अशा मार्गावरच्या अतिद्रुतगती रेल्वेची आवश्यकता काय, हा वेगळा मुद्दा. त्याची आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिकही गणिते हा भाग वेगळा. येथे प्रश्न बंदुकीच्या गोळीइतक्या वेगाचा आहे. तो झेपण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा, यंत्रणा, कौशल्य आणि त्या यंत्रणांची सुरक्षा हा खरा चिंतेचा घटक आहे. याच आठवड्यात मुंबईत झालेला 'लोकल-राडा' सर्वांनी पाहिला. २०११ मध्ये आपल्याकडे रेल्वे धडकरोधक यंत्रणेवर काम सुरू झाले. पुढे त्याचे 'कवच' असे छानसे नामांतर झाले. ही 'स्वयंचलित रेल्वे सुरक्षा' प्रणाली अद्याप सर्व रेल्वे मार्गांवर आलेली नाही. याची कारणे आर्थिक असोत वा अन्य काही. यातून दिसतो तो रेल्वे सुरक्षेबाबतचा आपला दृष्टिकोन. या अशा सुरक्षा यंत्रणा संगणकाधारित असतात. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा हा पुन्हा एक वेगळा मुद्दा. कृत्रिम प्रज्ञेच्या विकास आणि विस्तारामुळे या सुरक्षेची शंभर टक्के खात्री तर कोणासही देता येणार नाही. आणि त्यामुळेच अतिवेगवान प्रवास हा द्रुतगती मार्गावरील त्या 'अति घाई - संकटात नेई' या सुविचारास प्रत्यक्षात आणणारा तर ठरणार नाही ना, अशी शंका निर्माण होते.

प्रगतीसाठी वेग हवा, हे खरे. पण तो किती? त्याची मर्यादा काय? पुरेसा वेग म्हणजे काय? त्याचा वृथा हव्यास कशाला म्हणावयाचे, असे काही प्रश्न एकदा धोरणकर्त्यांनीच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांनीही गांभीर्याने घ्यायला हवेत. स्पेनच्या अपघाताचा हा मुख्य धडा आहे.

मायक्रोफायनान्स कंपन्यांमुळे दुष्काळग्रस्तांची होरपळ वाढली?

विश्लेषण

सुहास सरदेशमुख
suhas.sardeshmukh@expressindia.com

> **ग्रामीण अर्थकारण दुष्काळाने थिजले असताना लघुवित्त कंपन्यांचे चढे व्याजदर आणि हप्तेवसुलीची हडेलहप्पी, अशा परिस्थितीत आत्महत्या करण्यापर्यंत पावले उचलली जात आहेत...**

मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचीच चर्चा का?

नांदेडमध्ये एका मायक्रोफायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात शेतकऱ्याचा मृतदेह आढळला. इतके दिवस ग्रामीण भागात सोयाबीन काढणी, कापूस वेचणीची कामे थोड्या प्रमाणात का असेना उपलब्ध होती. आता तीही शिल्लक न राहिल्याने मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचा आठवड्याचा हप्ता कसा द्यायचा, अशी विवंचना गावोगावी वाढू लागली आहे. यातून आतापर्यंत चार जणांनी आत्महत्या केली आहे. त्यांत हिंगोलीमधील एक महिला आहे. परभणीतील एका शेतकऱ्याने १० हजार रुपयांच्या तगाद्यापोटी आत्महत्या केली. लातूरमध्ये एका गवंडीकामही करणाऱ्या शेतमजुराने आत्महत्या केली. त्याच्यावर वेगवेगळी कर्जे होती. यामुळे मायक्रोफायनान्सच्या कार्यप्रणालीवर आणि वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाऊ लागले आहे.

कामाची पद्धत आणि व्याजदर कसे असतात?

ज्या व्यक्तीची बँकांमध्ये पत नाही आणि कर्जाची निकड तर आहे, अशा व्यक्ती मायक्रोफायनान्सकडून कर्ज घेतात. आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि कर्ज घेणाऱ्या १० महिलांनी एकमेकींच्या कर्जहप्त्यास जामीन राहायचे, अशी अट कंपन्यांकडून टाकली जाते. सर्वसाधारणपणे एक ते दीड लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. कर्ज देताना एका जाड कागदावर कर्जाचे हप्ते कसे घेतले जाणार, हे नोंदवलेले असते. तसेच कर्जदार महिला सदस्यांच्या कर्जावर प्रक्रिया शुल्क आकारले जाते आणि त्यावर एकूण १८ टक्के वस्तू व सेवाकर लावला जातो. मराठवाड्यासह विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये दक्षिणेत मुख्यालय असणाऱ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांची मोठी संख्या आहे. एका कर्जावर २६ ते २८ आणि काही वेळा ३० टक्केही व्याजदर आकारला जातो. कष्टकरी, ऊसतोडणी कामगार, शेतमजूर, बांधकाम मजूर, तसेच अल्पभूधारक शेतकरी कर्ज घेतात. ज्याच्या मजुरीतून १२०० ते १५०० रुपये आठवड्याला मिळू शकतात, अशा व्यक्तींना हे कर्ज आवर्जून दिले जाते.

कर्जव्यवस्था किती खोलवर? नियंत्रण कोणाकडे?

बचत गटामध्ये स्वतःची बचत असते. त्यामुळे स्वयंसहायता गट सुरू करण्यासाठी सरकारही प्रयत्न करते. पण, बहुतांश बचत गट आणि मायक्रोफायनान्स यात आता अशी काही सरमिसळ झाली आहे, की मायक्रोफायनान्स कंपन्या याच जणू बचत गटाचेच काम करत आहेत, असे भासवले जाते. या कंपन्यांचा हप्ता आठवड्याला असल्याने मजुरांना पैसे परत करणे सोपे होते. पण कमालीचा व्याजदर असल्याने महिला कर्ज फेडूच शकत नाहीत. कर्ज कमी होताच, नवे कर्ज मंजूर करून देऊ, असे आमिष दाखवले जाते. यामुळे एक महिला कधी दोनदा, तर कधी तीनदा कर्ज घेते. काही वेळा वेगवेगळ्या दोन कंपन्या एकाच महिलेस कर्ज देतात. बीड जिल्ह्यातील काठवडा गावातील एका महिलेने, ऊसतोडणीला जाण्यापूर्वी गर्भपिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रियेसाठीही कर्ज घेतले होते. आजारपण, रुग्णालयाचा खर्च हीदेखील कर्जाची कारणे. अनेकदा लाडक्या बहिणीचा हप्ता मायक्रोफायनान्सकडे वर्ग केला जातो. विशेष म्हणजे एखाद्या गावात किती कर्जवितरण झाले आहे किंवा राज्यातील मायक्रोफायनान्सची संख्या किती, असा तपशील जिल्हाधिकारी पातळीवर उपलब्ध नाही; कारण या लघुवित्त कंपन्याचे नियंत्रण भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे असते.

आत्महत्यांचा विळखा वाढणार?

नांदेड जिल्ह्यात सक्तीच्या कर्जवसुलीच्या कारवाईत मुदखेड तालुक्यातील चंद्रकांत दगडूजी शिंदे (वय ४०) या तरुण शेतकऱ्याचा बळी गेल्यानंतर मागील दोन दिवसांत पोलीस दप्तरी खालसा फायनान्स या खासगी संस्थेचा उल्लेख झाला होता; परंतु या प्रकरणात कुबेरफल (केएफ) एंटरप्रायजेस या संस्थेचे नाव आता पुढे आले आहे. तर परभणीतील शेतकरी लहू माणिक लाडाने यांच्याकडे मायक्रोफायनान्स कंपनीचे २ लाख रुपयांचे कर्ज होते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आणि उत्पन्नाचे साधन नसल्याने दर आठवड्याला व्याजाची रक्कम भरणे त्यांना अशक्य झाले होते. शेतात लिंबाच्या झाडाला दोरीने गळफास घेऊन त्यांनी आत्महत्या केली. कर्ज परत केले नाही तर मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून वसुलीस येणारे तरुण दिवसभर घरात बसून राहतात. ज्या महिलेचा हप्ता चुकला तो अन्य सदस्यांना स्वखर्चातून द्यावा लागतो. रक्कम मिळाल्याशिवाय ही मंडळी गाव सोडत नाहीत. यामुळे मायक्रोफायनान्सचा विळखा फास आवळणारा ठरू लागला आहे. या अनुषंगाने 'लोकसत्ता'मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर राज्य पातळीवर नियंत्रणासाठी समिती नेमण्याची मागणी मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली आहे.

मानव की बहुमुखी भावनाओं का प्रबल प्रवाह जब रोके नहीं रुकता, तब वह कला के रूप में फूट पड़ता है।

- रस्किन

मतदाता का हक

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया जिस तरह अपने शुरुआती दौर से ही कई स्तर पर विवादों के घेरे में रही है, उसके मद्देनजर यह जरूरी है कि इस मसले पर एक ठोस स्पष्टता कायम हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक भी पात्र मतदाता वोट देने के हक से वंचित न हो। विडंबना यह है कि निर्वाचन आयोग की ओर से जब से एसआइआर के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में अभियान चलाया जा रहा है, तभी से इसे लेकर कोई न कोई विवाद उभरते रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से इसकी पारदर्शिता और मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अपात्र होने के तर्क पर मतदाता सूची में लोगों के नाम शामिल करने या उससे हटाने के मसले पर अब तक कोई स्पष्टता कायम नहीं हो सकी है। जब भी एसआइआर की किसी खामी पर सवाल उठाए जाते हैं, तो निर्वाचन आयोग की ओर से कोई नया समाधान पेश कर दिया जाता है। जबकि कई मौकों पर आयोग का फरमान कठघरे में पाया गया है।

दरअसल, दिल्ली में एसआइआर के क्रम में ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए वैसे मतदाताओं को भी फार्म 6 भर कर नए सिरे से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने को कहा गया, जिनका नाम पहले की सूची में था। जबकि फार्म 6 वैसे लोगों के लिए निर्धारित है, जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। समझना मुश्किल है कि ऐसा करने के पीछे आयोग की क्या मंशा है। इस मसले पर दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से यह पूछा कि पहले से मतदाता रहे लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आने पर उनसे फार्म 6 क्यों भरवाया जा रहा है, जबकि यह सिर्फ नए मतदाताओं के लिए है। गौरतलब है कि दिल्ली में हुए एसआइआर के क्रम में जब ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आई, तो उसमें से करीब सैंतालीस लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। इनमें करीब तैंतालीस लाख लोगों को स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित और लगभग दो लाख को मृत बताया गया। मगर विचित्र यह है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से अपना नाम हटाने के विरुद्ध दावा किया, उनके सामने नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने का विकल्प रखा गया।

सवाल है कि पहले से मतदाता रहे किसी व्यक्ति के सामने नए वोटर के रूप में नाम शामिल किए जाने के बाद अगर भविष्य में तकनीकी रूप से कोई समस्या खड़ी होगी, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ड्राफ्ट सूची में नाम न होने के बाद कोई व्यक्ति दस्तावेजों के साथ अपने पहले से मतदाता होने की सूचना देने की कोशिश करे, तो उसे नए मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए कैसे कहा जा सकता है? नोटिस का जवाब देने में देरी की कई वजहें हो सकती हैं। मगर क्या इसके एवज में व्यक्ति से मतदाता होने का अधिकार हमेशा के लिए छीना जा सकता है? सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने भी इसे 'संरचनात्मक असंगति' बताया और इसे दूर करने की जरूरत बताई। इसके अलावा भी एसआइआर की प्रक्रिया में व्यापक खामियां सामने आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरणों में दावे के बाद नब्बे फीसद से ज्यादा लोगों के नाम फिर से मतदाता सूची में बहाल किए गए। यह किसकी लापरवाही और गड़बड़ी का नतीजा था? ध्यान रखने की जरूरत है कि महज तकनीकी जटिलताओं में उलझा कर पात्र लोगों के नाम भी मतदाता सूची से बाहर किए गए, तो इससे देश के लोकतंत्र के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी होगी।

कथनी और करनी

राजनीति में विपक्ष और सत्ता की भाषा का फर्क नया नहीं है, पर दिल्ली में आनलाइन शराब बिक्री को बढ़ावा देने की तैयारी इस फर्क को थोड़ा ज्यादा साफ करती है। दिल्ली में तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति में वेबसाइट और ऐप के जरिए शराब की उपलब्धता का प्रावधान था। तब भाजपा ने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा और भ्रष्टाचार का जरिया बताया था। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, घोटाले के आरोप लगे और नीति को 'पाप' तक कहा गया। आज खुद भाजपा सत्ता में है और वही व्यवस्था उसे सुविधाजनक लगने लगी है। अब सत्ता में आने के बाद भाजपा का तर्क है कि यह सिलसिला पिछली सरकार ने शुरू किया था। सवाल है कि जिस नीति पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जिसे वापस लिया गया था, उसी से अब उसे इतना लगाव क्यों दिखने लगा है? पुरानी सरकार की किसी नीति को अगर अवांछित या गलत माना जाता है, तो उसे बदलना या रोकने की जिम्मेदारी नई सरकार की होती है। कोई नीति 'पहले से लागू है' जैसी दलील दरअसल जवाबदेही से पलायन है।

यह विरोधाभास दिल्ली तक सीमित नहीं है। पंजाब जैसे राज्य में नशे की समस्या राजनीतिक विमर्श का बड़ा विषय रही है। वहां नशे के खिलाफ अभियान और सरकारों की जवाबदेही पर जोर देने वाले दलों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे शराब की उपलब्धता और उसके सामाजिक प्रभावों पर समान कसौटी अपनाएं। नशे के खिलाफ चिंता विपक्ष में रहते हुए ही नहीं, सत्ता में आने के बाद भी दिखनी चाहिए। जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है, वहां उसके नेता नशे के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और युवाओं को नशामुक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जहां सरकार अपनी है, वहां शराब की आसान उपलब्धता पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं। फैसले सरकार के होते हैं, पर संगठन की चुप्पी बताती है कि सिद्धांत सुविधा देखकर तय होते हैं। शराब की आनलाइन बिक्री से उपजी आशंकाएं काल्पनिक नहीं हैं। राजनीति में रुख बदलना नई बात नहीं, लेकिन इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। विपक्ष में रहते हुए नैतिकता को मुद्दा बनाना और सत्ता में आने पर राजस्व की दुहाई देना दरअसल कथनी और करनी के फर्क को ही दर्शाता है।

शोध और नवाचार से संवरेगा भविष्य



भारत को वैश्विक तकनीकी शक्ति बनाने के लिए शोध एवं विकास में निवेश बढ़ाना, शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और शोधकर्ताओं को संसाधन व स्वतंत्रता देना अनिवार्य है।

रंजना मिश्रा

इक्कीसवीं सदी में किसी देश की ताकत का आकलन केवल उसकी अर्थव्यवस्था के आकार, सैन्य क्षमता या आबादी से नहीं, बल्कि ज्ञान-विज्ञान, मौलिक शोध और तकनीकी नवाचार में उसकी उपलब्धियों से भी होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसी तकनीकें वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रही हैं। इनका असर राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आम आदमी के जीवन तक दिखाई देता है। ऐसे में भारत को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शोध और नवाचार को विकास की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान देना होगा।

भारत की उपलब्धियां इस दिशा में उम्मीद जगाती हैं। मगर सवाल है कि क्या इस प्रतिभा को मौलिक खोजों और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के लिए अवसर मिल रहे हैं? मोबाइल फोन से लेकर आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, सेमीकंडक्टर और रक्षा तकनीक तक अनेक क्षेत्रों में भारत अब भी विदेशी तकनीक, उपकरणों और घटकों पर निर्भर है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद कई महत्त्वपूर्ण तकनीकों के विकास में आत्मनिर्भरता हासिल करना बाकी है। रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी प्रणालियों की प्रगति के साथ कुछ जटिल उपकरणों और तकनीकों के लिए विदेशी निर्भरता बनी हुई है। यह स्थिति बताती है कि तकनीक का इस्तेमाल करने और उसका मौलिक विकास करने के बीच बड़ा अंतर है। कोई देश दूसरे की तकनीक अपनाकर आर्थिक प्रगति तो कर सकता है, लेकिन दीर्घकालीन नेतृत्व के लिए उसे अपने ज्ञान और शोध की बुनियाद मजबूत करनी ही होगी।

भारत में अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7 फीसद खर्च किए जाने का अनुमान लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। इसके मुकाबले दक्षिण कोरिया और इजरायल जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था का कहीं अधिक हिस्सा शोध पर लगाते हैं। चीन और अमेरिका भी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। अलग-अलग देशों के आंकड़ों और उनकी गणना-पद्धतियों में अंतर हो सकता है, लेकिन साफ है कि भारत को शोध में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। विशाल आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास संबंधी जरूरतों वाले देश के लिए शोध पर एक फीसद से कम खर्च पर्याप्त नहीं है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उद्योग जगत अनुसंधान एवं विकास पर बड़ी रकम खर्च करता है, क्योंकि नई तकनीक वहां प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और बाजार में टिके रहने का आधार है। भारत में भी कुछ कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन समग्र रूप से निजी निवेश और उद्योगों की शोध क्षमता को और मजबूत करने की जरूरत है। तैयार तकनीक आयात करना या विदेशी कंपनियों से समझौते कर लेना कई बार व्यावसायिक रूप से आसान होता है, लेकिन इससे घरेलू मौलिक शोध को अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिलता। उद्योगों को विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के साथ मिलकर दीर्घकालीन परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए।

शोध की कमजोर बुनियाद का एक बड़ा कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था भी है। वैज्ञानिक सोच का विकास प्रयोगशालाओं से पहले कक्षाओं में होता है, जहां



बच्चों में सवाल पूछने, तर्क करने और किसी बात को प्रमाण के आधार पर परखने की प्रवृत्ति विकसित की जानी चाहिए। मगर शिक्षा का बड़ा हिस्सा अब भी पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षाओं में अधिक अंक लाने तक सीमित रह जाता है। विज्ञान की पढ़ाई में प्रयोगों और व्यावहारिक गतिविधियों की कमी बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को सीमित कर देती है। जब किसी विद्यार्थी को किसी घटना के पीछे का कारण समझने के बजाय केवल परिभाषा याद करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, तो उसमें मौलिक सोच विकसित करना कठिन होगा।

> **भारत के पास युवा आबादी, व्यापक वैज्ञानिक आधार और बड़ी घरेलू अर्थव्यवस्था जैसी महत्त्वपूर्ण ताकतें हैं। जरूरत इनका इस्तेमाल दूरदर्शी शोध नीति के साथ करने की है। सरकार को अनुसंधान पर निवेश बढ़ाने, निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने, स्कूली शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और विश्वविद्यालयों को शोध के अनुकूल संसाधन देने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल देश में वस्तुओं का उत्पादन करना नहीं, बल्कि उन तकनीकों और ज्ञान का विकास करना भी है, जिन पर भविष्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा निर्भर करेगी। भारत को यदि मजबूत और प्रभावशाली बनना है, तो उसे तकनीक का बड़ा उपभोक्ता बने रहने से आगे बढ़कर उसका निर्माता और मौलिक ज्ञान का सृजक बनना होगा।**

इसके अलावा, अनेक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं, आवश्यक उपकरणों और पर्याप्त शोध-वित्त की कमी है। शिक्षकों के रिक्त पद, संसाधनों का असमान वितरण और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बोझ भी शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसका असर उन विद्यार्थियों पर अधिक पड़ता है, जिनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए अवसरों और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां देना नहीं, बल्कि ज्ञान का विस्तार करना, समस्याओं के समाधान खोजना और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करना भी है।

समाज में सफलता की प्रचलित परिभाषा भी इस चुनौती को बढ़ाती है। अक्सर किसी युवा की उपलब्धि को उसकी नौकरी, पद और वेतन से मापा जाता है। समस्या तब पैदा होती है, जब शोध और अकादमिक करिअर को अनिश्चित, कम आकर्षक या कम प्रतिष्ठित समझा जाने लगता है। प्रतियोगी परीक्षाओं और कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता भी कई बार सीखने की प्रक्रिया को सीमित करके उसे प्रश्न हल करने और अंक जुटाने तक ले आती है।

शोध संस्थानों की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार भी आवश्यक है। वैज्ञानिकों और शोधार्थियों का समय अनुदान संबंधी जटिल प्रक्रियाओं, खरीद की लंबी औपचारिकताओं और अनावश्यक कागजी कार्रवाई में खर्च नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक उपकरणों और प्रयोगों के लिए जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। शोध के मूल्यांकन में केवल प्रकाशित शोधपत्रों की संख्या के बजाय उनकी गुणवत्ता, मौलिकता और सामाजिक उपयोगिता को महत्त्व दिया जाना चाहिए। वित्तीय जवाबदेही जरूरी है, लेकिन उसे इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि पारदर्शिता बनी रहे और शोध कार्य भी बाधित न हो।

भारतीय मूल के अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ विदेशों में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसे केवल देश छोड़ने की प्रवृत्ति के रूप में देखने के बजाय उन परिस्थितियों को समझना जरूरी है, जिनमें प्रतिभाएं बेहतर संसाधनों, स्वतंत्रता और अवसरों की तलाश करती हैं। भारत में उन्हें अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, प्रतिस्पर्धी शोध-अनुदान, योग्य मार्गदर्शन और संस्थागत स्वायत्तता मिले, तो देश के भीतर ही विश्वस्तरीय शोध का वातावरण मजबूत हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिकों का आवागमन भी ज्ञान के विस्तार में मदद कर सकता है।

भारत के पास युवा आबादी, व्यापक वैज्ञानिक आधार और बड़ी घरेलू अर्थव्यवस्था जैसी महत्त्वपूर्ण ताकतें हैं। जरूरत इनका इस्तेमाल दूरदर्शी शोध नीति के साथ करने की है। सरकार को अनुसंधान पर निवेश बढ़ाने, निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने, स्कूली शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और विश्वविद्यालयों को शोध के अनुकूल संसाधन देने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही, वैज्ञानिकों को प्रशासनिक बाधाओं से मुक्त करते हुए जवाबदेही और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना होगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल देश में वस्तुओं का उत्पादन करना नहीं, बल्कि उन तकनीकों और ज्ञान का विकास करना भी है जिन पर भविष्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा निर्भर करेगी। भारत को यदि वैश्विक स्तर पर मजबूत और प्रभावशाली बनना है, तो उसे तकनीक का बड़ा उपभोक्ता बने रहने से आगे बढ़कर उसका निर्माता और मौलिक ज्ञान का सृजक बनना होगा। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब शोध और नवाचार को नीतियों, शिक्षा, उद्योग और सामाजिक सोच के केंद्र में रखा जाएगा।

फिसलते वक्त की छाया

विजय सिंह अधिकारी

मनुष्य ने खोई हुई संपत्ति फिर अर्जित की है, उजड़ गए कई संसार फिर बसाए हैं और बीत गए दिनों में हुई भूलों से सीखकर अपने भविष्य की दिशा भी बदली है, लेकिन वह एक ऐसी चीज की भरपाई नहीं कर सका, जो हर क्षण उसके पास से गुजरती रहती है- समय। इसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब यह हमारे पास होता है, तब हम इसका मूल्य नहीं पहचानते। और जब इसका मूल्य समझ में आता है, तब यह हमारे पास नहीं होता। हालांकि समय को लेकर फिक्र करने में हमारे समाज ने कभी कमी नहीं की, लेकिन समाज का हर व्यक्ति इस बात से परेशान दिखता है कि उसके पास समय नहीं है। सवाल है कि क्या हम कभी गौर कर पाते हैं कि हमारा समय हमसे कौन छीन कर या चुरा कर ले गया!

दरअसल, हम अपने जीवन में होने वाले अनेक नुकसानों का हिसाब रखते हैं, लेकिन उन क्षणों का हिसाब कभी नहीं रख पाते, जिन्हें टालमटोल, उपेक्षा और अनजाने अपव्यय में खो देते हैं। शायद जीवन की सबसे बड़ी क्षति वही है, जिसका बोध हमें तब होता है, जब उसकी भरपाई असंभव हो चुकी होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रसिद्ध कथन- 'खोया हुआ समय फिर कभी प्राप्त नहीं होता'- इसी सत्य को संक्षेप में व्यक्त करता है। यों, हमारे यहां भी इसी आशय की कहावतें आमतौर पर दोहराई जाती रही हैं कि 'का वर्षा जब कृषि सुखाने' या फिर कबीर का दोहा बहुतों की जुबान पर होता है कि 'अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत'। सच यह है कि धन फिर से कमाया जा सकता है, संपत्ति का फिर से निर्माण कर लिया जाना संभव है, लेकिन जीवन से निकल चुके क्षण किसी भी कीमत पर वापस नहीं खरीदे जा सकते।

हम परिवार, प्रियजनों और मित्रों को महत्त्व देते हैं, फिर भी उनके लिए समय निकालना कल पर टाल देते हैं। लगता है कि माता-पिता की बातें बाद में सुन लेंगे, बच्चों के साथ खेलना फिर कभी हो जाएगा और मित्र से मिलने का अवसर दोबारा मिल जाएगा। मगर बचपन प्रतीक्षा नहीं करता और जीवन के आत्मीय क्षण अनिश्चित भविष्य के भरोसे नहीं रखे जा सकते। तस्वीरें स्मृतियां संजो लेती हैं, पर बीते हुए पलों को लौटा नहीं सकतीं।

टालमटोल की कीमत पढ़ाई और काम में भी चुकानी पड़ती है। परीक्षा की तैयारी को लगातार टालने वाला विद्यार्थी आखिरकार समय की कमी से जूझता है। अंतिम रात की मेहनत कुछ अधूरे विषयों को संभाल सकती है, लेकिन नियमित अध्ययन से मिलने वाली समझ की पूरी भरपाई नहीं कर सकती। इसी तरह, विचारों को लिखने में देर करने वाला लेखक अपनी संभावनाओं को टालता रहता है और स्वास्थ्य की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति सुधार की आवश्यकता को तब पहचान पाता है, जब स्थिति पहले से कठिन हो चुकी होती है। अवसर निकल जाने के बाद पछतावा बीते समय का विकल्प नहीं बनता।

सवाल है कि क्या कोई ऐसी घड़ी या चाबी बनाई जा सकती है, जो समय को रोक दे? घड़ी उसे मापती है, कैलेंडर तारीखें गिनता है और विज्ञान उसकी प्रकृति का अध्ययन करता है, लेकिन कोई भी वीते क्षण को वापस नहीं ला सकता। सेकंड मिनटों में, मिनट घंटों में और घंटे दिनों में बदलते जाते हैं। इसी प्रवाह में बचपन युवावस्था बन जाता है और युवावस्था धीरे-धीरे वृद्धावस्था में ढल जाती है। हम समय की गणना करते हैं, जबकि वह हमारे जीवन का स्वरूप बदल रहा होता है।

इतिहास भी समय के निर्णायक महत्त्व का साक्षी है। कभी अतीत में कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन की दिशा बदल दी, लेकिन युद्ध में हुई जनहानि की भरपाई संभव नहीं थी। इसी तरह, 1857 के विद्रोह से मिले अनुभवों ने आगे के स्वतंत्रता संघर्ष को प्रभावित किया, लेकिन उसमें खोए जीवन वापस नहीं आए। इतिहास बताता है कि घटनाओं से सीखकर भविष्य की दिशा बदली जा सकती है, पर बीती हुई क्षति मिटाई नहीं जा सकती। आज मोबाइल पर निरुद्देश्य विचरण समय के अपव्यय का सहज उदाहरण है। कुछ मिनटों के लिए खोला गया मोबाइल कब एक घंटा ले लेता है, पता ही नहीं चलता। बार-बार दोहराया गया यह व्यवहार अध्ययन, सृजन और आत्मीय संबंधों के लिए उपलब्ध समय को कम कर देता है। विडंबना यह है कि कई बार समय का चोर और उसका शिकार एक ही व्यक्ति होता है।

समय का सदुपयोग हर क्षण व्यस्त रहने का नाम भी नहीं है। परिवार के साथ हंसना, पुस्तक पढ़ना, प्रकृति के बीच बैठना और पर्याप्त विश्राम करना जीवन को सार्थक बनाते हैं। अंतर इस बात में है कि हम समय को सोच-समझकर जी रहे हैं या अनजाने में गंवा रहे हैं। व्यस्तता हमेशा सार्थक नहीं होती और विश्राम हमेशा बर्बादी नहीं। समय की कीमत कभी अवसर खोने पर, कभी किसी प्रियजन की अनुपस्थिति में और कभी अपनी ही टालमटोल के परिणामों से समझ आती है। भूल सुधारी जा सकती है, उससे सीखकर आगे की राह बदली जा सकती है, लेकिन उस भूल में व्यतीत समय वापस नहीं मिलता।

समय की सबसे बड़ी त्रासदी उसका बीतना नहीं, बल्कि उसके रहते जीवन को कल पर टालते रहना है।

दुनिया मेरे आगे

> **अतीत स्मृति है, भविष्य संभावना और वर्तमान वह अवसर है, जिसमें हम अपने निर्णयों को अर्थ दे सकते हैं। समय बीतता ही नहीं, हमारे जीवन में घटित होता है। आखिर प्रश्न यह नहीं कि हमने कितने वर्ष जिए, बल्कि यह है कि जो समय हमें मिला, उसमें कितना जीवन जिया।**

मानचित्र से छेड़छाड़



चीन और पाकिस्तान द्वारा अपने नक्शों में भारत के अभिन्न अंगों कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को दर्शाने की ओछी हरकतें जगजाहिर रही हैं। हाल ही में चीन द्वारा मानचित्र में फेरबदल किए जाने पर भारत की सख्त चेतावनी के बाद उसे नक्शा हटाना पड़ा, जो हमारी कूटनीतिक मजबूती को दर्शाता है। अतीत में भी ऐसे प्रयास होते रहे हैं। सामरिक दृष्टिकोण से केवल राजनीतिक नक्शे ही नहीं, बल्कि सैन्य और भौगोलिक उपयोग वाले टोपोग्राफिक (स्थलाकृतिक) शीट भी अत्यंत गोपनीय होते हैं। इनसे अक्षांश-देशांश की सटीक जानकारी लेकर शत्रु देश सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस प्रकार की हरकतों को बार-बार और कड़ाई से उठाया जाना चाहिए। भारत को वैश्विक संधियों और मंचों का उपयोग कर पड़ोसी देशों की इस नापाक विस्तारवादी मानसिकता को बेनकाब करना होगा, ताकि भविष्य में संप्रभुता से खिलवाड़ करने की कोई हिम्मत न कर सके।

- संजय वर्मा, धार, मध्य प्रदेश

सुधार की जरूरत

द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद विश्व शांति और मानवता की रक्षा के उद्देश्य से स्थापित संयुक्त राष्ट्र आज अपनी सार्थकता की दोराहे पर खड़ा है। 51 देशों से शुरू हुआ यह संगठन आज 193 सदस्यों का परिवार है, लेकिन इसके बावजूद रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के भीषण संघर्षों में यह लाचार नजर आया है। सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के पास मौजूद 'वीटो' अधिकार और आपसी मतभेदों के कारण आज संयुक्त राष्ट्र कई मौकों पर केवल चर्चा का मंच बनकर रह गया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा परिषद का विस्तार और उसमें सुधार समय की सबसे बड़ी मांग है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और शांतिप्रिय देश भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलना न्यायसंगत ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है। यदि यूएन को अपनी प्रासंगिकता बचाए रखनी है, तो इसे अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा।

- हिमांशु शेखर, गयाजी, बिहार

दायित्व के साथ

'साइबर खतरा' (संपादकीय, 23 अक्तूबर) डिजिटल बैंकिंग में ग्राहकों की सुरक्षा पर अत्यंत गंभीर और सामयिक चिंता उजागर करता है। साइबर धोखाधड़ी रोकना और जमा-पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करना बैंकों व साफ्टवेयर कंपनियों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है, न कि इसे केवल ग्राहकों की सतर्कता पर छोड़ देना। तकनीकी प्रणालियां इतनी सशक्त होनी चाहिए कि किसी भी ग्राहक की अनभिज्ञता का लाभ न उठाया जा सके। केवल डिजिटल संदेशों के जरिए निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत से उपभोक्ता तकनीक से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। बैंकों को स्थानीय भाषाओं में मुद्रित पत्र भेजकर भी सुरक्षा उपायों की जानकारी घर तक पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा, डार्क वेब पर सक्रिय साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सख्त और ठोस कार्रवाई करनी होगी, ताकि नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- बृज भूषण गोयल, लुधियाना

पर्यटन और सरोकार

'पर्यटन के विकास का पैमाना' (लेख, 27 अक्तूबर) देश के पर्यटन माडल पर एक आंख खोलने वाला और सामयिक वैचारिक दस्तावेज है। आज जब हम करोड़ों पर्यटकों के आंकड़ों और वैश्विक रैंकिंग पर गर्व करते हैं, तो यह सवाल अहम हो जाता है कि इसका वास्तविक लाभ धरातल पर कितने स्थानीय लोगों तक पहुंच रहा है। पर्यटन का उद्देश्य केवल होटलों की संख्या बढ़ाना या राजस्व कमाना नहीं होना चाहिए। लेखक ने सही रेखांकित किया है कि जब तक पर्यटन को पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक अस्मिता और स्थानीय आत्मनिर्भरता से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इसका विस्तार अधूरा रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में अविवेकी निर्माण और ऐतिहासिक स्थलों का व्यावसायीकरण आज गंभीर खतरे बन चुके हैं। सच्चा पर्यटन वही है जो केवल आगंतुकों को आनंद न दे, बल्कि मेजबान समाज के जीवन स्तर को भी समृद्ध बनाए।

- मनोज वशिष्ठ, रेवाड़ी, हरियाणा

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

चक्रवात से सबक

बंगाल की खाड़ी से उपजे चक्रवात अर्नब की वजह से आधे से ज्यादा भारत में मौसम बिगड़ा हुआ है। कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं बादल छाए हुए हैं, तो कहीं बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के करीब 14 राज्यों के लिए चेतावनी जारी कर रखी है। हालांकि, चक्रवात अर्नब का सर्वाधिक असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सबसे ज्यादा दिखा है। ओडिशा सरकार ने पूरी तैयारी दिखाई है, तो वहां किसी की भी जान नहीं गई है, जबकि आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में कम से कम पांच लोगों की मौत की दुखद सूचना है। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान एवं बारिश की वजह से करीब 15,000 बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। वहां करीब 3.45 लाख किसान प्रभावित हुए हैं और 14 जिलों के 2,24,489 हेक्टेयर में खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं या खराब हो गई हैं। वैसे, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकारों की तारीफ होनी चाहिए, इन्होंने समय रहते बचाव के इंतजाम किए हैं और हजारों गांवों को खाली करवाया है। वाकई, जान के नुकसान को कम से कम रखना सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

ओडिशा में भारी बारिश के कारण अनेक जगह भूस्खलन हुआ है, सड़कें जलमग्न हुई हैं और पेड़ उखड़ गए हैं। इसके बावजूद वहां कोई हताहत नहीं हुआ है, तो इस कामयाबी से सीखने की जरूरत है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे तूफानों या चक्रवातों की संख्या बहुत बढ़ी तो नहीं है, लेकिन उनकी आक्रामकता बढ़ती जा रही है। ऐसे में, हमारे पास सावधान और तैयार रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीति के तहत पहले जनहानि को बचाना और उसके बाद अन्य प्रकार के नुकसानों को रोकने के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। यह भी एक बड़ी चिंता की बात है कि ऐसे चक्रवात आमतौर पर अप्रैल-मई में देखे जाते थे। क्या मौसम के साथ आपदाओं का चक्र भी बदल रहा है? आपदाएं पहले की तुलना में ज्यादा घातक हो रही हैं? हम यह देख पा रहे हैं कि भारत ही नहीं, विकसित देशों को भी आपदाओं का सामना करने में अब बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ध्यान रहे, पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे समुद्री जल गर्म हो रहा है और वहां से उठने वाली आपदाओं की तीव्रता बढ़ रही है। यह अल नीनो वर्ष है और इसके दौरान महासागरीय बेसिन में उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात कम बार आते हैं और उनकी तीव्रता भी कम होती है, लेकिन चक्रवात अर्नब ने इस आकलन को धता बता दिया है।

चक्रवातों की संख्या में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन उनकी आक्रामकता बढ़ती जा रही है। ऐसे में, हमारे पास सावधान और तैयार रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

सनद रहे, अल नीनो वर्ष में भारी वर्षा, तूफान, चक्रवात, आगजनी, बाढ़ इत्यादि का खतरा ज्यादा मंडराएगा। संतोष की बात है कि हम इसके लिए बहुत हद तक तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसी आपदाओं के समय केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर मुमकिन प्रबंध करने चाहिए और ऐसे प्रबंधों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सराहनीय बात है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल व राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को समय रहते तैनात किया गया और प्रभावित राज्यों में बचाव व राहत अभियान युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। नुकसान का यथोचित आकलन करके मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार मृतकों के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये दे रही है, लेकिन उसे अध्ययन करना चाहिए, चेतावनी के बावजूद पांच लोगों की मौत कैसे हुई? बचाव के इंतजाम कैसे अधूरे रह गए? आपदा प्रबंधन में दिखी कमियों को दोहराने से बचना होगा।

दवाओं की कीमतों पर लगाम जरूरी



यहां स्कैन करें

संघमित्रा शील आचार्य | प्रोफेसर, जेएनयू

दवा मूल्य निर्धारण की नीति केवल चुनिंदा दवाओं या बीमारियों तक सीमित न रहे, बल्कि यह नीति सभी तरह की आवश्यक दवाओं के लिए सुनिश्चित की जाए।

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं की कीमतों में 93 फीसदी तक की कमी इसके मरीजों को बड़ी राहत पहुंचाएगी। भारत में कैंसर की दवाओं और इलाज पर एक मरीज औसतन 3.15 लाख रुपये सालाना खर्च करता है, जो इस बीमारी की गंभीरता के हिसाब से इससे अधिक भी हो सकता है। इसमें दवा की हिस्सेदारी 50 से 60 फीसदी तक हो सकती है। जाहिर है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए द्वारा 543 दवा ब्रांडों और उनकी अधिकतम खुदरा कीमतों में किया गया यह बदलाव मरीजों और उनके परिवार के आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। माना जा रहा है, इससे कैंसर मरीजों की सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकेगी।



यह पहल सर्वोच्च न्यायालय की 27 अक्तूबर, 2026 की उस टिप्पणी के संदर्भ में की गई जान पड़ती है, जिसमें उसने सवाल किया था कि केंद्र सरकार दवाओं की अधिक व्यापक श्रेणी को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने के प्रति अनिच्छुक क्यों है? उसने यह भी कहा था कि दवा उद्योग की वृद्धि को लेकर चिंताएं इस बात का आधार नहीं बन सकतीं कि मरीजों को ऐसी दवाओं की ऊंची कीमतों का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाए, जो उनकी खरीद-लागत से सैकड़ों गुना अधिक हो सकती हैं।

वास्तव में, न्यायालय ने उस समस्या की ओर ध्यान खींचा था, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संगठन लंबे समय से उठाते आ रहे हैं। दवाएं और 'मेडिकल कंज्यूमेबल्स', यानी चिकित्सा उपयोग की वस्तुएं मरीजों को उस कीमत से 300 से 700 प्रतिशत या उससे भी अधिक मूल्य पर बेची जाती हैं, जिस कीमत पर अस्पताल या खुदरा विक्रेता उनको खरीदते हैं। संभवतः इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं की अत्यधिक कीमतों के बने रहने में सरकार की भूमिका पर चिंता जताई थी।

यह कोई छिपी बात नहीं है कि दवाओं की खरीद-कीमत और मरीजों द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत के बीच बड़ा अंतर दवा कंपनियों के पक्ष में जाता है। ऐसी स्थिति में दवाओं के मूल्य निर्धारण में राज्य की प्रभावी भूमिका आवश्यक है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ही वह निकाय है, जिसे दवाओं की कीमतों को नियम-व्यवस्था के अधीन रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, कैंसर की दवाओं को लेकर उसने अब पहल की है, पर सवाल बना हुआ है कि उत्पादन-प्रक्रिया से लेकर मरीजों तक तमाम दवाओं के पहुंचने के दौरान कीमतों में बने रहने वाले बड़े अंतर की वह ढंग से नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही है?

केवल एक बीमारी पर विशेष ध्यान देने वाली नीति से पक्षपात का आरोप लग सकता है। सरकार को इस बारे में नीतिगत पहल करनी चाहिए, अन्यथा सवाल उठेगा कि क्या नए फैसले किसी विशेष क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तो नहीं लिए जा रहे हैं? दूसरी बीमारियों की उपेक्षा करने का कोई औचित्य नहीं दिखता, विशेषकर तब, जब उनके उपचार में प्रयोग होने वाली दवाओं की कीमतें और उपलब्धता के संबंध में भी समान रूप से हस्तक्षेप किए जाने की दरकार है।

यहां गणपति मुद्दू द्वारा साल 2006 में 'ब्रिटिश मेडिकल जर्नल' (बीएमजे) में प्रकाशित शोध 'इंडियन हेल्थ एक्टिविस्ट क्रिटिसाइज वलिंटरी प्राइस कट्स बाई इंडस्ट्री' की चर्चा लाजिमी है, जो इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण नजरिया हमारे समाने रखता है। इसमें बताया गया है कि भारत की कुछ सबसे बड़ी दवा कंपनियों ने 886 आवश्यक फॉर्मूलेशन की कीमतों में कटौती की, ताकि दवा की कीमतों को प्रभावित किया जा सके। इस कदम को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने औषधि उद्योग की ऐसी रणनीति के रूप में देखा, जिसका उद्देश्य प्रभावी और सार्थक मूल्य नियंत्रण से बचना था।

इस संदर्भ में जन-स्वास्थ्य अभियान जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता समूहों का यही मानना है कि कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं (जैसे कुछ कैंसर-रोधी दवाएं) पर कारोबारी मार्जिन की सीमा तय करना निस्संदेह अच्छा कदम है, लेकिन सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है। कीमतों में की जाने वाली कमी का प्रभाव आमतौर पर जेनेरिक दवाओं पर अधिक पड़ता है, जबकि महंगी पेटेंट-प्राप्त दवाएं या मूल ब्रांड की दवाएं इससे अछूती रह सकती हैं। इसलिए 'कॉस्ट-बेस्ड प्राइसिंग', यानी लागत आधारित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता अधिक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस बात पर बल देते हैं कि दवाओं की कीमतों की अधिकतम सीमा केवल चिकित्सीय के लाभांश में कमी के आधार पर तय नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे दवाओं की वास्तविक निर्माण व उत्पादन लागत से सीधे जोड़ा जाना चाहिए।

बेशक, केंद्र सरकार दवा की कीमतों को कम करने के प्रयास कर रही है। 'प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र' की परिकल्पना भी इसीलिए की गई, ताकि दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हो सकें। हालांकि, लोगों में अब भी जेनेरिक दवाओं को लेकर उलझन बनी हुई है, जिसको दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जरूरत यह भी है कि ऐसी दुकानें सुदूर इलाकों तक पहुंचें।

फिलहाल, कुछ दवाओं की कीमतें जरूर कम हुई हैं, लेकिन ऐसे प्रयास यदि समावेशी दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होंगे, तो स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार को अधिक किफायती बनाने का मकसद अधूरा रह जाएगा। जरूरी है कि ऐसे प्रयासों का लाभ हर मरीज तक, फिर चाहे वह किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, समान रूप से पहुंचे। अगर ऐसा नहीं होगा, तो चयनात्मक नीतियां नीति-निर्माताओं, न्यायालयों, दवा उद्योग के प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच गंभीर बहस को जन्म देती रहेंगी। एक प्रभावी नियामक व्यवस्था को दवा उद्योग की आर्थिक व्यावहारिकता और मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के बीच संतुलन बनाना ही चाहिए। जन-स्वास्थ्य के नजरिये से भी दवाओं तक पहुंच सामाजिक न्याय के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप आवश्यक है।

अतः दवा मूल्य निर्धारण की नीति केवल चुनिंदा दवाओं या बीमारियों तक सीमित न रहे, बल्कि यह नीति सभी आवश्यक दवाओं के लिए सुनिश्चित की जाए। इसमें दवाओं की वास्तविक उत्पादन लागत, निर्माताओं और वितरकों के लाभांश, बाजार में मूल्य-निर्धारण की प्रक्रिया, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों की भुगतान-क्षमता को समग्रता में देखना चाहिए। प्रभावी मूल्य-नियंत्रण का मूल उद्देश्य केवल कीमतों में कमी करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि आवश्यक व जीवन-रक्षक दवाएं सभी मरीजों को सुलभ और सस्ती कीमतों पर मिलें।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

एआई के रचनात्मक उपयोग से सबको होगा फायदा



यहां स्कैन करें

राहुल मथान | साइबर विशेषज्ञ

इस साल की शुरुआत में कोलंबिया में एक दिलचस्प घटना घटी। वहां की सर्वोच्च अदालत ने एक अपील इसीलिए खारिज कर दी, क्योंकि उसके मुताबिक, याचिका में महज सात फीसदी सामग्री ही ईमान द्वारा लिखी गई थी। एआई डिटेक्टर 'विंस्टन' से इसका पता चला, इसलिए (कुछ अन्य वजहों से भी) अदालत ने इसे वैध तरीके से तैयार याचिका मानने से इनकार कर दिया। हालांकि, इस याचकों के कुछ समय बाद वकील इमैनुएल एलेसियो वेलास्केज ने अदालत के उसी फैसले की जांच इसी एआई डिटेक्टर से कराई, तो हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि डिटेक्टर ने उस फैसले का भी 93 फीसदी हिस्सा एआई-रचित बताया।

इन दिनों दस्तावेज तैयार करने में एआई के इस्तेमाल को जांचने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सितंबर में एक व्यक्ति ने 'पैंग्राम' टूल की रिपोर्ट पोस्ट करते हुए बताया कि थेलीसिन ओरेलियन का उपन्यास एआई की मदद से लिखा गया है, जिसके बाद कुक की तरह प्रतिष्ठित फ्रांस के गोनकोर्ट पुरस्कार की जूरी ने उस उपन्यास को अपनी सूची से बाहर कर दिया। इसी तरह, शोधकर्ता लिंच झांग ने जब पोप लियो चौदहवें के 'एआई के दौर में मनुष्य की स्थिति' पर लिखे धर्मपत्र *मैग्निफिका ह्यूमेनिटास* की जांच पैंग्राम से कराई, तो कुछ पैराग्राफ को एआई-निर्मित बताए जाने से चर्चा का केंद्र इस धर्मपत्र का संदेश नहीं, बल्कि यह सवाल बन गया कि आखिर इसे लिखा किसने है? एआई अब इतना बेहतर लेखन करने लगा है कि कई बार उसकी रचित सामग्री और हमारे लिखे पाठ में फर्क करना असंभव हो जाता है। यही वजह है, एआई रचित लेखों की पहचान करने वाले टूल का सहारा अधिक लिया जाने लगा है। नतीजतन, अब हम इस बात से ज्यादा चिंतित रहते हैं कि कोई सामग्री कैसे तैयार हुई, जबकि हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि उस लेखन में खास बात क्या है?

अगर आपको कोई लेख रोचक लगा, तो क्या सच में इससे कोई फर्क पड़ता है कि उसे एआई ने पांच प्रतिशत लिखा है या 95 फीसदी?

पाठक मुझसे अक्सर यह पूछते रहते हैं कि मुझे अपने लेख के विचार कहां से मिलते हैं? मैं शोध में कितना समय लगाता हूं और हर हफ्ते लेख लिखने के लिए समय कैसे निकाल पाता हूं? अगर मैं कहूं कि यह सब आसान है, तो झूठ होगा। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रकाशन की 'डेडलाइन' करीब आ रही होती थी और मुझे कोई विचार नहीं सूझता था।

इस स्थिति से निपटने के लिए मैंने कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन जितनी मदद मुझे एआई से मिली, वैसी किसी अन्य साधन से नहीं। मेरे हर लेख की शुरुआत किसी ऐसे विचार से होती है, जिसे मैंने किसी कॉन्फ्रेंस में सुना, या कोई पॉडकास्ट सुनते समय मेरे दिमाग में कौंधा। आजकल, जैसे ही कोई नया विचार आता है, मैं उसे अपने 'जर्मिनेशन बेंच' में दर्ज कर लेता हूं। यह एक ऐसा 'आइडिया-स्टोर' है, जिसे एआई संभालता है। यहां हर नए विचार को तब तक विकसित किया जाता है, जब तक कि वह एक पूरा लेख बनने लायक न हो जाए। जब लिखने का समय आता है, तब एआई जर्मिनेशन बेंच को स्कैन करके कोई उपयुक्त विचार ढूंढ़ता है। बिल्कुल नया या कोई ऐसा विचार, जो मेरी पिछली बातों को आगे बढ़ाता हो या किसी ऐसे मुद्दे से जुड़ा हो, जिस पर मैंने अभी तक कुछ न लिखा हो।

इसके बाद एआई तर्कों पर रिसर्च करता है, तथ्यों की पुष्टि करता है और उन सभी दावों के स्रोत खोजता है, जिनका मैं लेख में इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसके बाद वह मसौदा तैयार करना शुरू करता है। इसलिए हमें तकनीक के अनिवार्य विकास का विरोध करने के बजाय इसके साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए। हमें इसमें पूरी तरह से रम जाना चाहिए, ताकि इससे मिलने वाले नए अवसरों का हम लाभ उठा सकें।

एआई वर्कफ्लो का इस्तेमाल करके ही यह लेख लिखा गया है। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि इसने सबसे जरूरी 'टेस्ट' पास कर लिया, यानी आखिर तक आपका ध्यान बनाए रखा। आपमें से कुछ लोग शायद इसे किसी एआई डिटेक्टर से गुजारकर देखना चाहें कि इसका कितना हिस्सा एआई द्वारा रचित है। अगर आपको यह लेख रोचक लगा, तो क्या सच में इससे कोई फर्क पड़ता है कि इसे एआई ने पांच प्रतिशत लिखा है या 95 फीसदी?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मानसिक जप सर्वोत्तम

बहुत लोग यह पूछते हैं कि मन के संयम से लिये अजपाजप अच्छा है या ओंकार जप? मैं आपसे पूछता हूं, अजपाजप के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुख से 'सोहम्-सोहम्' रटना अजपा है? वस्तुतः अजपा का अर्थ वह जप है, जो मुख से उच्चारित हुए बिना, अनायास, अपने आप चलता रहता है। इस वास्तविक अर्थ को जानें बिना लोग यह सोचते हैं कि मुख से सोहम्-सोहम् जप हजारों-लाखों बार उंगली पर या माला से गिनकर किया जाना चाहिए।

जप का प्रारंभ करने से पहले प्राणायाम करना चाहिए, ऐसा शास्त्र-विधान है। प्राणायाम के दौरान मुख बंद रखना होता है। है कि नहीं? यदि प्राण की गति रोककर शरीर के पांच महाभूतों को एक साथ बांधकर उनका संयम किया जाए, तो शेष आत्मा रहती है। स्ववं आत्मा हमेशा अपने आप अहं-अहं दोहराती रहती है, यह अजपा है। इसको जानने के बाद मौखिक जप को अजपा कैसे कहा जा सकता है? सच्ची अपने आप अनैच्छिक रूप से, अखंड, अंतहीन रूप से जप करती रहती है, उसका दर्शन करना अजपा या गायत्री या सब कुछ है। यदि आप यह जानें कि जप कौन कर रहा है, तो आप जान लेंगे कि जप क्या है? यदि आप तलाश करें और जानने का यत्न करें कि वह कौन है, जो जप कर रहा है, तो वह जप स्वयं आत्मा बन जाता है।

अब आपके भीतर प्रश्न उठ रहा होगा कि मौखिक जप से क्या कोई लाभ नहीं होता? किसने कहा कि लाभ नहीं है? ऐसा जप चित्त को शुद्ध करेगा। जैसे-जैसे जप निरंतर किया जाएगा, वह प्रयत्न जल्दी से या देर से सच्चे मार्ग पर ले आएगा। अच्छा या बुरा, जो भी किया जाता है, वह निष्फल नहीं होता। केवल व्यक्ति के विकास स्तर के अनुसार इनके भेद तथा गुण-दोष बनाए जाते हैं। मौखिक जप ध्वनि-रूप होता है, ध्वनि विचार से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि विचारों को शब्दों में व्यक्त करने के पूर्व सोचना पड़ता है। मन विचारों से बनता है। इसलिए मानसिक जप मौखिक से अच्छा है।

मानसिक जप को ही ध्यान कहा जाता है; ध्यान चिंतन तथा मानसिक जप एक समान हैं। विचार जब उलझे हुए नहीं होते और कई विचारों के स्थान में एक ही

जप अथवा ध्यान का लक्ष्य यह है कि बहुत सारे विचारों को हटाकर केवल एक विचार को बनाए रखना। तब वह एक विचार भी अपने मूल- पूर्ण चैतन्य- में विलीन हो जाता है।

विचार बना रहता है, तो इसे ध्यान कहते हैं। जप अथवा ध्यान का लक्ष्य यह है कि बहुत सारे विचारों को हटाकर केवल एक विचार को बनाए रखना। तब वह एक विचार भी अपने मूल- पूर्ण चैतन्य- में विलीन हो जाता है। मन जप में जुड़ जाता है और तब अपने मूल में समा जाता है। जप मन को एक विचार पर स्थिर करने में सहायता करता है। दूसरे सब विचारों को गौण बनाकर उनको एक विचार के अधीन तब तक बनाए रखा जाता है, जब तक वे अदृश्य न हो जाएं। ध्यान ही आपका सच्चा स्वभाव है।

रमण महर्षि

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत



विकास यात्रा में जनजातीय समाज की प्रकृति-पोषक जीवन पद्धति से उपयोगी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उपयुक्त प्रोत्साहन मिले, तो आदिवासी समाज के बेटे-बेटियां जीवन के हर क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ा सकते हैं।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले 30 अक्तूबर, 1951

नया चीन

नेपोलियन ने एक बार चीन के संबंध में कहा था:- 'वह एक निद्रामग्न दैत्य है, उसे सोया हुआ रहने दो, क्योंकि जब वह जाग पड़ेगा तो सारी दुनिया को हिला देगा।' यह भविष्यवाणी वास्तव में सत्य सिद्ध हो रही है क्योंकि नये चीन ने विश्व को किसी हद तक हिला दिया है और कोई राष्ट्र माओ सरकार को चाहे कूटनीतिक मान्यता प्रदान करे या नहीं, चीन की संसार की एक बड़ी शक्ति के रूप में उदित होने से नहीं रोका जा सकता।

आजकल 'साम्यवादी चीन' तथा 'नया चीन' पर्यायवाची शब्द बन गये हैं। यद्यपि चीन में साम्यवादी नेतृत्व तथा प्रभाव को देखते हुए यह मान्यता एक हद तक सही है, किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि नई सरकार ने देश में एक ऐसी उखाड़-पछाड़ नहीं की है, जिससे चीनी जीवन का मूल स्रोत ही बदल गया हो। पर्यवेक्षकों का कहना है कि माओ-त्से-तुंग द्वारा प्रतिपादित और प्रचारित साम्यवाद रूसी साम्यवाद की हुबहू नकल नहीं है। चीन के नये नेता ने कृषि वर्ग को एक क्रान्तिकारी शक्ति मानकर आगे कदम बढ़ाया है। चीन की समस्या प्रधानतः एक कृषि-समस्या रही है। च्यांग-काई शेक की असफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि च्यांग सरकार किसानों- दूसरे शब्दों में 80 प्रतिशत जनता- के लिए कोई आर्थिक व्यवस्था न कर सकी।...

यद्यपि किसी सरकार की सफलता-असफलता को उसके दो वर्ष के कार्यकाल से नहीं मापा जा सकता, किन्तु यह निर्विवाद है कि चीन की नवीन शासन-व्यवस्था के पौधे ने अपनी जड़ें जमा ली हैं और यह आसानी से नहीं उखड़ेगा। हम समझते हैं कि नये चीन को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि माओ सरकार अपने को सुस्थिर तथा लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कर रही है। इस संबंध में चीन-स्थित भारतीय राजदूत सरदार पणिक्कर ने विस्तृत प्रकाश डालकर भारतीय जनता की जिज्ञासा की तृप्ति ही नहीं की है, बल्कि कतिपय भ्रान्त धारणाओं का उन्मूलन भी किया है। उन्होंने कहा है कि यद्यपि चीनी शासनतंत्र के बहुत से नेता साम्यवादी विचारधारा के अनुगामी हैं, किन्तु चीनी सरकार साम्यवादी सरकार नहीं है। बहुत दिन हुए श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित ने अमरीका में कहा था कि चीन की सरकार विभिन्न दलों की एक सम्मिलित सरकार है।

ठेका आधारित व्यवस्था से बढ़ रहा भ्रष्टाचार

सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग, यानी ठेका आधारित व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक कुशल, लचीला और कम-खर्च बनाना था, पर असलियत में ठेका के बहाने सरकारी विभागों और आउटसोर्सिंग कंपनियों (ठेकेदारों) के बीच एक सुनियोजित गठबंधन काम करने लगा है, जो भ्रष्टाचार को अंजाम देता है। मसलन, स्थानीय निकायों में कार्य करने हेतु मानव संसाधनों की आपूर्ति निविदा के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसियां कर रही हैं, और यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार का खेल। दरअसल, जो बिल आउटसोर्सिंग एजेंसियां सरकारी दफ्तरों में जमा करती हैं, विभागीय अधिकारी उनको पूर्ण जांच किए बिना स्वीकृत कर लेते हैं। माना जाता है कि इसमें परदे के पीछे एजेंसियों और अधिकारियों में लेन-देन होता है। न तो इस बात की जांच की जाती है कि कर्मचारियों की जितनी संख्या एजेंसी बता रही है, वह वाकई उपयुक्त है और न इस बात की पड़ताल होती है कि कर्मचारियों को प्रावधान के मुताबिक कितनी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं?

यह पूरा खेल किस तरह असीमित मुनाफे का होता है, इसका पता इससे भी चलता है कि सरकारी खजाने से प्रति कर्मचारी जितनी राशि निर्गत होती है, उसका कुछ हिस्सा विभागीय अधिकारी व एजेंसियां आपस में बांटती हैं और शेष कर्मचारियों को दिया जाता है। बेरोजगारी के इस दौर में उच्च शिक्षित युवा जब मामूली रकम हाथ में पाते हैं, तो उनका हताश होना स्वाभाविक है। यही नहीं, बिल में फर्जी कर्मचारियों की संख्या भी खूब बताई जाती है। जैसे- कागजों पर 100 कर्मचारियों की तैनाती दिखाई जाती है, पर हकीकत में 60-70 कर्मचारी ही काम करते हैं। बाकी 'कर्मचारियों' के वेतन-भत्ते आदि ठेकेदार व विभागीय अधिकारी आपस में बांट लेते हैं। इसी तरह, भर्ती के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया जाता है।

आउटसोर्सिंग में एक बड़ा घपला निविदा-प्रक्रिया में भी किया जाता है। ई-टेंडरिंग के बावजूद अधिकारियों द्वारा इस तरह निविदाएं जारी की जाती हैं कि ठेका उनकी पसंदीदा एजेंसी को ही मिले। कई बार तो अधिकारी खुद अपने रिश्तेदारों या करीबियों के नाम पर बेनामी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ठेका दिलाते हैं। कहने का अर्थ यही है कि ठेके वाली इस व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। वैसे भी, जब कर्मचारियों से संबंधित अधिकांश कार्य सरकारी विभागों में ही होते हैं, तो फिर एजेंसियों (बिचौलियों) को दिए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान की उपयोगिता आखिर क्या है?

शुभम झा, वकील

अनुलोम-विलोम
ठेका आधारित व्यवस्था



आउटसोर्सिंग से सेवाओं का होता विस्तार

सरकारी कामकाज में आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पहले जिन कामों के लिए स्थायी सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता था, उनमें से कई अब निजी एजेंसियों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। इससे सरकार को जरूरत के अनुसार मानव संसाधन जुटाने, भर्ती-प्रक्रिया का बोझ कम करने और सेवाओं को समयबद्ध तरीके से संचालित करने में मदद मिली है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और दूर-दराज के क्षेत्रों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना वैसे भी चुनौतीपूर्ण काम रहा है, वहां आउटसोर्सिंग व्यवस्था उपयोगी साबित हो रही है।

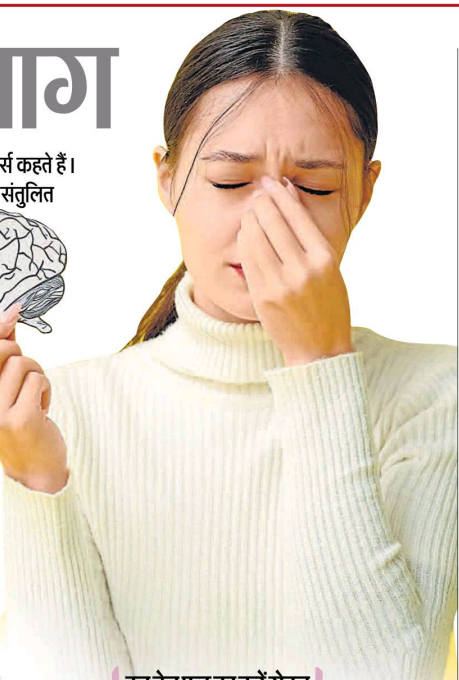
सरकार का मुख्य काम नीतियां बनाना, जन-कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना है, लेकिन कार्यालयों में डाटा एंट्री, कंप्यूटर संचालन, सफाई, सुरक्षा, तकनीकी सहायता, वाहन संचालन और अन्य सहायक कार्यों के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इन कामों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कराने से विभागों को अपनी जरूरत के मुताबिक कर्मचारी उपलब्ध हो सकते हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में लचीलापन आता है। आउटसोर्सिंग एजेंसियां अपेक्षाकृत कम समय में आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करा देती हैं, जिससे कार्यालयों के रोजमर्रा के काम प्रभावित होने की आशंका घटती है। विशेष रूप से तकनीकी सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में विशेषज्ञता हासिल करने वाली एजेंसियों की मदद से विभाग नई क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में 'गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस' के माध्यम से सरकारी संगठनों ने दस लाख से अधिक श्रमिकों को काम पर रखने की प्रक्रिया पूरी की। इससे पता चलता है कि सरकारी सेवाओं में आउटसोर्सिंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

हालांकि, इसकी सफलता केवल कर्मचारियों की उपलब्धता से नहीं मापी जानी चाहिए। यह जरूरी है कि एजेंसियां समय पर वेतन दें, कर्मचारियों के भविष्य निधि व कर्मचारी राज्य बीमा संबंधी अंशदान जमा करें और न्यूनतम मजदूरी के नियमों का पालन करें। फिर भी, सच यही है कि आउटसोर्सिंग को सरकारी व्यवस्था में दक्षता बढ़ाने के एक माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। इससे भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं का बोझ कम करने, विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त करने और विभागों को तात्कालिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। अब सरकार की प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था बनाने की होनी चाहिए, जिसमें काम समय पर हो, सरकारी धन का बेहतर उपयोग हो और कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहें।

विजय शंकर राय, टिप्पणीकार

ताउम्र तेज चले दिमाग

कुछ लोगों का दिमाग बढ़ती उम्र के बावजूद बेहतर काम करता है। वैज्ञानिक ऐसे लोगों को सुपरएजर्स कहते हैं। 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर हुए शोध बताते हैं कि सही दिनचर्या, नया सीखने की ललक और संतुलित खानपान से दिमाग के 'ग्रे मैटर' को सिकुड़ने से रोकने में मदद मिलती है। उम्र के साथ दिमाग की धार कैसे बरकरार रखें, बता रहे हैं तोयज कुमार सिंह



उम्र 80 पार, लेकिन दिमाग की धार 25 साल के युवा जैसी! हमारे आसपास ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं, जिनकी याददाश्त, सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती उम्र के बावजूद कमजोर नहीं होती। न्यूरोसाइंस में ऐसे लोगों को 'सुपरएजर्स' कहा जाता है। सवाल उठता है कि कुछ लोगों के दिमाग पर उम्र का असर क्यों नहीं होता?

सुपरएजर्स के दिमाग में क्या खास?

उम्र के साथ मस्तिष्क का तेज बने रहना कोई इत्तेफाक या महज किस्मत नहीं है, बल्कि यह दिमाग की आंतरिक सेहत और जीवनशैली का नतीजा है। अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के सुपरएजिंग शोध कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों का अध्ययन किया जाता है, जिनकी याद्दाश्त 50-60 वर्ष के लोगों जैसी होती है। शोध में ऐसे लोगों में मस्तिष्क की कुछ संरचनाएं दूसरों से बेहतर देखी गई हैं। खासकर, मस्तिष्क की बाहरी परत सेरेब्रल कॉर्टिक्स में उम्र के साथ होने वाली क्षति कम देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग की कार्यक्षमता में गिरावट की रफ्तार हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं होती। वैज्ञानिक इस संबंध में मस्तिष्क की बनावट, जीन, सेहत और जीवनभर के अनुभवों की भूमिका का अध्ययन भी कर रहे हैं।

दिमाग की संरचना को समझें

मानव मस्तिष्क के तीन हिस्से मुख्य होते हैं-

सेरेब्रम : यह दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। सोचना, तर्क करना, याददाश्त, भाषा, निर्णय लेना व इच्छाशक्ति जैसी प्रक्रियाएं इस हिस्से में होती हैं।

सेरेबेलम : इसे 'छोटा दिमाग' भी कहते हैं। इसका मुख्य काम शरीर का संतुलन, पॉस्चर बनाए रखना और सूक्ष्म शारीरिक हरकतों को नियंत्रित करना है।

ब्रेनस्टेम : यह दिमाग को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। सांस लेना, दिल का धड़कना, बीपी व भोजन निगलने जैसी स्वत: होने वाली क्रियाएं यहीं से संचालित होती हैं।

ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर: सेरेब्रम की सबसे ऊपरी सतह को सेरेब्रल कॉर्टिक्स कहा जाता है, जो ग्रे मैटर से बनी होती है। यह 2 से 4 मिलीमीटर मोटी होती है और सोचने-समझने का सारा काम यहीं होता है। उम्र के साथ जब ग्रे मैटर कम होने लगता है, तो याद्दाश्त पर सीधा असर पड़ता है। इसके ठीक नीचे व्हाइट मैटर होता है, जो अंदर बिछे टेलीफोन के तारों की तरह काम करता है। यह दिमाग को शरीर के बाकी अंगों से जोड़ता है।

न्यूरॉन्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी : दिमाग में मौजूद लगभग 86 अरब तंत्रिका कोशिकाएं (न्यूरॉन्स) आपस में जुड़कर सूचना ओं को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आगे बढ़ाती हैं। दिमाग की एक अनूठी क्षमता न्यूरोप्लास्टिसिटी है। जब भी आप कोई नया अनुभव, ज्ञान या भाषा सीखते हैं, तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं।

क्या है कॉग्निटिव रिजर्व

40 की उम्र के बाद दिमाग की कोशिकाएं और उनके बीच संपर्क बनाने वाले सिनैप्स कमजोर पड़ने लगते हैं। नए न्यूरॉन्स बनने की दर घट जाती है व कोशिकाओं में टॉक्सिक प्रोटीन जमा होने लगता है। इसके शुरुआती संकेत छोटी- छोटी बातें भूलने या फैसले लेने में भ्रम के रूप में दिखते हैं। ऐसे में कॉग्निटिव रिजर्व , दिमाग की वह क्षमता है, जिसके सहारे वह उम्र या किसी क्षति के बावजूद काम करने के वैकल्पिक तरीके अपना सकता है। यह रिजर्व दो चीजों से बनता है:

कठिन मानसिक चुनौतियां : ऐसी चीजें सीखना, जो दिमाग को कम्फर्ट जोन से बाहर निकालें। जैसे, यदि आप गणित में अच्छे हैं, तो चित्रकारी सीखें; अगर भाषा प्रेमी हैं, तो कोडिंग या शतरंज सीखें। इससे नए सिनैप्स बनते हैं।

कार्डियोवैस्कुलर और मस्कुलर हेल्थ : पैरों और शरीर की कसरत करने से दिमाग में खास हार्मोन्स बनते हैं, जो याद्दाश्त के केंद्र हिप्पोकैम्पस को सिकुड़ने से रोकते हैं।

दिमाग को कैसे बनाए रखें जवान

बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. विजयनाथ मिश्रा बताते हैं कि दिमाग को जवान रखने का सबसे कारगर तरीका है उसे व्यस्त रखना। आपकी जिज्ञासा ही दिमाग की धार को कुंद होने से रोकती है।

1. नया और कठिन सीखें : कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें, नई भाषा, ड्राइविंग या डांस सीखें। जब दिमाग किसी नए काम से जुड़ता है, तब नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं।

2. व्यायाम : दौड़ना, तैरना या तेज पैदल चलना मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। इससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सहारा देने वाले प्रोटीन का स्राव होता है। योग चिकित्सक विनय भारती के अनुसार, ध्यान व प्राणायाम से दिमाग मजबूत होता है। शोध में इसे करने से दिमाग के ग्रे मैटर में भी वृद्धि देखी गई है।

3. गहरी नींद : नींद के दौरान मस्तिष्क का ग्लिम्फैटिक तंत्र सक्रिय रहता है, जो विषैले पदार्थ बाहर करने में मदद करता है। कुछ टॉक्सिन अल्जाइमर का खतरा बढ़ाते हैं।

4. सामाजिक जुड़ाव : लोगों से मिलना-जुलना व अकेलेपन से दूर रहना दिमाग को सक्रिय रखता है।

5. एंटी-इन्फ्लेमेटरी डाइट : ओमेगा-3 फैटी एसिड (अखरोट, अलसी), हरी सब्जियां व बेरीज दिमाग की सूजन कम करने में मददगार माने जाते हैं।

6. सही रक्त संचार : डब्ल्यूएचओ ने संज्ञानात्मक गिरावट और डिमेंशिया का जोखिम कम करने के लिए नियमित व्यायाम, तंबाकू से दूरी, संतुलित पोषण, उच्च रक्तचाप और मधुमेह पर नियंत्रण तथा सुनने की क्षमता, अवसाद और वायु प्रदूषण जैसे जोखिम कारकों पर ध्यान देने की सलाह दी है।



दिमागी सेहत से जुड़े मिथक

1. सुडोकू व पहेलियां हल करने से दिमाग तेज होता है
सच : सुडोकू खेलने से आप केवल सुडोकू खेलने में बेहतर बनते हैं, इससे पूरा दिमाग या ग्रे मैटर मजबूत नहीं होता। ये गेम्स एक तरह के पैटर्न पर काम करती हैं, जब तक दिमाग को कोई नई चुनौती नहीं मिलती, तब तक नए न्यूरॉन्स नहीं बनते।

2. दिमागी थकावट मतलब दिमाग की तेजी
सच : केवल मानसिक तनाव से कॉग्निटिव रिजर्व नहीं बनता। शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों का होना भी जरूरी है।

3. मल्टीटास्किंग से दिमाग सक्रिय रहता है
सच : एक साथ कई काम करना प्रीफ्रंटल कॉर्टिक्स पर दबाव बढ़ाता है। इससे स्ट्रैस हार्मोन बढ़ता है। मल्टीटास्किंग से बढ़ती उम्र में दिमाग की प्रोसेसिंग क्षमता में कमी आती है।

4. सप्लीमेंट्स खाने से दिमाग बूढ़ा नहीं होगा
सच : कोई भी दवा उम्र के साथ होने वाली गिरावट को अकेले नहीं रोक सकती। जब तक रक्त वाहिकाओं की अच्छी सेहत न हो, सप्लीमेंट्स का कोई बड़ा असर नहीं पड़ता।

कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है?

बढ़ती उम्र में कभी-कभार चाबी या चश्मा रखकर भूल जाना या नया सीखने में देर लगना सामान्य हो सकता है। अगर आप हाल की बातचीत भूलने लगे, परिचित जगहों पर रास्ता भटकने लगे या निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्ट बदलाव दिखे, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। याद्दाश्त में कमी का कारण हमेशा अल्जाइमर रोग या डिमेंशिया नहीं होता। कुछ दवाएं, नींद की समस्या, अवसाद व विटामिन बी12 की कमी भी इसकी वजह हो सकती हैं।

इन ब्रेन फूड का करें सेवन



हल्दी (करक्यूमिन) : दिमाग में टॉक्सिक प्रोटीन (एमिलॉइड प्लेक) जमा होने से रोकने और सूजन कम करने में मददगार।



अखरोट व अलसी : ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर, जो ब्लाड ब्रेन मैटर और न्यूरल कनेक्शंस को मजबूती देते हैं।



हरी पत्तेदार सब्जियां : पालक, मेथी आदि में विटामिन-के, ल्यूटिन और फोलेट भरपूर होता है, जो दिमाग की सेहत के लिए जरूरी तत्व हैं।



ब्राह्मी व शंखपुष्पी : इन जड़ी- बूटियों का इस्तेमाल याददाश्त, एकाग्रता और मानसिक शांति को बढ़ाया देने के लिए किया जाता है।

देखभाल

सोरायसिस के लक्षणों को अनदेखा न करें

सोरायसिस त्वचा से जुड़ी एक ऑटोइम्यून बीमारी है। यह किसी भी उम्र व त्वचा के रंग के लोगों को हो सकती है। फिलहाल इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, पर नई दवाओं और जीवनशैली में बदलाव से इसे काबू कर सकते हैं।



सोरायसिस में त्वचा की कोशिकाएं बहुत तेजी से बनने लगती हैं। त्वचा उन्हें सामान्य गति से हटा नहीं पाती। नतीजतन, त्वचा की सबसे ऊपरी परत पर मृत कोशिकाएं जमा होने लगती हैं। त्वचा पर मोटी, पपड़ीदार परतें जमा होने लगती हैं और चकते बन जाते हैं। इस बीमारी में आनुवंशिक कारक भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

इस बीमारी के लक्षण

- त्वचा पर उभरे हुए, पपड़ीदार चकते
- त्वचा रूखी होना और उसमें दरारें पड़ना व खून निकलना
- त्वचा पर जलन, खुजली और दर्द
- जोड़ों में सूजन या दर्द
- नाखूनों में छोटे गड्ढे पड़ना या उनका फटना।

जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. गुंजन अग्रवाल के अनुसार, सोरायसिस की समस्या गठिया, मोटापा, मधुमेह व हृदय तंत्र से भी जुड़ी हो सकती है। अगर त्वचा पर ये लक्षण दिखाई दें, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए।

उपचार स्थिति पर निर्भर

1. दवाएं : ये दवाएं सीधे प्रभावित त्वचा पर लगाई जाती हैं। इन्हें शुरुआती उपचार के रूप में दिया जाता है। ये क्रीम, लोशन और फोम के रूप में उपलब्ध होती हैं। इनमें त्वचा पर लगाने वाले स्टेरॉयड भी शामिल हैं, जो त्वचा में सूजन और प्रतिरक्षा तंत्र की गतिविधि को कम करने में मदद करते हैं। इनका ज्यादा इस्तेमाल त्वचा को पतला कर सकता है, इसलिए इन्हें डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए।

2. बायोलॉजिकल दवाएं : डॉ. गुंजन के अनुसार, ये आधुनिक दवाएं जैविक स्रोतों से तैयार की जाती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र के खास हिस्सों को लक्षित करके सूजन कम करती हैं। इन्हें आमतौर पर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है।

3. ओरल रेटिनॉइड्स : ये विटामिन ए से संबंधित दवाएं हैं, जो त्वचा की कोशिकाओं के बढ़ने और परिपक्व होने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

4. सैलिसिलिक एसिड : यह त्वचा पर जमी पपड़ी को नरम करने और उसे हटाने में मदद करता है। इसका अधिक या अनुचित इस्तेमाल त्वचा में जलन पैदा कर सकता है।

5. कोल टार युक्त मलहम और शैंपू: कोलटार सोरायसिस के पुराने उपचारों में से एक है। यह खुजली, सूजन और त्वचा पर जमी पपड़ी कम करने में मदद कर सकता है।

6. फोटोथेरेपी : इस उपचार में त्वचा को नियंत्रित मात्रा में पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है। इसे चिकित्सकीय निगरानी में किया जाता है। प्राकृतिक धूप में लंबे समय तक रहना फोटोथेरेपी का विकल्प नहीं है।

त्वचा रोग विशेषज्ञ से कब मिलें?

त्वचा रोग विशेषज्ञ सबसे पहले, त्वचा पर बने चकतों और घावों की जांच करेंगे। साथ ही, वे आपकी चिकित्सा संबंधी पिछली जानकारी भी जानेंगे। इस दौरान वे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे- क्या त्वचा पर खुजली होती है? क्या नाखूनों से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे उनका मोटा होना या पीला पड़ना? क्या जोड़ों में सूजन या अकड़न महसूस होती है? क्या परिवार में किसी को सोरायसिस रहा है या हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है?

सवाल-जवाब

स्ट्रोक में समय की अहमियत



डॉ. राजिंदर के धमीजा
प्रोफेसर, न्यूरोलॉजी विभाग और प्रमुख इश्वर हॉस्पिटल, नई दिल्ली

सवाल : पिछले दिनों मेरे एक सहकर्मी को अचानक बोलने में परेशानी हुई और उनके चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा हो गया। उनकी उम्र 54 साल है। कुछ देर बाद वे सामान्य हो गए। क्या ऐसी स्थिति में अब भी अस्पताल जाना जरूरी है?

जवाब: यह स्ट्रोक के प्रमुख संकेत हैं। कुछ देर बाद लक्षण ठीक हो जाएं, तब भी इन्हें अनदेखा न करें। यह मिनी स्ट्रोक यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक (टीआईए) हो सकता है, जिसमें दिमाग के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित होती है। इसे भविष्य में होने वाले गंभीर स्ट्रोक की चेतावनी माना जाता है। ऐसे में तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। डॉक्टर मस्तिष्क की इमेजिंग, रक्त वाहिकाओं की जांच, हृदय गति और खून के थक्के की स्थिति का आकलन करते हैं। इससे दोबारा स्ट्रोक आने का जोखिम कम किया जा सकता है।

सवाल : स्ट्रोक के इलाज में कितने बदलाव आ चुके हैं। क्या हर मामले में सर्जरी जरूरी है?

जवाब: पिछले 30 सालों में स्ट्रोक के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। जहां पहले इसे लाइलाज माना जाता था, वहीं आज इसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान में आई इस प्रगति के तहत, स्ट्रोक के शुरुआती 4.5 घंटों के भीतर मरीज को क्लॉट बस्टिंग दवाएं दी जा सकती हैं, जो दिमाग में जमे खून के थक्के को घुला देती हैं, इसीलिए मरीज को बिना देरी किए सही अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा मरीज को स्ट्रोक यूनिट में भर्ती कर खून पतला करने की दवाएं दी जाती हैं और जांच के जरिये थक्के के स्रोत या ब्रेन हैमरेज का पता लगाकर इलाज किया जाता है। जहां तक सर्जरी का सवाल है, तो इसका प्रयोग हर मामले में नहीं, बल्कि केवल सीमित और चुनिंदा स्थितियों में ही किया जाता है। यदि गर्दन की कैरोटिड आर्टरी में क्लॉट हो, तो स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी की जाती है और यदि क्लॉट बहुत बड़ा हो, तो दिमाग का दबाव कम करने के लिए 'डीकंप्रेसिव क्रेनिएक्टमी' सर्जरी करते हैं; वहीं नसों के फटने से मैसिव ब्रेन हैमरेज होने की स्थिति में मरीज की जान बचाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है।

सवाल : मेरी उम्र 40 साल है, परिवार में कम उम्र में स्ट्रोक के मामले रहे हैं और बीपी भी बढ़ता है। किन जांचों की जरूरत है?

जवाब: हमारे देश में एक तिहाई स्ट्रोक युवा लोगों को आते हैं। हालांकि, परिवार में स्ट्रोक का इतिहास होने का अर्थ यह नहीं कि आपको भी ऐसा होगा। हां, पर सावधान रहना जरूरी है। आप डॉक्टर से मिलकर परिवार में स्ट्रोक होने की उम्र, उसके संभावित कारण और सेहत संबंधी जोखिमों की जानकारी साझा करें। आमतौर पर डॉक्टर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी व परिवार के इतिहास व लक्षणों के आधार पर गर्दन या दिमाग की रक्त वाहिकाओं की इमेजिंग या कुछ अन्य विशेष रक्त जांचों की सलाह दे सकते हैं। ये सभी जांचें हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं हैं। स्ट्रोक का जोखिम कम करने के लिए नमक सीमित रखें, नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान से बचें, वजन काबू रखें और बीपी काबू रखें। अपने आप खून पतला करने वाली दवा शुरू न करें।

सवाल : क्या स्ट्रोक का इलाज केवल शुरुआती साढ़े चार घंटे में ही संभव है?

स्ट्रोक में समय बेहद महत्वपूर्ण है, पर साढ़े चार घंटे बीतने के बाद भी उपचार संभव हो सकता है। उन्नत इमेजिंग जांचों से मस्तिष्क की स्थिति का आकलन कर कुछ मरीजों को साढ़े चार से नौ घंटे के भीतर थक्का घोलने वाली दवा दी जा सकती है। वहीं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टॉमी में कैथेटर से थक्का निकालने की प्रक्रिया लक्षण शुरू होने के 24 घंटे तक लाभकारी हो सकती है। इसके लिए कई जांचें की जाती हैं, इसलिए लक्षण दिखते ही मरीज को तुरंत स्ट्रोक उपचार की सुविधा वाले अस्पताल ले जाना चाहिए।

भेजें अपने सवाल

सेहत से जुड़े सवाल
tanmanhindustan@gmail.com पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं- **तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, 2 आर्कोन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, 201301**

रोजनामचा



पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी रहेगा। पढ़ाई के कार्यों में सफल रहेंगे। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी।

वृष : वाणी में मधुरता तो रहेगी, परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, परंतु कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

मिथुन : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। बातचीत में संतुलित रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आय में वृद्धि भी होगी।

कर्क : पठन-पाठन में रुचि रहेगी। पढ़ाई के कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र बढ़ेगा।

सिंह : मन प्रसन्न तो रहेगा, परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। कारोबार में मामूली अधिक रहेगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। कारोबार में सुधार के लिए पिता व किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है।

तुला : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। अफसरों का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी, परंतु स्थान परिवर्तन हो सकता है।

वृश्चिक : मन परेशान रहेगा। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि व आय में कमी हो सकती है।

धनु : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। माता की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टप्रद रहेगा। खर्च बढ़ेंगे। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ में वृद्धि हो सकती है।

मकर : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। संयत रहें और धैर्य लीला बनाए रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।

कुंभ : मन प्रसन्न तो रहेगा, फिर भी मन में नकारात्मक विचारों से बचें। नौकरी में तरक्की के साथ स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। आय में वृद्धि होगी।

मीन : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। पढ़ाई के काम के सुखद परिणाम मिलेंगे। कारोबार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पिता से धन मिल सकता है।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषभकांत गोस्वामी

30 अक्तूबर, शुक्रवार, शक संवत् : 08 कार्तिक (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 14, कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 18 जमादि उल्लाल,1448, विक्रमी संवत् : कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि सायं 07 .26 बजे तक पश्चात षष्ठी तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र प्रात: 09 .05 बजे तक पश्चात आर्द्रा नक्षत्र, शिव योग रात्रि 08 .42 बजे तक पश्चात सिद्ध योग, कौलव करण, चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन-रात)।

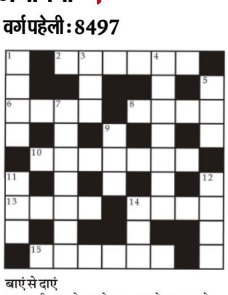
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। प्रात: 10 .30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

घर में अचानक बहुत समस्याएं आने लगें, तो करें ये उपाय :

- प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होना ठीक है, किंतु घर में घुसते ही सेप्टिक टैंक होना या गंदगी का गड्ढा होना ठीक नहीं होता। इसे हटाना चाहिए।
- घर में बहुत सारी पुरानी अलमारियां हैं, या ऐसी अलमारी है, जिसकी लकड़ी फूल गई है, तो उन्हें हटा दें। इससे जीवन की गति एवं धन प्रभावित होता है।
- यदि आपकी दीवारों एवं छतों का प्लास्टर जगह-जगह से उखड़ है, तो यह समस्याओं को बढ़ाता है। इससे संबंध, स्थिति, परिस्थिति सब प्रभावित होती है। बहुत पुराने मकान यदि समय पर मेंटेन नहीं किए जाएं, तो उनमें वास्तु दोष बढ़ जाता है।

वर्ग पहेली : 8497



बाएं से दाएं
2. अच्छी तरह से जानते हुए; समझते हुए; जानते-बूझते हुए; संकल्पपूर्वक (6)
6. तीता; तीखे स्वादवाला; तेज (4)
8. आवाज देना; बुलाना; ऊंचे स्वर में संबोधन करना (4)
10. अनुरक्त करना; खींचना; प्रभावित करना (4,3)
13. समझाना; सूचना देना; इश्तिहार; प्रकाशित की गई सूचना; प्रचार पत्र (4)
14. बनने या बनाने का भाव; संरचना; दिखावा (4)
15. खिंचाव का कारण; तनाव करने वाला; तनावकारी; तनाव पैदा करने वाला (6)

ऊपर से नीचे
1. स्थिर; अचल; अटल (4)
3. चोचला; दिखावटी, इनकार; रूप अभिमान; हाव-भाव (3)
4. किसी भी योग्य न रहना; सब तरफ से ठुकराया जाना; सभी पक्षों द्वारा तिरस्कृत होना (2,1,1,3)
5. खराबी; तबाही; नाश; हानि (3)
7. पलक का नीचे की ओर गिरना उठना; देखते रह जाना; हैरान होना (3,4)
9. घात करने वाला; जान लेवा; शत्रु; हत्यारा; हिंसक (3)
11. मन:स्थिति जिसमें किसी एक बात का निश्चय न हो रहा हो; चित्त की अस्थिरता; अनिश्चितता; असमंजस; चिंता; संशय (3)
12. अनुमान; कल्पना; अंदाज; कयास; तखमीना (4)
14. बसंत; विकास; शोभा; सौंदर्य; प्रफुल्लता (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8496



सुडोकू : 8451 *कठिन

		5				7		
	9	1				8		
				2		5		6
			7				3	8
	7					2		
9	8			4				
8		3		5				
		4				6	5	
	5			1				

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की सही संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8450

8	5	2	4	7	6	1	3	9
1	6	3	2	8	9	4	5	7
4	9	7	5	3	1	6	8	2
3	8	6	9	5	7	2	4	1
5	7	4	3	1	2	8	9	6
2	1	9	6	4	8	5	7	3
7	3	5	1	2	4	9	6	8
9	4	1	8	6	3	7	2	5
6	2	8	7	9	5	3	1	4

संपादकीय

कौल नव्हे, कोंडी !

इस्रायलमध्ये मतदारांनी कौल दिला खरा; पण तो कोंडी निर्माण करणारा ठरला! हमासच्या इस्रायलवरील ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या हल्ल्यानंतरची ही पहिली निवडणूक पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वावरील सार्वमत मानली जात होती. मतदारांनी त्यांना नाकारलेही नाही आणि स्वीकारलेही नाही. नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे खटले, गाझा युद्ध आणि इराणशी संघर्ष यांच्या सावटाखाली झालेल्या या निवडणुकीने इस्रायलमधील दुभंग उघड केला आहे. आतापर्यंतच्या मतमोजणीनुसार १२० सदस्यांच्या 'नेसेट'मध्ये नेतन्याहू यांच्या पक्षाला ५३ जागा मिळू शकतात. गादी आयझेनकॉट यांचा 'यशर', नफ्ताली बेनेट व याइर लापिड यांचा 'बीयाचाड', तसेच अविग्डोर लिबरमन व याइर गोलान यांचे पक्ष मिळून विरोधकांना ४८, तर अरब पक्षांना विक्रमी ९ जागा मिळण्याची चिन्हे आहेत. सैनिकांची मते अद्याप मोजायची असल्याने एक-दोन जागा इकडेतिकडे होऊ शकतात. अधिकृत निकाल ४ नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे. कोणत्याही पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व आघाडीला बहुमताची संख्या ६१ हा आकडा गाठता आला नाही, तर राष्ट्राध्यक्ष यित्झाक हर्झोग बहुमताच्या सर्वाधिक नजीक असलेल्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करतील. त्याला २८ दिवस मिळतील आणि ९४ दिवसांची मुदतवाढ शक्य असते. त्याला अपयश आल्यास दुसऱ्याला संधी मिळेल. सर्व प्रयत्न फसल्यास पुन्हा निवडणूक होईल. तोवर नेतन्याहू काळजीवाहू पंतप्रधान असतील. मतमोजणीनंतरचे चित्र पाहता सरकार स्थापनेचे चार मार्ग दिसतात. लिकुड सर्वांत मोठा पक्ष असला तरी, नेतन्याहू यांना बहुमताशी विरोधी पक्षांत फूट पाडावी लागेल. आयझेनकॉट यांना सत्तेसाठी अरब पक्षांची साथ लागेल; पण बेनेट आणि लिबरमन यांचा त्याला ठाम नकार आहे. आयझेनकॉट यांचाही अरब पक्षांशी औपचारिक आघाडीला विरोध आहे. नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली आळीपाळीच्या व्यवस्थेसह संयुक्त सरकारही आयझेनकॉट यांना अमान्य आहे. त्यामुळे उरतो केवळ चौथा मार्ग आणि तो म्हणजे पुन्हा निवडणूका अरब पक्षांकडे किल्ली आहे; पण कुलूप उघडायला कुणीही तयार नाही. विक्रमी अरब मतदानाआधी नेतन्याहू यांनी अरब मतदार निवडणूक 'चोरतील', असा इशारा दिला होता. आज तीच मते सत्तेच्या गणितात निर्णायक ठरत आहेत. नेतन्याहू त्यांना झायोनिझमविरोधी ठरवतात. अरब 'राम' पक्षाला २०२१ मध्ये सरकारमध्ये घेणारे बेनेट आज मात्र अरब पक्षांना नको म्हणत आहेत. गोलान सहभागाचे समर्थन करतात, तर 'जॉइंट लिस्ट' या अरब पक्षांच्या आघाडीने नेतन्याहू यांना हटविण्यासाठी वाट मोकळी करण्याची तयारी दाखवली आहे. हमासला दहशतवादी संघटना म्हणण्याबाबतची अरब पक्षांची अनिच्छा हा आणखी एक अडसर आहे. सरकार स्थापनेबाबत अनिश्चितता असली तरी, कोणतेही सरकार आल्याने इस्रायलच्या पराराष्ट्र धोरणात फार फरक पडणार नाही, हे मात्र निश्चित! अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खासगीत नेतन्याहू यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त असतानाही त्यांना जाहीर पाठिंबा घोषित केला होता. दुसरीकडे आयझेनकॉट यांनी ट्रम्प यांच्याविषयी आदर व्यक्त केला आहे. उभय देशांसाठी व्यक्तिगत संबंधांपेक्षा राष्ट्रहित महत्त्वाचे आहे, हा त्याचा अर्थ! त्यामुळे नेतृत्वबदल झाला तरी अमेरिका-इस्रायल सहकार्य थांबणार नाही. भारताचेही इस्रायलसोबतचे संबंध पक्षनिरपेक्ष आहेत. फेब्रुवारीतील पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यात संरक्षण, कृषी, तंत्रज्ञानासह मुक्त व्यापार करार आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (आयमेक)वर भर होता. हे हितसंबंध कोणया एका नेत्यावर अवलंबून नाहीत; मात्र राजकीय अस्थिरतेमुळे वाटाघाटींचा वेग मंदावू शकतो. नेतन्याहू टिकले तर अब्राहम करार कायम राहतील; पण पॅलेस्टिनी राज्याचा विश्वासार्ह मार्गाविना सौदी अरेबियासोबतचे संबंध सामान्यीकरण दूरच राहील. निवडणूक जिंकल्यास इराणसोबत पुन्हा युद्ध सुरू करण्याचे सूतोवाच नेतन्याहू यांनी केले होते; पण आयझेनकॉट यांचा सूर तुलनेत संयत आहे. आयझेनकॉट गरज पडल्यास इराणवरील लष्करी कारवाईचे समर्थक असले, तरी तेहरानमधील सत्ताबदल लष्करी बळावर अशक्य असल्याचे ते अलीकडेच म्हणाले होते. इस्रायलमध्ये नवे सरकार आले तरी इराण व पॅलेस्टाइनसंदर्भातील धोरणात आमूलाग्र बदल संभवत नाही. सध्या तरी इस्रायलमधील कोंडी लवकर सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आकड्यांचा खेळ संपला आहे आणि आता राजकीय इच्छाशक्तीची कसोटी आहे. या काळात भारताने कोणत्याही नेत्याशी, पक्षाशी वैयक्तिक जवळीक न दाखवता, संस्थात्मक संबंध, मुक्त व्यापार वाटाघाटी आणि 'आयमेक'वर लक्ष केंद्रित करणे आणि आखाती देशांशी संतुलन जपणे गरजेचे आहे.

भाजपला दणका, युतीला धक्का, काकांची जिगर !

नागपूर, पुण्याचा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला, भाजप-शिंदेसेनेतील वादांनी महायुतीला धक्का बसला, काकांनी मात्र 'जिगर' दाखवून दिली !



यदु जोशी
राजकीय संपादक, लोकमत

विधान परिषद निवडणुकीत नागपूरात भाजपने भाजपचा पराभव केला. काँग्रेसपेक्षा रणनीतीत भाजप कमी पडला. पहिल्या पसंतीच्या आधारे सुधाकर कोहळे चार हजारांवर मतांनी पुढे होते. दुसऱ्या पसंतीने त्यांचा घात केला. नितेश कराळेंना पहिली पसंती दिलेल्या बहुतेकांनी दुसरी पसंती काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांना दिली. खरेतर कोहळे अन् कराळे एकाच 'सिरिज'चे, वंजारी वेगळ्या 'सिरिज'चे पण लोकांनी सिरिज वगैरे पाहिली नाही; कोहळेंचा बल्ब फ्यूज केला. दुसऱ्या पसंतीची आठ-दहा हजार मते भाजपने अन्य उमेदवाराकडे वळवलीच नाहीत; आपण पहिल्या पसंतीच्या आधारेच जिंकू, या भ्रमात ते राहिले अन् आपटले. अनिल सोले शांत झाले, पण त्यांच्या निमित्ताने पक्षात निर्माण झालेली खदखद कायम राहिली; त्याचे चटके कोहळेंना बसलेच. कोहळेंच्या बंडखोरीसाठी सोलेंना सुरुवातीला ताकद देण्यात कोणकोण होते, याचा नीट तपास केला तर धक्कादायक नावे येतील. गिरीश व्यास उघडपणे समोर आले होते एवढेच.

आणखी एक... गडकरी, फडणवीस, बावनकुळेंच्या नागपूरात भाजपच्या उमेदवारावर दुसऱ्या फेरीपर्यंत रखडण्याची पाळी आली आणि पराभवही पत्करावा लागला ही आत्मचिंतनाची बाब आहे. अभिजित वंजारींचे टोपणनाव बिट्टू. त्यांच्यावर बिट्टू म्हणून प्रेम करणारे सर्वपक्षीय मित्र आहेत; त्यांचा हातभारही लागलाच असेल. मात्र, वंजारी यांच्या विजयात त्यांची स्वत:ची मेहनत आणि नम्र स्वभावाचा वाटा सर्वाधिक आहे. एक मात्र खरे की, आता वंजारी जिंकले म्हणून काँग्रेस आ गई, काँग्रेस उभी गई, वगैरे कोणी समजू नये. 'अभी नागपूर से वाडी तक पहुचे है, अमरावती बहोत दूर है,' नागपुरात काँग्रेसने भाजपला दिलेला दणका ही पुनरागमनाची सुरुवात असू शकते; पण तो संपूर्ण पुनरुत्थानाचा दाखला नाहीच. कदेम नागपुरातच नाही तर अन्य निकालातही एमपीएससी घोटाळा, विविध आंदोलनांच्या निमित्ताने उद्भवलेली नाराजी फरक झाली.

औरंगाबाद पदवीधरमध्ये सतीश चव्हाण यांच्या पराभवात त्यांचा स्वत:चा आणि भाजप, शिंदेसेनेच्या काही नेत्यांचा निश्चितपणे वाटा आहे. अतिआत्मविश्वासही नडला. चव्हाण हे महायुतीचे उमेदवार होतेही आणि नव्हतेही. मित्रपक्ष सोबत आहेत म्हणजे एक अधिक दोन असे तीन होतील, असे त्यांना वाटले, पण राजकारणात नेहमीच तसे होत नसते. चव्हाण यांच्याबाबत 'अँटिइन्कमबन्सी' होतीच. शरद पवार गटाचे प्रतापसिंह पाटील यांना निवडून देण्यामागे सतीश चव्हाणांचा पराभव करायचाच ही भावना अधिक होती. ही जागा आणि पुणे पदवीधरची जागा जिंकून शरद पवार यांनी 'मी अजूनही आहे' हे घरच्यांना आणि बाहेरच्यांनाही दाखवून दिले आहे.



पुणे पदवीधरमध्ये ऐनवेळी लादलेल्या उमेदवारामुळे भाजपमध्येच नाराजी होती. शिंदेसेनेने अपेक्षित साथ दिली नाही. विधान परिषद निकालाने राज्यातील राजकीय चित्र बदलेल, अशी कोणतीही शक्यता नाही. पण सत्तारूढ महायुतीला या निकालाने काही धडे दिलेच आहेत. 'पक्षाला आत्मचिंतनाची गरज आहे,' असे राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटलेच आहे. काकांनी प्रभाव सिद्ध केलेला असताना पुतणे कुटुंबाला अधिक सावध राहून पुढे जावे लागेल.

या निमित्ताने काही निरीक्षणे अशी -

१) वाडवडील, घराण्याची पुण्याई निश्चितपणे कामाला येते. पण त्याचवेळी वाडवडिलांनी केलेल्या चुका, लोकांना दिलेला त्रास याचे दुष्परिणामदेखील सहन करावे लागतात. दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघांतील दोन महिला उमेदवारांबाबत ही प्रचिती आली. वारश्याने आपल्याकडे चांगूलपणा येते तसे काही वाईटपणदेखील येत असते. ते काही वेळा त्रास देते. तुमच्याकडे आधीच्यांची पुण्याई खूप असेलही, पण निवडणुकीच्या वेळी पूर्वसुरींच्या अल्पशा चुकादेखील आडव्या येतात. ज्येष्ठांनी कमावलेली प्रतिष्ठा पुढच्या पिढीला सावली देते; पण त्यांनी दिलेल्या जखमा काटे बनून वाट अडवतात.

२) महायुतीने जिंकलेले दोन मतदारसंघ असे आहेत की, जिथल्या विजयी उमेदवारांना भाजपमध्ये आणून तिकीट दिले पाहिजे, असा एक मोठा प्रवाह होता. प्राथमिक बोलणीदेखील झाली होती. पण एका मतदारसंघात एका प्रवाहाची अशी भावना झाली की, हा आपल्या पक्षात आला तर आपल्यालाच पुढे अडचणीचे ठरेल, म्हणून त्याला रोखले पाहिजे. 'निष्ठावंतांला, कार्यकर्त्यालाच संधी द्या,' असा आग्रह धरत हमखास विजयी होईल, अशा उमेदवाराची आयात रोखली गेली. एका उमेदवाराने (महिला की पुरुष तुम्हीच ओळखा) भाजपकडे दोन वर्षांपूर्वी उमेदवारी मागितली होती. पण ती व्यक्ती खूप शिष्ट आहे; आपल्या संस्कृतीत बसणार नाही, असे तिच्याबाबत कान भरून तिला रोखले गेले. दोन्ही प्रवेश झाले असते तर आज निकाल कदाचित वेगळा राहिला असता.

३) अमरावतीचे नाव उगाच बदनाम होऊन राहिले. पैसा कुठे नाही चालला? त्या मानाने अमरावतीचा पिचर लो बजेट होता. शिक्षक, पदवीधरही पाकिटे घेतात म्हणून बोंब सुरू आहे. त्याच्या मुळाशी जाऊन पाहा. बेरोजगारीत पाच-पंचवीस हजार भेटले तर दिवाळी निभते नं भाऊ! विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, खासगी शाळा, महाविद्यालयांमधील शिक्षक दहा-दीस हजार रुपये महिन्यावर राबतात, त्यांच्यासाठी हा बोनस होता. देणाऱ्यांना लाज नव्हती अन् घेणाऱ्यांना लाजेपेक्षा पैसे मोठे होते. इतरांपेक्षा अमरावतीचे वेगळेपण हे होते की, सात-आठ हजार मतदारांचे अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग वर्षभरापूर्वीच करून ठेवण्यात आले होते.

yadu.joshi@lokmat.com

कामगारनामा

स्थलांतरित कामगारांनी 'गाव चलो' अभियान का सुरू केले?

सुरत हे देशातील वस्त्रोद्योगाचे महत्त्वाचे केंद्र, मात्र कारखानदारांनी तेथील कामगारांच्या मागण्या मान्य न केल्याने ते आपापल्या मूळ गावी परतू लागले आहेत.



डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत
स्थलांतर, कामगार विषयांचे अभ्यासक

गुजरातमधील सुरत हे देशातील वस्त्रोद्योगाचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. या उद्योगाच्या उभारणीत आणि विस्तारात उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा यांसह विविध राज्यांतून आलेल्या स्थलांतरित कामगारांचा मोठा वाटा आहे. विविध अंदाजांनुसार, सुरत जिल्ह्यातील वस्त्रोद्योगात सुमारे १२ ते १५ लाख स्थलांतरित कामगार कार्यरत आहेत. साधारणपणे ऑगस्टपासून हे कामगार दिवसाचे आठ तास काम, आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी आणि वेळेवर वेतन यांसारख्या मूलभूत मागण्यांसाठी संघटित होत आहेत. मात्र, या मागण्यांबाबत तोडगा न निघाल्याने कामगारांनी 'गाव चलो' अभियान सुरू केले असून, मोठ्या प्रमाणात हे कामगार आता आपापल्या मूळ गावी परतू लागले आहेत.

सुरतमधील कामगारांच्या मागण्या आणि कारखानदारांनी मांडलेले वेतनाचे पर्याय यांतील तफावत हा या संघर्षाचा महत्त्वाचा पैलू आहे. अलीकडील बैठकांमध्ये वस्त्रोद्योग मालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'टेक्सटाईल एम्प्लॉयडरी जॉबवर्क असोसिएशन ऑफ सूरत' (तेजस) या संघटनेने दोन पर्याय मांडले. पहिल्या पर्यायानुसार, आठ तासांची कामाची शिफ्ट आणि साप्ताहिक सुट्टी यांसह दरमहा १४,३०० रुपये वेतन, तर दुसऱ्या पर्यायानुसार, १२ तासांची शिफ्ट, दरमहा ३५,००० रुपये वेतन, साप्ताहिक सुट्टी आणि मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव होता. परिणामी, कमी कामाचे तास आणि साप्ताहिक सुट्टी मिळवण्यासाठी उत्पन्नात मोठी घट स्वीकारावी किंवा अधिक वेतनासाठी दीर्घ कामाची पाळी स्वीकारावी, अशी द्विधा परिस्थिती कामगारांसमोर उभी राहिली आहे.

खरं तर किमान वेतन, कामाचे तास आणि साप्ताहिक विश्रांती या परस्परविरोधी बाबी नसून, सन्मानजनक रोजगाराच्या एकमेकांना पूरक अटी असतात. त्यामुळे कामाचे तास कमी करण्याच्या मागणीबरोबरच किमान आणि नियमानुसार वेतन मिळण्याच्याही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दुसरीकडे, उद्योगांच्या उत्पादनखर्चाचा आणि स्पर्धात्मकतेचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. मात्र, उद्योगाची उत्पादकता टिकवण्याची संपूर्ण जबाबदारी कामगारांच्या वेळेवर आणि आरोग्यावर टाकता येणार नाही. यासोबतच, कामगारांच्या मागण्यांकडे केवळ उत्पादनखर्च वाढवणारा घटक म्हणून न पाहता, दीर्घकालीन औद्योगिक विकास आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे. कामाच्या तासांत बदल करताना वेतन, उत्पादकता आणि कामगारांचे हक्क यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.

'गाव चलो' या अभियानाकडे केवळ कामगारांनी नोकरी सोडून गावाकडे केलेले 'पलायन' म्हणून पाहता कामा नये. या अभियानाचे समाजशास्त्रीय महत्त्वही लक्षात घेतले पाहिजे. भौगोलिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता, रोजगारातील असुरक्षितता, कंत्राटी कामाचे स्वरूप, नोकरी गमावण्याची भीती आणि संघटनात्मक आधाराचा अभाव यांमुळे स्थलांतरित कामगार अनेकदा विखुरलेले असतात. अशा परिस्थितीत त्यांचे संघटित होणे आणि समान मागण्यांसाठी एकत्र येणे ही महत्त्वाची बाब आहे. 'गाव चलो' हे वैयक्तिक असंतोषाचे सामूहिक कृतीत रूपांतर होण्याचे आणि कामगारांमध्ये सामायिक हितसंबंधांची जाणीव निर्माण होण्याचे उदाहरण आहे. या अभियानामुळे उद्योगांचे स्थलांतरित कामगारांच्या श्रमावरील अवलंबित्व, कामगारांची सामूहिक सौदेबाजीची क्षमता आणि श्रमसंबंधांतील सत्तासमीकरणे या वास्तवावरही प्रकाश पडला आहे.

सुरतमधील वस्त्रोद्योग मालक आणि कामगार संघटनांमधील वाटाघाटी सुरू राहतील, मात्र, या घडामोडींपलीकडे जाऊन स्थलांतरित कामगारांच्या संरचनात्मक प्रश्नांकडे पाहणे आवश्यक आहे. गावात रोजगाराच्या पुरेशा संधी नसल्यामुळे हे कामगार शहरांकडे आले. शहरातही असुरक्षित रोजगार, दीर्घ कामाचे तास आणि सन्मानजनक कामाच्या अटींचा अभाव असेल, तर त्यांनी जायचे कुठे? गावाकडे परतल्यानंतर त्यांच्या रोजगाराचा आणि उपजीविकेचा प्रश्न सुटणार आहे का? शहरातील असुरक्षिततेतून गावाकडे परतणे आणि गावातील रोजगाराच्या अभावामुळे पुन्हा शहराकडे स्थलांतर करणे, या दुष्टचक्रात कामगारांची होणारी कुचंबणा समजून घेणे गरजेचे आहे. या प्रश्नाकडे ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थांना जोडणाऱ्या स्थलांतराच्या व्यापक संरचनेच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे.

rajputkdr@gmail.com

जगभर

'तुम्ही कोणाशी पंगा घेत आहात, माहीत आहे का?'

गल्लीतली भांडणं, एकमेकांची कॉलर पकडणं किंवा एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणं अशा घटना आपल्याला अपरिचित नाहीत. पण अशीच घटना अंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणि तेही संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत घडली तर? - तसं घडलं आहे खरं! त्यावरुनच सध्या संपूर्ण जगभरात चर्चा सुरू आहे.

अमेरिका आणि क्यूबा यांच्यात अनेक दशकांपासून सुरू असलेला संघर्ष आता पुन्हा चिघळला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत अमेरिकी दूत माइक वॉल्ट्झ आणि क्यूबाचे परराष्ट्रमंत्री ब्रुनो रॉड्रिग्ज पारिला यांच्यात झालेली शाब्दिक हाणामारी झाली की अख्ख सभागृह चकित झालं.

एवढंच नाही, ही शाब्दिक हाणामारी खरोखरच्या हाणामारीत परावर्तित होते की काय आणि दोन्ही नेते एकमेकांची गचांडी पकडून तिथंच मारामारी करतात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. दोघाही जणांनी एकमेकांना धमक्याही दिल्या. अमेरिकी दूत माइक वॉल्ट्झ यांनी तर 'तुम्ही कोणाशी पंगा घेत आहात, हे माहीत आहे का? नीट राहा' या शब्दांत ब्रुनो रॉड्रिग्ज यांना धमकावलं. या भांडणामुळे सभेचं कामकाजही काही काळासाठी स्थगित करावं लागलं.

क्यूबाविरोधातील अमेरिकेच्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या आर्थिक आणि व्यापारविषयक निर्बंधांचा निषेध करणाऱ्या प्रस्तावावर मतदान होण्यापूर्वी ही घटना घडली. अमेरिकी दूत माइक वॉल्ट्झ संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून बोलताना क्यूबाच्या नेत्यांवर कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार आणि ऐषारामी जीवनशैलीचे आरोप करत होते. त्यावेळी क्यूबाचे परराष्ट्रमंत्री ब्रुनो रॉड्रिग्ज पारिला त्यांच्या जवळ गेले आणि त्यांनी खोटं बोलत असल्याचा आरोप केला. अमेरिकी दूत सदस्य देशांवर क्यूबाविरोधात मतदान करण्यासाठी दबाव आणत



असल्याचाही दावा त्यांनी केला.

आपले आरोप अधिक ठळक करण्यासाठी वॉल्ट्झ यांनी क्यूबाचे माजी नेते फिडेल कॅस्ट्रो यांचं छायाचित्र दाखवलं. त्यात कॅस्ट्रो यांनी दोन रोलेक्स घड्याळं घातल्याचं दिसत होतं. प्रत्येक घड्याळाची किंमत चाळीस हजार डॉलरपेक्षा अधिक असल्याचा दावा वॉल्ट्झ यांनी केला. क्यूबा सरकारच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत या घड्याळांची एकूण किंमत सामान्य क्यूबन नागरिकाच्या पंचावन्न वर्षांच्या कमाईइतकी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

यानंतर त्यांनी क्यूबाचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष मिगेल डियाझ-कॅनेल यांचं छायाचित्र दाखवून तेही रोलेक्स घड्याळ वापरत असल्याचा आरोप केला. या वक्तव्यांमुळे क्यूबाच्या प्रतिनिधींनी आपल्या जागेवरूनच जोरदार विरोध सुरू केला.

वाद वाढत असताना क्यूबाचे प्रतिनिधी व्यासपीठाजवळ पोहोचले. त्यावर वॉल्ट्झ यांनी त्यांना मागे हटण्यास सांगितलं. 'मागे व्हा, राजदूत. ही हवाना नाही. तुम्ही मला धमकावू शकत नाही, तुम्ही कोणाशी पंगा घेत आहात, हे माहीत आहे का? ही अमेरिका आहे. ही तुमची साम्यवादी हुकूमशाही नाही. तुम्ही मला गप्प बसवू शकत नाही,' असं सुनावलं.

संयुक्त राष्ट्रांचे अध्यक्ष खलील्लुर रहमान यांनी परिस्थिती चिघळत असल्याचं पाहून सभेचं कामकाज स्थगित केलं. या घटनेनंतर क्यूबाचे परराष्ट्रमंत्री रॉड्रिग्ज पारिला यांनी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर वॉल्ट्झ यांच्यावर टीका केली. सार्वजनिक नळावरील भांडणासारखी या भांडणाचीही सध्या जगभरात चांगलीच चर्चा आहे.

जनमन

फटाकेमुक्त दिवाळीचा संकल्प करूया !



महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाने दडी मारल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पाण्याअभावी शेती धोक्यात आली आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा व पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला, लहान मुले आणि सर्वसामान्य नागरिक यांचे हाल होत आहेत. अनेक ठिकाणी दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या विदारक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनही विविध उपाययोजना करीत आहे. अशा वेळी आपण फटाके फोडून दिवाळी साजरी करणे कितपत योग्य आहे? दिवाळी हा आनंदाचा आणि मांगल्याचा सण आहे. मात्र, या आनंदोत्सवात फटाके फोडण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढते. फटाक्यांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण, वायुप्रदूषण आणि अस्वच्छता यांचा त्रास केवळ माणसांनाच नव्हे, तर पशुपक्ष्यांनाही सहन करावा लागतो. विशेषत: लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्वसनाचा त्रास असलेल्या व्यक्तींना या प्रदूषणाचा अधिक त्रास होऊ शकतो. अनेकदा फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगीने जीवितहानी आणि वित्तहानीही होते. परंतु, या घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आपण सुरक्षिततेबाबत पुरेशी काळजी घेतो का? आजच्या काळात दिवाळीचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी फटाके फोडणे हाच एकमेव पर्याय आहे का? शक्यतो फटाक्यांचा वापर टाळणे, मोठ्या आवाजाचे व धूर निर्माण करणारे फटाके न फोडणे, हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिक जबाबदार पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे आपण सारेच फटाकेमुक्त दिवाळीचा संकल्प करूया!

- चंद्रवीर वंशीधर यादव, तुळशेत पाडा, भांडूप (पश्चिम), मुंबई

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : janman@lokmat.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे



या वर्षीच्या अंकात १७

सिरिअल्स, चित्रपट, ओटीटी
अशा बक्कळ पैसे-प्रसिद्धी मिळवून देणाऱ्या व्यावसायिक ठिकाणी न जाता तुम्ही प्रायोगिक नाटकातले अपार कष्ट आणि पैशाची वानवा सतत सोसत असता, पुरेशा पैशाविना तुम्ही जगता कसे?
- हा प्रश्न मला अनेकदा विचारला जातो. त्याचे उत्तर मी फार कष्टाने शोधून काढले आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे मला ते सापडले आहे!
व्यवहार उत्तम कळणारा मी,
ठरवून बिनव्यवहारी राहिलो आहे.
पैशाचे मोल कळूनही मी माझे जगणे
त्याभोवती व्यापू दिलेले नाही.



लोकमत दीपोत्सव २०२६ हक्क घरी प्रकाश...

पैसा पुरेल, उरेल की सरेल?

अर्थपूर्ण भासे मज हा कलह जीवनाचा!
Money पेक्षा Meaning
मला कांकणभर जास्त महत्त्वाचे वाटते.
ख्यातनाम रंगधर्मी
अतुल पेठे
यांचे प्रांजळ आत्मकथन

तीन लाख प्रतींचा खप ओलांडणारा अंक नव्हे, उत्सव!

पाने सुमारे : २५६ | मूल्य : ४९९ रुपये
प्रसिद्धी : दिवाळीआधी | फोन आणि 91120 50500
lokmatdeepotsav
अधिक माहिती, ऑनलाईन खरेदीसाठी स्कॅन करा
deepotsav.lokmat.com | स्थानिक वृत्तपत्र विक्रेत्यांकडे उपलब्ध
अंक लवकरच प्रसिद्ध होईल
आजच आपली प्रत निश्चित करा

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८५८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०७ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४५७४८
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७७०७२४६ ● **ठाणे कार्यालय :** रेसर्व्ह ब्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४५९०५, २५३८५७४४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०७. फोन : ०२२ ४६०४५७४८ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● संपादक : **विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर** ● संपादक : **अतुल कुलकर्णी** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे व्यापारचिन्ह आहे.

प्रेरणा

कठिनाइयां मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराती हैं। -सेनेका

संपादकीय

नशाखोरी पर अंकुश लगाने में पैरेंट्स की भूमिका अहम

नशाखोरी ने केवल किसी व्यक्ति पर शारीरिक-मानसिक-आर्थिक असर डालती है, बल्कि पूरे परिवार का सुख-चैन छीन लेती है। पंजाब इसका उदाहरण है। बिहार में दस साल से शराबबंदी कानून है, लेकिन प्रभावी अमल की समस्या के कारण हर रोज औसतन 198 गिरफ्तारियों के बावजूद सैकड़ों लोग नकली शराब पीकर मरते रहे। उधर आसान धन की लालच में किशोर और युवा वर्ग का बड़ा हिस्सा शराब-अपराध में लिप्त पाया गया। शराब तस्करी से हासिल धन से हथियार खरीदकर बैंक लूटना, हत्या करना बढ़ गया। ताजा खबर है कि शराब मिलने की दिक्कत और बढ़ी कीमतों से नशेबाज अब ड्रग्स की ओर मुड़ गए हैं। चार साल में एनडीपीएस के मामले तीन गुना बढ़ गए। ड्रग्स की बरामदगी 2022 की कुल बरामदगी से पिछले पांच महीने में तीन गुना हो गई। दरअसल नशाखोरी सामाजिक दोष है, लिहाजा केवल कानून से इससे मुक्ति संभव नहीं। फिर इसके प्रति हर राज्य का समाज अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। यूरोपीय समाज कम अल्कोहल वाली शराब का सेवन करता है, जबकि भारत में उच्च अल्कोहल वाली शराब पी जाती है। गुजरात में इस बुराई को लेकर अलग भाव है, नार्थ-ईस्ट में अलग। साथ ही, ड्रग्स की सप्लाई पर प्रभावी नियंत्रण भी जरूरी है। हर घर में पैरेंट्स ही समय रहते बच्चों को इसके खिलाफ सचेत करें।

जीने की राह



पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

आत्मा पर टिकेंगे तो शरीर से करने वाले संघर्ष आसान होंगे

इस समय दो बड़ी समस्याएं चल रही हैं- महंगाई और बेरोजगारी। जेन-जी के 50% युवा पार्ट टाइम जॉब यानी दो नौकरियां कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि एक से काम चल नहीं रहा। बेरोजगारी, पर्यावरण, परिवार विघटन जैसी समस्याएं उनके जीवन में भी हैं। ऊपर से हाइब्रिड मोड पर लाइफ आ गई। एआई आने के बाद इंसान का नजरिया ही बदल गया। लोग कहते हैं एआई से नौकरियां चली जाएंगी, पर कुछ नौकरियां एआई के लिए भी हो रही हैं। पिछले दिनों विदेश यात्रा में किसी ने मेरा प्रवचन सुनकर मुझे सलाह दी कि आप कहें तो मैं एक एआई कंपनी में आपको जॉब दिला सकता हूं। वर्क फ्रॉम होम कर लेना। आप एआई को समझाना कि व्याकुल व्यक्ति को कैसे समझाया जाए, क्योंकि कई बार एआई इसमें चूक जाता है। अब बताइए हम जैसों को ऐसी नौकरी दी जा रही है! जीवन बड़े खतरनाक मोड़ों से गुजर रहा है। ऐसे में युवाओं को समझाया जाए कि जितना अधिक आत्मा पर टिकेंगे, शरीर से किए जाने वाले संघर्ष उतने ही आसान हो जाएंगे। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नया विचार • नौकरियों का परिदृश्य बदल रहा है

'मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा!' पर उसके बाद क्या करेगा?

रोजगार



चेतन भगत
अंग्रेजी के उपन्यासकार
chetan.bhagat@gmail.com

माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपने लगभग 60 हजार कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने के बदले विशेष पैकेज देने की पेशकश की है। जरूरी नहीं कि ये सभी कर्मचारी नौकरी छोड़ दें, लेकिन यह खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। हमारे देश में भी टेक सेक्टर- जो लंबे समय से नई नौकरियां पैदा करने के सबसे भरोसेमंद स्रोतों में से एक रहा है- चिंताजनक रुझान दिखा रहा है। स्टाफिंग कंपनी हान डिजिटल के अनुसार, भारत के आईटी-बीपीएम क्षेत्र में भर्ती किए नए स्नातकों की संख्या 2021-22 में अनुमानित 4 लाख से घटकर 2025-26 में 1.75 लाख रह गई। तकनीकी उद्योग में सृजित नई नौकरियों की संख्या भी 2021-22 के 4.45 लाख से घटकर 2025-26 में 1.35 लाख रह गई। यह 70 प्रतिशत की गिरावट है।

और इसके बावजूद भारतीय मध्यवर्ग का अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने का सपना कम नहीं हो रहा। एडकॉम रिसर्च द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के आधिकारिक डैशबोर्ड के आंकड़ों के आधार पर किए विश्लेषण के अनुसार, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में नए दाखिलों की संख्या 2021-22 के 9.2 लाख से बढ़कर 2025-26 में 13.5 लाख हो गई। जबकि आज यह स्थिति है कि इंजीनियरिंग में दस दाखिले होते हैं, तब जाकर एक को टेक-सेक्टर की नौकरी मिलती है।

बेशक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाला हर स्नातक आईटी सेक्टर में नौकरी नहीं करता। लेकिन पहले यह क्षेत्र इंजीनियरिंग स्नातकों के बड़े हिस्से को रोजगार देता था। अब आईटी सेक्टर में जॉब की संभावनाएं घट रही हैं। और इसके बावजूद इंजीनियरिंग में दाखिले लगातार बढ़ रहे हैं। 'मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा!' वाला सपना आज भी जिंदा है। कोई भी यह नहीं पूछ रहा कि 'उसके बाद क्या करेगा?'

आईटी में नए स्नातकों के लिए जो थोड़ी-बहुत नौकरियां बची हैं, उनमें वेतन कोई खास आकर्षक नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की बड़ी आईटी सेवा कंपनियों में नए कर्मचारियों को मिलने वाला सामान्य शुरुआती वेतन वर्षों से तीन से चार लाख रुपये सालाना के आसपास बना हुआ है। यह समस्या केवल आईटी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दफ्तरों में काम करने वाले पेशेवरों के रोजगार से जुड़े कई दूसरे उद्योग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि नए कर्मचारियों को आमतौर पर जो काम सौंपे जाते हैं, वे अपेक्षाकृत तयशुदा प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं। और इन्हें एआई बड़ी आसानी से कर सकता है।

मिसाल के तौर पर, एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बुनियादी कोडिंग, डीबगिंग, टेस्टिंग जैसे काम कर सकता है। कानूनी क्षेत्र में अनुबंधों की समीक्षा और मुकदमों से संबंधित शोध कर सकता है। कंसल्टिंग क्षेत्र में प्रजेंटेशन तैयार कर सकता है और ग्राहक सेवा में रोजमर्रा के सवालों के जवाब दे सकता है। इसका दूसरा पहलू भी है। जब आज के वरिष्ठ कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, तब उनकी जगह लेने के लिए पर्याप्त अनुभवी कर्मचारी नहीं होंगे। अगर आप नए स्नातकों को नौकरी ही नहीं देंगे, तो उन्हें काम का अनुभव कैसे मिलेगा?

आर्थिक उदारीकरण के बाद से भारतीय परिवार सफलता के एक जाने-पहचाने फॉर्मूले पर चलते आए हैं। मन लगाकर पढ़ाई करो। अच्छे अंक लाओ। अच्छे कॉलेज में दाखिला लो। डिग्री हासिल करो। कैम्पस प्लेसमेंट में नौकरी पाओ। वेतन कमाओ और आत्मनिर्भर बन जाओ। लेकिन अब एआई ने इस

एआई क्रांति हमें यह सबक सिखाने जा रही है कि अपने हाथों से काम करना कम्प्यूटर पर काम करने से कमतर नहीं है। जो बात मायने रखती है, वो ये है कि आपके पास कोई उपयोगी हुनर हो, आप उसमें दक्ष हों और उसके जरिये सम्मानजनक आजीविका कमा सकें।

दौड़ के नियम बदल दिए हैं। ऐसे में हमें अपनी सोच और करियर की योजना में बदलाव लाने होंगे। पहला बदलाव यह कि हर दिन एक घंटा एआई की दुनिया में हो रहे नए डेवलपमेंट्स को समझने में लगाएं। इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखें। नवीनतम एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्टिव काम करें। इस उभरती इंडस्ट्री के अनुरूप स्किल्स विकसित करें। आने वाले समय में एआई का क्षेत्र बड़ी तादाद में नई नौकरियां पैदा करने वाला है।

दूसरे, इंजीनियरिंग की डिग्री पाने का जुनून छोड़ें। पहले इंजीनियरिंग की डिग्री आपको नौकरी और प्रतिष्ठा दिलाती थी, लेकिन अब इसकी गारंटी नहीं रह गई है। और तीसरे, ब्लू-कॉलर जॉब्स को हिकारत की नजर से ना देखें। हर कोई ऑफिस में बैठकर काम करने वाली नौकरी करना चाहता है, जबकि यही नौकरियां एआई के कारण सबसे अधिक खतरे में हैं। हम ऐसे दौर की ओर बढ़ रहे हैं, जब एक प्लम्बर की नौकरी किसी प्रोग्रामर की नौकरी से ज्यादा सुरक्षित है। खुद ही सोचें कि बेहतर स्थिति में कौन है? हर महीने 80 हजार कमाने वाला एक ऑटोमोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन या इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर घर में बैठा बेरोजगार नौजवान?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • हर साल 2.7 ट्रिलियन डॉलर की क्षति से बचें

पर्यावरण से जुड़े प्रश्न युद्ध खत्म होने तक नहीं रुकेंगे

क्लाइमेट



मैरी रॉबिन्सन
आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति और यूएन में पूर्व पदाधिकारी

युद्ध, भू-राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक तंगी के दौर में यह बड़ी आसानी से मान लिया जा सकता है कि प्रकृति का संरक्षण जरूरी तो है, लेकिन उसकी तत्काल कोई अनिवार्यता नहीं। इसे तो शांतिकाल में भी किया जा सकता है। यह सोच घातक है। इन सर्दियों में जब दुनिया के नेता संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के लिए जुटेंगे तो उन्हें याद रखना चाहिए कि दुनिया की आधी से अधिक जीडीपी प्रकृति और उससे मिलने वाली सेवाओं पर निर्भर है। 9.5 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल फूड इंडस्ट्री गुणवत्तापूर्ण मिट्टी पर टिकी है। 1.5 अरब लोगों की आजीविका वनों पर निर्भर है। नदियां बाढ़ के पानी को खुद में समेटकर परिवहन के महत्वपूर्ण नेटवर्क को बनाए रखती हैं। प्रकृति वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसकी रक्षा करना राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

पर्यावरण से जुड़े प्रश्न मध्य-पूर्व और यूक्रेन में युद्ध खत्म होने तक इंतजार नहीं करेंगे। इस गर्मी में यूरोप में सूखे के कारण 2 से 3 अरब डॉलर की फसलें खराब हुईं। यह किसानों के लिए दोहरी मार थी, क्योंकि इससे पहले हीमुंज बंद होने से फर्टिलाइजर की कीमतों में भी 71% की बढ़ोतरी हो गई थी। युद्ध और चरम-मौसम की घटनाओं के मिले-जुले असर ने वैश्विक खाद्य कीमतों को 2022 के बाद के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पारिस्थितिकी तंत्र के आंशिक रूप से ध्वस्त होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर साल 2.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। भू-रागनीतिक अस्थिरता के बावजूद हम उन प्राकृतिक प्रणालियों को कमजोर करने का जोखिम नहीं उठा सकते, जिन पर हमारी अर्थव्यवस्थाएं निर्भर हैं। '30 बाय 30' की पहल आज पहले से कहीं अधिक अहम हो गई है। इसके तहत 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र की रक्षा एवं संरक्षण का लक्ष्य है।

प्रकृति की रक्षा करना संकटों को झेलने के सामर्थ्य और एकजुटता में निवेश करने जैसा है। यह खाद्य और जल सुरक्षा को सुदृढ़ करता है तथा जलवायु संकट से उबरने की क्षमता बढ़ाता है। साथ ही आजीविका, जनस्वास्थ्य और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है। वर्ष 2022 में सरकारों द्वारा ऐतिहासिक 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल बायो-डायवर्सिटी फ्रैमवर्क' के तहत अपनाया गया '30 बाय 30' लक्ष्य यह मानता है कि प्रकृति का संरक्षण सार्वजनिक हितों से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने में बुनियादी अहमियत रखता है।

'30 बाय 30' लक्ष्य की दिशा में दुनिया ने बीते चार वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 'कैम्पेन फॉर नेचर' के नए विश्लेषण से पता चलता है कि अब भूमि और देशों की सीमाओं के भीतर स्थित जल क्षेत्रों (इनलैंड वॉटर्स) के 20% हिस्से को 'प्रोटेक्टेड या कंजर्ड' के तौर पर निर्धारित कर दिया गया है। मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह लागू किया तो 2030 तक यह हिस्सा बढ़कर लगभग 27% हो सकता है, जो लक्ष्य के काफी करीब होगा। हालांकि समुद्र के मामले में प्रगति काफी धीमी रही है। महासागरों के केवल 10% हिस्से को औपचारिक रूप से संरक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। मौजूदा प्रतिबद्धताओं के अनुसार 2030 तक यह हिस्सा 12% तक ही बढ़ पाएगा। इससे भी बुरा यह है कि 'ट्रुगेदर फॉर द ओशन'

दुनिया की आधी से अधिक जीडीपी प्रकृति और उससे मिलने वाली सेवाओं पर निर्भर है। 9.5 ट्रिलियन डॉलर की फूड इंडस्ट्री गुणवत्तापूर्ण मिट्टी पर टिकी है। 1.5 अरब लोगों की आजीविका वनों पर निर्भर है. पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों को हम हल्के में नहीं ले सकते।

की ताजा रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के केवल 3.5% हिस्से को ही प्रभावी रूप से संरक्षित माना गया है।

'30 बाय 30' लक्ष्य हासिल करने के लिए अब केवल चार साल बचे हैं। लेकिन फिर भी दुनिया के पास इस लक्ष्य को पूरा करने का अवसर है। यह इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिबद्धताओं में से एक है। लेकिन सवाल है कि बीते समय की भरपाई के लिए हमें क्या करना होगा?

सबसे पहले तो यही कि सरकारों को प्रकृति के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करनी होगी। '30 बाय 30' लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर साल लगभग 100 से 180 अरब डॉलर की जरूरत होगी, जबकि फिलहाल इस दिशा में सालाना केवल 24 अरब डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। हमें समझना होगा कि यह खर्च महज लागत नहीं, बल्कि एक निवेश है।

(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक | पेटीएम : भारतीय फिनटेक कंपनी

पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द, फाउंडर का इस्तीफा भी हुआ, अब टॉप-3 फिनटेक कंपनी में पेटीएम

नवंबर 2017, पेटीएम वॉलेट के करीब 28 करोड़ खाते थे। उस समय देश में हर पांचवें व्यक्ति पर एक पेटीएम खाता था। फरवरी 2017 में पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा था कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के पास 20.2 करोड़ खाते हैं और पेटीएम के पास 19 करोड़। यानी खातों के मामले में एक स्टार्टअप देश के सबसे बड़े बैंक के बराबर पहुंच गया था।

हालांकि 7 साल बाद एक ऐसा दौर आया जब पेटीएम गंभीर संकट में फंसा। जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 29 फरवरी के बाद नए डिपॉजिट, वॉलेट टॉप-अप और फास्टैग रिचार्ज पर रोक लगा दी। आरबीआई ने उस बैंक को बंद कर दिया, जिस पर पूरा कारोबार टिका था। दो दिन में शेयर 36% गिर गया। करीब 18 हजार करोड़ रु. की बाजार वैल्यू साफ हो गई। 26 फरवरी 2024 को विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के पार्ट-टाइम नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। अप्रैल 2026 में पीपीबीएल का लाइसेंस रद्द हो चुका है। हालांकि कंपनी ने दूसरे बैंकों की मदद से कारोबार रुकने से बचा लिया है। यूपीआई हिस्सेदारी के आधार पर अब यह देश की तीसरी बड़ी फिनटेक कंपनी है।

• वर्तमान स्थिति

आज 1.04 लाख करोड़ रु. की कंपनी है पेटीएम

पेटीएम (मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड) वर्तमान में करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाली भारतीय कंपनी है। विदेश में व्यवसाय के लिए पेटीएम ने यूएई, सऊदी अरब, सिंगापुर, इंडोनेशिया और लक्जमबर्ग में सब्सिडियरी कंपनियां बनाई हैं। कनाडा में 2014 से इसका रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर पेटीएम लैब्स स्थित है। ब्राजील के स्टार्टअप डिनी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यूएई यूनिट में एमार के संस्थापक मोहम्मद अलअब्बार से जुड़ी कंपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी ले रही है।



सबक...
सही समय पर सही समस्या का समाधान उपलब्ध कराने से सफलता का रास्ता मिलता है।

8.5 करोड़ यूजर हैं मासिक लेन-देन वाले कंपनी के पास।

7.1 लाख करोड़ का भुगतान व्यापारियों को हुआ जुलाई-सितंबर में।

1.64 करोड़ साउंड बॉक्स वाले दुकानदार हैं कंपनी के।

13,617 करोड़ रु. की नकदी है कंपनी के पास वर्तमान में।

ऐसे संकट में फंसी कंपनी...

- **पेमेंट्स बैंक में केवाईसी की खामियां :** आरबीआई ने 2018 के ऑडिट में पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कई मामलों में एक पैन से 100 से ज्यादा ग्राहक जुड़े थे। मनी लॉन्ड्रिंग का शक हुआ। नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगी। 2023 में 5.39 करोड़ का जुर्माना लगा।
- **चीनी निवेश से रेगुलेटरी अड़चन :** आईपीओ से पहले चीन का एंट ग्रुप 34.7% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरहोल्डर था। चीनी टैग ने निवेशकों और नियामकों का भरोसा कमजोर किया।
- **महंगा आईपीओ:** कंपनी 2021 में करीब 1.39 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ बाजार में आई। लिस्टिंग के दिन 27% गिरावट ने 38,000 करोड़ डुबो दिए।
- **फाउंडर पर सवाल:** आरोप था कि आईपीओ दस्तावेजों में विजय शेखर को नॉन-प्रमोटर बताया गया, जबकि वित्तवर्ष 2021 के रिटर्न में वे प्रमोटर थे।

इस तरह की वापसी...

- **यूजर्स को बड़े बैंकों पर शिफ्ट किया :** आरबीआई की समय-सीमा (15 मार्च 2024) से पहले ही पेटीएम को थर्ड-पार्टी यूपीआई ऐप के रूप में मंजूरी मिली। एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई व यस बैंक नए पार्टनर बने। सेवाएं बंद होने से बचीं।
- **एंट ग्रुप से दूरी:** 2023-25 के बीच चीन के एंट ग्रुप ने पेटीएम में पूरी हिस्सेदारी बेच दी। चीनी टैग हटते ही निवेश के रास्ते खुले। अगस्त 2025 में आरबीआई ने पेटीएम की पेमेंट सर्विस को एग्रीगेटर की मंजूरी दी।
- **खर्च पर कैंची:** 2024 में मूवी टिकटिंग कारोबार जोमैटो को करीब 2,048 करोड़ रु. में बेचा। कर्मचारियों पर होने वाला करोड़ों का खर्च घटाया।
- **सेबी से सेटलमेंट :** अप्रैल 2025 में विजय शेखर शर्मा ने कर्मचारी स्टॉप ऑप्शन स्कीम के 2.1 करोड़ शेयर छोड़ दिए। 1.1 करोड़ जुर्माना भी दिया।

शुरुआत : अलीगढ़ में शिक्षक के घर जन्मे विजय शेखर ने रखी नींव

अलीगढ़ में शिक्षक के घर जन्मे विजय शेखर शर्मा ने सन 2000 में 8 लाख का कर्ज लेकर वन-97 कम्युनिकेशंस बनाई, जो मोबाइल पर कंटेंट और वैल्यू-एडेड सर्विस देती थी। इसके बाद अगस्त 2010 में नोएडा से 20 लाख डॉलर के शुरुआती निवेश के साथ उन्होंने पेटीएम प्रीपेड मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म शुरू किया।

नए कदम : एआई एजेंट व एआई ढांचा विकसित कर रही है कंपनी

पेटीएम कारोबार को बढ़ाने के लिए एआई एजेंट और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। इसकी मदद से कारोबारियों को मार्केटिंग करने, विज्ञापन बनाने और संभावित ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने में मदद की जा रही है। पीआई इंटरफाइज एआई प्लेटफॉर्म की मदद से कंपनियों को एआई मॉडल चलाने, एआई एजेंट बनाने की भी जानकारी दी जाती है।

ऐसे पड़ा नाम : पेटीएम का पूरा नाम है 'Pay Through Mobile' यानी मोबाइल से भुगतान। नाम ही बताता है कि कंपनी का मिशन था मोबाइल से पेमेंट।

बड़े प्रतिद्वंद्वी : यूपीआई बाजार हिस्सेदारी के मामले में सितंबर 2026 में फोनपे का हिस्सा 45.57%, गूगल-पे का 32.23% और पेटीएम का 8.1% रहा।

पीपुल भास्कर | नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन

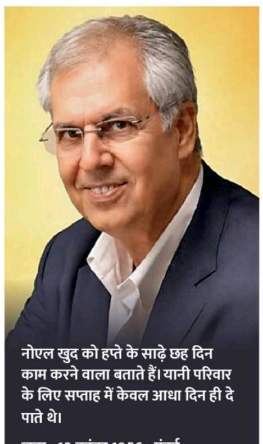
खुद को साढ़े छह दिन काम करने वाला कहते हैं, तेज कार चलाने के शौकीन हैं नोएल टाटा

टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा अपनी सादगी के लिए मशहूर हैं। एक इंटरव्यू में नोएल बताते हैं कि चकाचौंध से दूर रहना उनका स्वभाव हर है। उन्हें अपने काम को लेकर जुनून है। वे महंगे सूट, ब्लेजर और टाई पहनने से बचते हैं। आधी बांह की कमीज में वे खुद को सहज महसूस करते हैं। दफ्तर के दौरों पर वे कंपनी के गेस्ट हाउस में रुकते थे।

एक साक्षात्कार में वे बताते हैं कि जब भी उन्हें कभी नासिक या पुणे के किसी स्टोर का निरीक्षण करने जाना होता था तो वे रविवार का दिन चुनते थे। यह उनके लिए सबसे अनुकूल होता था। उनके बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि वे सड़क पर चलते हुए भी आइडिया डेवलप कर सकते हैं। एक साक्षात्कार में नोएल टाटा बताते हैं कि छुट्टियों के दिनों में भी जब वे कहीं बाहर जाते और टहलते हुए उन्हें कोई दुकानदार अलग तरह से दुकान चलाता हुआ दिख जाता तो सोचने लगते थे कि इस तरह हम भी बिजनेस को बड़े स्तर पर शुरू कर सकते हैं। और उस आइडिया को लागू करने में जुट जाते थे।

उन्हें पढ़ने का बेहद शौक है। वे आज भी नई-नई किताबें पढ़ते हैं ताकि कुछ नया सीख सकें। उन्हें तेज रफ्तार वाली गाड़ियां चलाने का भी शौक है। काफी लंबे समय तक अक्सर उन्हें मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए देखा गया। कंपनी की टाटा सफारी वे खुद ड्राइव करते थे। नोएल टाटा ने एक साक्षात्कार में बताया कि उन पर पिता नवल टाटा का काफी असर है। नोएल कहते हैं कि उन्होंने बताया कि लोगों तक कैसे पहुंचे।

चर्चा में क्यों : 12 नवंबर को 70 साल के होने पर टाटा समूह की रिटायरमेंट नीति के तहत छह कंपनियों के बोर्ड से हट रहे हैं।



नोएल खुद को हफ्ते के साढ़े छह दिन काम करने वाला बताते हैं। यानी परिवार के लिए सप्ताह में केवल आधा दिन ही दे पाते थे।

जन्म : 12 नवंबर 1956 , मुंबई

शिक्षा : ससेक्स यूनिवर्सिटी, यूके से ग्रेजुएशन की डिग्री

परिवार : पत्नी- आलू मिस्त्री, तीन बच्चे, बेटा- नेविल टाटा, बेटियां- लिया व माया टाटा।

संपत्ति- करीब 38 हजार करोड़ रु.
(विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार)

• परिवार

लैक्मे की चेयरपर्सन रहीं मां सिमोन

नोएल का जन्म मुंबई में नवल और सिमोन टाटा के घर हुआ था। सिमोन नवल टाटा की दूसरी पत्नी और रतन टाटा की सौतेली मां थीं। जेनेवा में जन्मी सिमोन 1953 में ट्रेस्ट के तौर पर भारत भ्रमण पर आई थीं, यहीं उनकी मुलाकात नवल टाटा से हुई। दोनों ने 1955 में शादी कर ली। वे लैक्मे की चेयरपर्सन रहीं।

• विवाह

पत्नी आयरलैंड के सबसे अमीर शख्स की बेटी हैं

नोएल ने शापूरजी पालोनजी समूह के मुखिया पालोनजी मिस्त्री की बेटी आलू मिस्त्री से शादी की है। पालोनजी ने डबलिन में जन्मीं पैट्रसी पेरिन दुबाश से शादी की थी। उन्होंने 2003 में आयरिश नागरिकता ले ली थी। पलोन जी मृत्यु के समय आयरलैंड के सबसे अमीर व्यक्ति थे।

• कॅरिअर

मैनेजमेंट ट्रेनी से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन तक

उन्होंने टाटा ग्रुप की विदेशी कारोबारी शाखा टाटा इंटरनेशनल से मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में करियर शुरू किया। ग्रुप की रिटेल शाखा ट्रेंट के 1999 में एमडी बने। 2003 में टाइटन और वोल्टास के डायरेक्टर बनाए गए। 2010 में टाटा इंटरनेशनल के एमडी बने। 2019 में सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी और 2024 में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने, जो टाटा संस के करीब 66% हिस्से का मालिक है।

रोचक : फरटिदार फ्रेंच भी बोल लेते हैं नोएल टाटा

- हिंदी, अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच भी फरटिदार बोल लेते हैं नोएल टाटा।
- इनके पास आयरलैंड की भी नागरिकता है।
- इनके पिता नवल टाटा अनाथालय में पढ़ते थे। 13 साल की उम्र में लेडी रतन टाटा (नवाजबाई) ने उन्हें गोद लिया था।

उपलब्धि : इनके कार्यकाल में 4000% तक बढ़े ट्रेंट के शेयर

- नोएल ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन रहे हैं। ट्रेंट जुडियो और वेस्टसाइड की ओनर है। उनकी लीडरशिप में पिछले 10 साल में कंपनी के शेयर 4000% तक बढ़े।
- ट्रेंट ने स्पेन की इंडिटेक्स के साथ जारा व मासिमो दुत्ती को भारत लाने वाला वेंचर चलाया।

विवाद भी: टाटा ट्रस्ट में फूट, चेयरमैन से टकराव दिखा

- 2025 में टाटा ट्रस्ट्स के भीतर विजय सिंह की टाटा संस बोर्ड में पुनर्नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ। नोएल टाटा ने समर्थन किया, वहीं मेहली मिस्त्री सहित कुछ ट्रस्टियों ने विरोध किया।
- अक्टूबर 2026 को नोएल ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को चुनौती दी है।

बिज़नेस भास्कर

Business Standard और TheEconomist की खबरों के साथ

नई दिल्ली, शुक्रवार 30 अक्टूबर, 2026

बिजनेस ब्रीफ

माइक्रोसॉफ्ट का मुनाफा 32% बढ़ा, आय 19%

न्यूयॉर्क | जुलाई-सितंबर तिमाही में माइक्रोसॉफ्ट का मुनाफा सालाना 32% बढ़कर 36.6 अरब डॉलर (₹3.48 लाख करोड़) हो गया। आय भी 19% बढ़कर 92.3 अरब डॉलर (₹8.78 लाख करोड़) हो गई। एआई और क्लाउड बिजनेस से कंपनी को मजबूती मिली। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की आय 30% बढ़ी जबकि एज्योर की आय में 48% बढ़ोतरी हुई।

अमीरों के बीच औसत टर्म इंश्योरेंस कवर 30% बढ़ा

नई दिल्ली| देश में अमीर तबके के बीच टर्म इंश्योरेंस की मांग बढ़ रही है। पॉलिसीबाजार के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2023 के बाद ऐसे ग्राहकों की बुकिंग दोगुनी हो गई, जबकि औसत बीमा कवर 30% बढ़ा है। करीब 50% ग्राहक 35 साल से कम उम्र के हैं। ₹3 करोड़ या उससे अधिक के कवर 25% बढ़े। 5% ग्राहक 5 करोड़ या अधिक का कवर चुन रहे हैं।

रिलायंस ब्रिटेन में हैमलीज फ्रेंचाइजिंग बंद कर रही

मुंबई|रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में अपनी सहायक कंपनी हैमलीज (फ्रेंचाइजिंग) लिमिटेड को स्वेच्छा से बंद करने जा रही है। ब्रिटेन के कंपनी रजिस्ट्रार ने 27 अक्टूबर को इसे रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कम से कम दो महीने बाद कंपनी को भंग किया जा सकता है। 2025 में कंपनी का कारोबार सिर्फ ₹56 करोड़ का रहा था।

फोक्सवैगन को 61,886 करोड़ रुपए का घाटा

बर्लिन| जर्मन कार कंपनी फोक्सवैगन को सितंबर तिमाही में 6.5 अरब डॉलर (₹61,886 करोड़) का शुद्ध घाटा हुआ। चीन में कमजोर मांग, अमेरिकी टैरिफ और इलेक्ट्रिक कारों से कम मुनाफा इसकी वजह रही। पोर्शे में हिस्सेदारी की वैल्यू घटने से 6.4 अरब यूरो (₹67,802 करोड़) का असर पड़ा। आय 6.3% घटकर 80.3 अरब यूरो रह गई।

अमेरिका की विकास दर बढ़कर 3.4% हुई

वॉशिंगटन| सितंबर तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 3.4% बढ़ी, जबकि अर्थशास्त्रियों ने 3.2% वृद्धि का अनुमान लगाया था। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता खर्च और एआई से जुड़ा निवेश बढ़ना इसके प्रमुख कारण रहे। उपभोक्ता खर्च 3.8% बढ़ा। मध्य-पूर्व संघर्ष के कारण तेल महंगा होने के बावजूद अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज रही।

ट्रिगर • महंगाई के बावजूद अमेरिका में ब्याज दरें नहीं बढ़ने से बाजार में तेज रिकवरी

बाजार 7 में से 6 दिन गिरने के बाद संभला, सेंसेक्स में 905 अंकों की तेजी

भास्कर न्यूज | मुंबई

अमेरिका में ब्याज दरें न बढ़ने से घरेलू बाजार को सहारा मिला। पिछले सात में से छह सत्रों की गिरावट के बाद गुरुवार को सेंसेक्स 905 अंक की उछाल के साथ 74,151 पर और निफ्टी 238 अंक चढ़कर 22,937 पर बंद हुआ। दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में 1% से ज्यादा तेजी रही।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड ने कहा कि महंगाई अब भी ऊंची है, इसलिए दरों पर फैसला अगले हफ्ते अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद होगा। ऊंची ब्याज दरें डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में निवेश को आकर्षक बनाती हैं। ऐसे भारत जैसे उभरते बाजारों से विदेशी निवेशक दूरी बनाते हैं। ब्याज दरें न बढ़ने से यह ट्रेंड पलट गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.88% चढ़कर ₹1,168.75 पर रही। एक दिन पहले लिस्ट हुआ जियो प्लेटफॉर्म्स 0.40% तेजी के साथ ₹1,423 रुपए पर बंद हुआ। अदाणी पोर्ट्स का सितंबर तिमाही का मुनाफा 18% बढ़कर ₹3,682 करोड़ पर पहुंचने से उसके शेयर भी 5% उछाल के साथ ₹1,850 पर बंद हुए।

व्यापक मजबूती
बीएसई के 27 सेक्टोरल इंडेक्स में से 26 में तेजी



टॉप-10 इंडेक्स	तेजी
यूटिलिटीज	3.11%
रियल्टी	2.44%
एफएमसीजी	1.94%
सर्विसेज	1.77%
पावर	1.63%
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स	1.55%
टेलीकम्युनिकेशन	1.30%
फाइनेंशियल सर्विसेज	1.19%
बैंकेक्स	1.17%
हाउसिंग फाइनेंस	1.01%

सिर्फ ऑटो इंडेक्स में 0.18% गिरावट आई

रिस्क: विदेशी निवेशक अब भी शेयर बेच रहे

भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बुधवार को 872 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की थी। लेकिन गुरुवार को इन्होंने 843 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक बुधवार को 643 करोड़ रुपए की और गुरुवार को 1,924 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इससे पहले भी विदेशी निवेशक अक्टूबर में अब तक करीब ₹35,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके थे। टिकाऊ तेजी के लिए उनकी वापसी अहम है।

बड़े फैक्टर: कच्चे तेल के दाम 1% घटे, रुपया स्थिर

- **कच्चा तेल**: ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 1% घटकर 114 डॉलर प्रति बैरल पर रह गई, फिर भी यह सामान्य स्तर से करीब 40% ऊपर है।
- **रुपया**: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग स्थिर रहा। इसकी विनिमय दर 3 पैसे बढ़कर 95.25 प्रति डॉलर रही।
- **डर कम**: उतार-चढ़ाव का इंडेक्स इंडिया विक्स 5.18% गिर गया।

निफ्टी 22,830 से ऊपर टिके तो बाजार चढ़ सकता है

स्तर	मतलब
22,830 के ऊपर टिकना	23,000-23,175 तक चढ़ने का रास्ता खुलेगा
22,750-22,800	कोटक निज़ी के मुताबिक, ये बड़ा सपोर्ट है
22,650 से नीचे	इससे नीचे आना मंदी की वापसी का संकेत होगा

रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिकवरी, जियो के शेयर स्थिर

रिलायंस के शेयर में 1% तेजी बड़ी रिकवरी है। एक दिन पहले ही बुधवार को यह शेयर 3.19% टूटा था। सेंसेक्स में ज्यादा वेटेज के कारण इसकी तेजी बाजार के लिए अहम रही। दूसरी तरफ जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर 1,423 रुपए पर लगभग स्थिर रहे। अदाणी एंटरप्राइजेज, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी बाजार की तेजी में साथ दिया।



बाजार ने 110 डॉलर से ऊपर के कच्चे तेल को नजरअंदाज किया। कमजोर वैश्विक संकेतों से उतार-चढ़ाव रहेगा, घरेलू फंडामेंटल्स मजबूत हैं। - **सनी अग्रवाल,** हेड-फंडामेंटल रिसर्च, एसबीआई सिक्योरिटीज



फेड का दरें स्थिर रखना हल्का सकारात्मक है, लेकिन अमेरिकी बॉन्ड से कमाई और महंगा तेल भारत के लिए चुनौतियां बनी हैं। - **वीके विजयकुमार,** मुख्य निवेश रणनीतिकार, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स



निफ्टी 22,800 की बाधा अब पार कर चुका है। लेकिन इस बेंचमार्क इंडेक्स के 22,750 से नीचे जाने पर लंबे सौदे वाले ट्रेडर बाहर निकल सकते हैं। - **श्रीकांत चौहान,** हेड-इक्विटी रिसर्च, कोटक निओ

तिमाही नतीजे • प्रति किलोमीटर यात्री कमाई 34% बढ़कर 6.30 रुपए

इंडिगो: टिकट महंगे करके आय 26% बढ़ाई, फिर भी 1,879 करोड़ का घाटा

भास्कर न्यूज | मुंबई

ईंधन पर खर्च बढ़ने के बीच कमजोर रुपए ने इंडिगो (इंटरग्लोब एविएशन) की कमाई पर गहरा असर डाला। टिकट महंगे करने से जुलाई-सितंबर तिमाही में आय तो 26% बढ़कर ₹23,364 करोड़ हो गई, पर कंपनी को ₹1,879 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा उठाना पड़ा।

एयरलाइन ने प्रति किलोमीटर यात्री कमाई 34% बढ़ाकर 6.30 रुपए कर ली। लेकिन यात्री 4.7% घटकर 2.75 करोड़ रह गए और सीटें भरने की दर (लोड फैक्टर) 80.3% ही रही। हालांकि घाटा पिछले साल की समान तिमाही के ₹2,582 करोड़ से कम है, पर जून तिमाही के ₹237 करोड़ से काफी ज्यादा है।

इंडिगो के सीईओ विली वॉल्श ने कहा कि सितंबर की सुस्त तिमाही में ईंधन खर्च बहुत ऊंचा रहा और भू-राजनीतिक उथल-पुथल भी रही। इस बीच कंपनी ने क्षमता घटाई और कमाई बढ़ाई, लेकिन इससे बढ़ी लागत की आंशिक भरपाई ही हो सकी।

जुलाई-सितंबर में ईंधन खर्च 67% बढ़ा, अब कंपनी की कुल लागत में इसकी हिस्सेदारी 27% से 38%

तिमाही	जुलाई-सितंबर-25	जुलाई-सितंबर-26
ईंधन खर्च	₹5,962 करोड़	₹9,967 करोड़
कुल खर्च	₹22,081 करोड़	₹26,188 करोड़
लागत में हिस्सा	₹27%	₹38%

घाटे में रुपए की कमजोरी का असर ₹1,155 करोड़

सितंबर तिमाही के लिए इंडिगो के बही-खाते पर नजर डालें तो इसमें रुपए की कमजोरी का असर साफ दिखा। कंपनी के कुल घाटे में इसका असर 1,155 करोड़ रुपए रहा। यदि यह असर हटा दें तो घाटा 724 करोड़ रुपए रह जाएगा, जबकि पिछले साल 104 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था।

सीटें कम हुईं, पर प्रति सीट कमाई 26% बढ़ी

- क्षमता 1% घटकर 40.8 अरब सीट-किलोमीटर रही।
- प्रति सीट-किलोमीटर आय 26.4% बढ़कर 5.76 रुपए।
- टिकट से आय 2% बढ़कर ₹23,364 करोड़ हो गई।
- अन्य सेवाओं से आय 15.9% बढ़कर ₹2,481 करोड़।

बड़ा सपोर्ट • कंपनी के पास ₹52,685 करोड़

इंडिगो के पास ₹52,685 करोड़ कैश है। इसमें ₹39,929 करोड़ फ्री कैश है। कुल कर्ज ₹87,303 करोड़ है। फ्लीट में 442 विमान हैं, बीती तिमाही 10 बढ़े। समय पर फ्लाइट की आवाजाही 91.3% रही।

इंटरग्लोब एविएशन: जुलाई-सितंबर तिमाही का रिजल्ट (कन्सॉलिडेटेड) एक नजर में

मापदंड	Q2 FY27	Q2 FY26	अंतर
ऑपरेटिंग रेवेन्यू	23,364	18,555	25.9 %
टैक्स पूर्व लाभ	▼1,877	▼2,482	▼24.4 %
ऑपरेटिंग मार्जिन	12.22%	8.75%	3.47pp
टैक्स बाद लाभ	▼1,879	▼2,582	▼27.2 %

(आंकड़े करोड़ रुपए में, pp = पर्सेंटेज पॉइंट्स) स्रोत: कंपनी फाइलिंग

IndiGo इंटरग्लोब एविएशन का मार्केट कैप 30 सितंबर 2026 तक 1.93 लाख करोड़ रुपए था।

यहां पड़ी ज्यादा चोट...

एबिटा (ब्याज, टैक्स, विमान किराए से पहले की कमाई) विदेशी मुद्रा (रुपए में कमजोरी) के असर के बिना 3,800 करोड़ से घटकर 3,615 करोड़ रुपए रही। इसका मार्जिन 20.5% से गिरकर 15.5% रह गया। इसका असर कंपनी के पूरे बही-खाते पर साफ नजर आया।

अनुमान • नई नौकरियां नहीं बढ़ेंगी: बीसीजी

एआई से 2030 तक 19 लाख करोड़ के नए मौकों के आसार

बिज़नेस संवाददाता | मुंबई

एआई आधारित सेवाओं से 2030 तक ₹9.5 से 19 लाख करोड़ के नए काम पैदा हो सकते हैं। लेकिन इससे टेक कंपनियों में नई भर्तियां नहीं बढ़ेंगी। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म बीसीजी की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियां मौजूदा कर्मचारियों को ही नई तकनीक की ट्रेनिंग देकर मांग पूरी कर सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल सर्विस मार्केट 2025 में ₹152-162 लाख करोड़ का था। यह 2030 तक ₹210-229 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसमें एआई का योगदान ₹28.6-38 लाख करोड़ होगा।

चुनौती • एआई विशेषज्ञ हैं, पर इनकी रीस्किलिंग जरूरी

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनौती एआई जानने वाले लोगों की कमी नहीं, बल्कि मौजूदा कर्मचारियों को सही भूमिका में तैयार करने की है। पारंपरिक टेक कंपनियों में एआई से जुड़े कर्मचारियों में केवल 10-15% ही एआई समाधान लागू करने, चलाने और संभालने में विशेषज्ञ हैं। एआई आधारित कंपनियों में ऐसे पेशेवरों की हिस्सेदारी 90-95% है। बीसीजी ने मौजूदा पदों से 40 तरह की एआई भूमिकाएं विकसित करने की पहचान की है।

खुलासा • ट्रम्प को जानकारी दी गई, कार्रवाई नहीं हुई

चीनी जासूसी के निशाने पर एनवीडिया के हुआंग: रिपोर्ट

जोनाथन स्वान | न्यूयॉर्क

एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग के संपर्क में रही चीनी कारोबारी एलिस हुआंग पर बीजिंग को खुफिया जानकारी देने का आरोप सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की निगरानी में यह बात सामने आई।



एलिस सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड में वरिष्ठ अधिकारी रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों को पहले से संदेह था कि वह प्रतिबंधों से बचकर एनवीडिया की एडवांस एआई चिप चीन पहुंचाने में मदद कर रही थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की करीब सालभर पहले जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। जेन्सेन को भी संभावित जासूसी खतरे की औपचारिक चेतावनी नहीं दी गई। चीन ने आरोपों को निराधार बताया। हालांकि, एलिस ने कौन-सी जानकारी भेजी, यह स्पष्ट नहीं है। शुरुआती अमेरिकी आकलन में जेन्सेन को उनकी कथित भूमिका की जानकारी नहीं थी।

एनवीडिया का जवाब- गोपनीय जानकारी साझा नहीं की: कंपनी ने कहा कि ग्राहकों से मिलना सीईओ के काम का हिस्सा है।

एलआरएस स्कीम

विदेश भेजने की रकम 5 साल में 2.28 गुना हुई

बिज़नेस संवाददाता | नई दिल्ली

विदेश में निवेश, यात्रा और पढ़ाई पर खर्च के लिए भारतीयों की ओर से भेजी जाने वाली रकम लगातार बढ़ी है। रिजर्व बैंक की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीयों ने कुल 28.98 अरब डॉलर (₹2.76 लाख करोड़ रुपए) विदेश भेजे। यह रकम वित्त वर्ष 2020-21 के 12.68 अरब डॉलर (₹1.21 लाख करोड़) से 2.28 गुना है। वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे बड़ा हिस्सा विदेश यात्रा और ट्रांस्पर्ट पर खर्च हुआ, जिसके लिए 16.44 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा उपयोग की गई।विदेश में रहने वाले करीबियों-रिश्तेदारों के रखरखाव पर 3.54 अरब डॉलर बाहर भेजे गए।

चीन में समुद्र तल से 93 मीटर नीचे दुनिया की सबसे लंबी रेल टनल 2028 तक होगी तैयार; ₹31,400 करोड़ खर्च



प्रोजेक्ट एक नजर में | डायमीटर: 14.57 मीटर लंबाई: 135 मीटर वज़न: 4,000 टन से अधिक

बीजिंग | चीन के झेजियांग में समुद्र तल से 93 मीटर नीचे 16.18 किमी लंबी जिनतांग टनल की खुदाई का काम चल रहा है। इसके लिए स्वदेशी 'योंगझोऊ' टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया की सबसे लंबी इस अंडरसी हाई-स्पीड रेल टनल का निर्माण 77 किलोमीटर लंबे 'योंगझोऊ रेलवे प्रोजेक्ट' का हिस्सा है। इसके निर्माण पर 31,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट अथॉरिटी के मुताबिक, 2028 तक पूरी रेलवे लाइन को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हाई-स्पीड रेल लाइन के शुरू होने से निंगबो से झोउशान शहर का सफर 90 मिनट से घटकर महज 26 मिनट रह जाएगा।

सर्विस सेक्टर 19 में से 13 क्षेत्र 10% से ज्यादा बढ़े

हिमांशी भारद्वाज | नई दिल्ली

अगस्त 2026 में देश के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बढ़कर 14 फीसदी पहुंच गई। जुलाई में यह 13.5% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 19 में से 13 प्रमुख क्षेत्रों में 10% से अधिक की मजबूत ग्रोथ देखी गई। रिटेल व्यापार 19.9% की सर्वाधिक बढ़त के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद रियल एस्टेट और रिपेयर सर्विसेज दोनों में 17.6% की समान वृद्धि दर्ज हुई। बीमा क्षेत्र में 16.5% तथा बैंकिंग में 14.9% की उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई। कूरियर सेवाओं में 13.2% और गोदाम कारोबार में 11.2% का उछाल आया। ईवाई इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर डीके श्रीवास्तव के अनुसार जून से अगस्त के बीच औसतन 13.6% की यह तेजी देश की आगामी जीडीपी ग्रोथ को मजबूत सहारा देगी।

ट्रेंट: दिवालिया कानून से जुड़े बहराम होंगे चेयरमैन

बिज़नेस संवाददाता | मुंबई

टाटा समूह की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड में नेतृत्व बदलने जा रहा है। कंपनी ने बहराम वकील को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वे 12 नवंबर, 2026 से यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा चेयरमैन नोएल टाटा 11 नवंबर को रिटायर होने के बाद चेयरमैन एमेरिटस होंगे। बहराम वकील देश के शीर्ष वकीलों में गिने जाते हैं। वे प्रमुख लॉ फर्म एजेडबी एंड पार्टनर्स के सह-संस्थापक हैं। बहराम वकील को दिवाला, पुनर्गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट फाइनेंस मामलों का विशेष जानकार माना जाता है। उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री हासिल की है।



पार्टनरशिप • अदाणी और टाटा समूह साथ आए

अदाणी बनाएंगे, टाटा ऑपरेट करेगी 4 शहरों में 8 होटल

भास्कर न्यूज | मुंबई

हवाई अड्डों के आसपास होटल बिजनेस बढ़ाने के लिए अदाणी एयरपोर्ट्स और टाटा समूह की इंडियन होटल्स (ताज ग्रुप) साथ आई हैं। दोनों मिलकर मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी में 2,000 से ज्यादा कमरों वाले 8 होटल बनाएंगी।

करार के तहत होटलों का निर्माण अदाणी एयरपोर्ट्स करेगी, जबकि इन्हें चलाने का जिम्मा ताज ग्रुप का होगा। यानी निर्माण अदाणी का और ब्रांड-संचालन टाटा समूह का। कुल 8 में से 3 ताज, दो विवांता, एक गेटवे और दो जिंजर ब्रांड के होटल होंगे। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर ताज होटल बनेगा। अदाणी की योजना हवाई अड्डों को सिर्फ उड़ान तक सीमित न रखकर होटल, बिजनेस, रिटेल और मनोरंजन वाली 'एयरपोर्ट सिटी' बनाने की है। इस करार के बाद इंडियन होटल्स के प्रमुख हवाई अड्डों पर होटलों की संख्या 25 हो जाएगी।

भास्कर नॉलेज

किस शहर में कौन से ब्रांड के होटल बनाए जाएंगे

शहर	होटल
मुंबई	ताज (टर्मिनल-2)
अहमदाबाद	ताज, विवांता
लखनऊ	विवांता, जिंजर
गुवाहाटी	ताज, गेटवे, जिंजर

मेहमानों को क्या मिलेगा | ठहरने के साथ रेस्तरां, मीटिंग और इवेंट स्पेस, वेलनेस और मनोरंजन की सुविधाएं।

अदाणी का प्लान: 20 हजार करोड़ का निवेश

- अदाणी एयरपोर्ट्स ने 'अदाणी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड' बनाई है। इसके पास 7 राज्यों के 8 हवाई अड्डों पर 655 एकड़ से ज्यादा जमीन है। इसमें करीब 440 एकड़ मुंबई और नवी मुंबई में है।
- पहले चरण में मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में 2.2 करोड़ वर्ग फुट में निर्माण होगा। अदाणी एयरपोर्ट्स अपने हवाई अड्डों पर कुल 15 प्रॉपर्टीज के लिए होटल ब्रांड्स से करार कर चुकी है।

एयरपोर्ट के पास बिजनेस, और पर्यटन पर फोकस

दुनिया भर में बड़े हवाई अड्डे बिजनेस, पर्यटन और शहरी विकास के केंद्र बन रहे हैं। ताज ग्रुप के साथ साझेदारी से एयरपोर्ट सिटी में होटल सुविधाएं मजबूत होंगी।
- जीत अदाणी, डायरेक्टर, अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स

एयरपोर्ट के आसपास के प्रोजेक्ट अब अहम बिजनेस और होटल केंद्र बन रहे हैं। यह साझेदारी देश के ट्रैवल और ट्रांस्पर्ट सेक्टर को बढ़ाने की साझा सोच का नतीजा है।
- पुनीत छत्वाल, एमडी-सीईओ, इंडियन होटल्स

बिजनेस एंकर

कीमत 1,40,000 रुपए के करीब आने पर नई तेजी की शुरुआत हो सकती है: कोटक

धनतेरस से पहले राहत: फेड ने दरें स्थिर रखीं, इसके चलते आगामी हफ्तों में सोने की कीमत में भारी उछाल या गिरावट की आशंका कम

भास्कर न्यूज | मुंबई

ज्वेलर्स और शादियों के सीजन में सोना खरीदने वालों को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के फैसले से थोड़ी राहत मिली है। फेड ने बुधवार को ब्याज दरें 3.75% से 4% के दायरे में स्थिर रखीं। जानकारों के मुताबिक आने वाले हफ्तों में सोने के दाम एक दायरे में रह सकते हैं, यानी न बड़ा उछाल, न भारी गिरावट।

कोटक नेओ में करेंसी और कमोडिटी रिसर्च के प्रमुख अनिंद्य बनर्जी कहते हैं कि यह ठहराव स्थिरता तो दे सकता है, पर इसे नई तेजी की शुरुआत नहीं समझना चाहिए। एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सोना 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे दबाव में है। बनर्जी के मुताबिक भाव 1,40,000 रुपए के करीब आएं तो घरेलू खरीदारों को मौका मिल सकता है। असली पेच दिसंबर की ब्याज दर है। मेटल्स फोकस के रिसर्च कंसल्टेंट आदर्श दिवे के मुताबिक दिसंबर में दरें बढ़ने की संभावना 78% है। ब्याज बढ़ता है तो बॉन्ड जैसे निवेश ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं, जबकि सोना नियमित कमाई नहीं देता। यह आशंका घटी तो सोने को ऊपर जाने की जगह मिल सकती है।

दूसरी ओर बाजार में त्योहारी रौनक लौटी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता के मुताबिक पिछले पांच दिनों में देशभर में अच्छी खरीदारी दिखी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्हें दिसंबर तक दाम दायरे में रहने की उम्मीद है। अमेरिकी चुनाव और फेड की अगली बैठक पर नजर रहेगी। ज्यादा मांग का मतलब दाम बढ़ना नहीं है। मध्य-पूर्व के हालात भी असर डालेंगे। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन केडिया के अनुसार अनिश्चितता से उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और राहत 2027 में मिल सकती है। ईरान से सीधी बातचीत के प्रस्ताव पर प्रगति से तनाव घट सकता है, पर 4 नवंबर के बाद हालात फिर बिगड़ सकते हैं। मंगल केशव फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन परेश भगत के मुताबिक अमेरिकी बॉन्ड यील्ड (सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज) बढ़ने और डॉलर मजबूत होने से सोना रखना महंगा पड़ता है, इसलिए नजदीकी दबाव रह सकता है। लंबी अवधि में केंद्रीय बैंकों की खरीद और सुरक्षित निवेश की मांग सोने को सहारा दे सकती है। यानी शादी-त्योहार की खरीदारी करने वालों को दाम घटने पर मौका मिल सकता है, पर लगातार गिरावट की गारंटी नहीं है। किस्तों में खरीदने से उतार-चढ़ाव वाले दिन पूरी खरीद करने का जोखिम घटता है।

रुपए का गणित • विदेश में सस्ता, पर भारत में राहत कम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,120 डॉलर प्रति औंस से नीचे है। 95.16 रुपए प्रति डॉलर के भाव से यह करीब 1.26 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम* बैठता है (कर-शुल्क जोड़े बिना)। आदर्श दिवे के अनुसार घरेलू सोना अंतरराष्ट्रीय भाव से अब सिर्फ ₹2 डॉलर (₹190 रुपए) प्रति औंस सस्ता है। परेश भगत के मुताबिक रुपया कमजोर हो तो आयात महंगा पड़ता है, इसलिए वैश्विक गिरावट का पूरा फायदा खरीदारों तक नहीं पहुंचता।

कमाई • बीमा से कमीशन घटना तय, नया प्लान

म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स से आय बढ़ाने की तैयारी में बैंक

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

बीमा नियामक इरडा ने इंश्योरेंस कमीशन और बीमा कंपनियों के प्रबंधन खर्च की सीमा घटाने का प्रस्ताव दिया है। इससे बैंकों की कमाई पर असर पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए बैंक अन्य सेवाओं पर शुल्क आय बढ़ाने, ग्राहकों को अधिक म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसियां बेचने, लोन प्रोसेसिंग फीस से कमाई मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। सात बैंक दूसरी सेवाओं से शुल्क आय बढ़ाने, ज्यादा पॉलिसियां बेचने और खर्च घटाने की तैयारी कर रहे हैं।

बंधन बैंक को सालाना 200 करोड़ की संभावित कमी का अनुमान है। वह म्यूचुअल फंड वितरण, थोक बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और ट्रेड फाइनेंस बढ़ाएगा। छोटे शहरों में बीमा बिक्री भी बढ़ाएगा। एक्सिस बैंक ज्यादा पॉलिसियां बेचने और उत्पादों में बदलाव पर विचार कर रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक विदेशी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड और ट्रेड फाइनेंस बढ़ाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विदेशी मुद्रा जमा पर लागत बचत और अन्य आय पर भरोसा कर रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बीमा कमीशन आय 33% घटकर 49 करोड़ रह सकती है, जो अभी 76 करोड़ है। वह अपने बीमा कारोबार और क्रेडिट से जुड़े बीमा उत्पादों पर जोर देगा। केनरा बैंक को जीवन बीमा वितरण आय में सालाना 120-145 करोड़ की कमी का अनुमान है।

सुनील भारती मित्तल को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान

बिज़नेस संवाददाता | नई दिल्ली

फ्रांस सरकार ने भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'शेवेलिए द लॉर्द नास्योनाल द ला लेजिओन दॉनेउर' से नवाजा है। भारत में फ्रांस के राजदूत थिएरी मातू ने नई दिल्ली में उन्हें यह सम्मान सौंपा। फ्रांस सरकार ने दूरसंचार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सैटेलाइट संचार के क्षेत्र में मित्तल के असाधारण योगदान को यह मान्यता दी है। समारोह के दौरान फ्रांसीसी राजदूत ने इंश्योरेंस ग्रुप एएक्सए, अल्काटेल-लूसेंट और यूटेलसैट जैसी फ्रांसीसी कंपनियों के साथ मित्तल की पुरानी कारोबारी साझेदारियों की सराहना की।



Last day to join the Free Newspapers Community

At just one time entry fee of ₹19... It's worth it 🙏

EDITORIALS PDF

- **English Editorials PDF**
  with International Newspapers Editorials [35–40 pages]
- **Hindi Editorials PDF**
- **Daily Vocabulary PDF**

MAGAZINE CHANNEL

National & International
[General & Exam related]

INTERNATIONAL NEWSPAPERS

Newspapers around the world.
Asian, European & American

INDIAN NEWSPAPERS CHANNEL

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. Business Line
4. Financial Express
5. Times of India
6. Hindustan Times
7. Economic Times
8. Live Mint
9. Business Standard

HINDI NEWSPAPERS (Delhi Editions)

1. दैनिक जागरण
2. जनसत्ता
3. हरिभूमि
4. हिंदुस्तान
5. लोकमत
6. लोकसत्ता
7. दैनिक भास्कर

CLICK HERE ▼

Tap the button above to get free access